हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2001

(द्वितीय बैठक)

खण्ड-1, अंक-10

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 14 मार्च, 2001

	पृष्ट संख्या
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	1
वर्ष 2001-2002 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	1
तथाकथित विशेषाधिकार का भंग करना	8
वर्ष 2001-2002 के बजट अनुदानो की मांगो पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	11
व्यैक्तिक स्पष्टीकरण	13
चौधरी बंसी लाल एम0 एल0 ए0 द्वारा	13
वर्ष 2001-2002 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	14
वाक आउट	55

मूल्य : 38

वर्ष 2001-2002 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	56
राज्यपाल का सन्देश	57
वर्ष 2001-2002 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	58
बैठक का समय बढ़ाना	63
वर्ष 2001-2002 के बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	63

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 मार्च, 2001 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान अब प्रश्न होंगे।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था। मेरा एडजर्नमेंट देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठिये, यह क्वैश्चन आवर है। क्वैश्चन आवर के बाद आप अपनी बात कह लेना।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, क्वैश्चन आवर इतना इम्पोर्टैंट नहीं जितना मेरा एडजर्नमेंट मोशन है क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठ जायें, क्वैश्चन आवर के बाद आप अपनी बात कह लेना।

Acquisition of Land

*529. **Shri Nafe Singh Rathi :** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a notification for acquiring the land of village Sankhol, Distt. Jhajjar for the construction of Auto-Market was issued during the year 1994-95;

(b) if, the reply to part(a) be in affirmative, whether the aforesaid land has been acquired, if not, the reasons thereof ;

(c) whether any un-authorised colony has been carved out/developed with the connivance of some property dealers on the said land ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to conduct an enquiry for not acquiring the land referred to in part(a) above so far togetherwith the action to be taken against the persons found guilty for the purpose ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) :

(ए) जी हां, श्रीमान।

(बी) श्रीमान जी, नहीं। क्योंकि यह भूमि सामान्यतः अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों के गरीब वर्ग के परिवारों इत्यादि से सम्बन्धित है। इसलिए उस समय के माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा उपरोक्त उद्देश्य के लिए भूमि को अधिग्रहण न करने के लिए आदेश दिये थे।

(सी) इस भूमि पर कुछ भूमि स्वामियों द्वारा एक अवैध कॉलोनी का विकास शुरु किया हुआ है।

(डी) जी नहीं, श्रीमान।

श्री नफे सिंह राठी : स्पीकर साहब, वर्ष 1994-95 में बहादुरगढ़ में एक ऑटो मार्किट बनाने के लिए दफा 4 के नोटिस जारी हो चुके थे। इस ऑटो मार्किट बनाये जाने के लिए तकरीबन 22 एकड़ जमीन भी एक्वायर कर ली गई थी। उस वक्त श्री भजन लाल की सरकार थी। उस वक्त इनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से कुछ प्रौपर्टी डीलर्ज़ मिल लिए और उन्होंने किसानों को डरा धमका कर जो नोटिस दफा 4-6 के हो चुके थे उसके बाद भी उनकी जमीन वापस रिलीज करवा दी। उसका बहाना यह बताया गया कि इस जमीन में कुछ गरीब हरिजनों की जमीन थी जिसमें उनके मकान बने हुए थे। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर किसी हरिजन का मकान आज तक नहीं बना हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस झूठी रिपोर्ट पर यह जमीन वापस रिलीज़ की गई क्या उन संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त के मुख्यमंत्री को 9-4-92 को बहादुरगढ़ की ऑटो मार्किट एसोसिएयशन की तरफ से 200 व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवा कर एक ज्ञापन दिया गया था कि बहादुरगढ़ में इस वक्त जो ऑटो वर्क्स काम कर रही है वह नेशनल हाई वे पर होने की वजह से वहां पर गाड़ियां आदि खड़ी करने में काफी दिक्कत आ रही है इसलिए हमारे लिए नेशनल हाईवे से हटकर ऑटो मार्किट के लिए जमीन दी जाये। इसके बाद 21.11 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दफा 4 के नोटिस 26-10-94 को जारी हुए और दफा 6 के नोटिस 25-10-95 को जारी हुए। लेकिन बाद में चन्द्रभान व रामकिशन आदि ने एक प्रतिवेदन सरकार को दिया कि इसमें किसानों की और गरीब हरिजनों की व पिछड़े वर्ग के कुछ गरीब लोगों की जमीन भी है इसलिए यह जमीन वापस की जाये यानि प्रस्तावित ऑटो मार्किट से मुक्त की जाये क्योंकि यह उनकी कृषि योग्य भूमि है और उनकी जीविका का केवल एक मात्र साधन है। इसके बाद रोहतक के डी० सी० ने 15-6-1996 को भूमि रिलीज़ करने की सिफारिश की और उसी के आधार पर अधिग्रहण की गई भूमि को रिलीज़ किया गया। स्पीकर सर, जहां तक कार्यवाही करने की बात है, इस अवैध निर्माण में सैक्शन 7.1 औफ अर्बन एक्ट 1975 के तहत 8 एफ० आई० आर० पुलिस में दर्ज करवाई थी जिसमें तीन केसों की इन्क्वायरी हुई है जिसमें से एक को तो रद्द कर दिया गया है और दो पर अभी जांच चल रही है। कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका, बहादुरगढ़ को निर्देश दिये गये हैं कि इस अवैध कॉलोनी के नक्शे स्वीकार न किये जाएं।

डा0 रघुवीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि यह जो लैण्ड एक्वायर की जा रही है इसके कारण वहां के किसानों में बड़ा जबरदस्त रोष है। हमारे माननीय साथी श्री नफे सिंह राठी को भी इस बात का पता है। मैं अपने माननीय साथी मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब जो लैण्ड एक्वायर की जा रही है वह किस रेट पर एक्वायर की जा रही है। क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि जो लैण्ड एक्वायर की जा रही है उसका रेट बढ़ाया जाए जैसे कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 15 लाख एकड़ से बढ़ा कर 23 लाख प्रति एकड़ करने पर विचार किया है ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय डा0 साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बहादुरगढ़ में ऑटो मार्किट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए धारा 6 और 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है। इनकी पार्टी के नेता ने इसको रिलीज किया था मैंने तो उसका उत्तर दिया है। दूसरे माननीय साथी ने यह पूछा है कि इनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है। अध्यक्ष महोदय मेरे पास, आठ एफ0 आई0 आरस0 की फोटोस्टेट कॉपीज़ हैं। अगर मेरे साथी इनको देखना चाहेंगे तो मैं इनको दिखा दूंगा और ये जो भी जानना चाहेंगे वह भी इनको बता देंगे। जो ईशू इन्होंने रेज़ किया है से बताएं कि ये रोहतक की बात कर रहे हैं या कि गुड़गांव की ? (विघ्न) जैसे कि दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और वहां की कुछ औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर निकालने की दिल्ली सरकार ने उस आदेश की पालना की है। छोटे उद्योगों की इकाईयों के मालिकों ने मुख्य मन्त्री जी से विनती की थी और उनकी इस विनती को स्वीकार करते हुए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए दफा 4 के तहत नोटिस की अधिसूचना जारी हुई है। डा0 कादयान साहब जी, यह सारा काम एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने करवाया है।

श्री नफे सिंह राठी : स्पीकर साहब, ऑटो मार्किट बनाने के लिए दफा 4 और दफा 6 के नोटिस 1991 में जारी हुए थे। 1993 में बहादुरगढ़ नगरपरिषद् की सीमा बढ़ी थी तो सारी की सारी जमीन नगरपालिका सीमा के अन्दर आ गई थी। चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में इनके वरिष्ठ मन्त्री ने प्रौपर्टी डीलर्ज़ के साथ मिल कर इस जमीन को नगरपालिका बहादुरगढ़ से बाहर दिखा कर नगरपालिका को लाखों रुपये का चूना लगाया था। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मन्त्री जी अगर इसमें छानबीन करवाएं तो सारी बात सामने आ जाएगी। जिस प्वायंट के आधार पर यह जमीन रिलीज़ की गई है उस प्वायंट में दिखा रखा है कि वह जमीन गरीब हरिजनों की दिखा कर आज उसमें कॉलोनियां काटी जा रही हैं जबकि आज तक भी किसी गरीब हरिजन का वहां मकान नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो सरकार और नगरपालिका को चूना लगा है इसकी ये रिकवरी कैसे कर पाएंगे ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि उस समय की सरकार ने भूमि को रिलीज़ किया है। कारण तो इन्होंने उस समय रिलीज़ करते वक्त उसमें यही दर्शाया है कि वह भूमि बी0 सी0 और एस0 सी0 परिवारों से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कम्पलेंट दी है उनके नाम राम किशन और चन्द्र भान हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि वह हरिजनों और पिछड़े वर्गों की भूमि थी वहां मकान तो नहीं थे लेकिन भूमि का कुछ हिस्सा जरूर था वह कितनी भूमि थी इसका पता नहीं है। उसके बाद अवैध निर्माण हुए हैं। जिसकी वजह से आठ एफ0 आई0 आरस0 दर्ज हुई हैं। उसके बाद ही मैसर्ज़ बहादुरगढ़ एग्रो इन्डस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड वगैरह को नोटिस जारी किया गया है और इन्होंने अतिरिक्त सिविल जज सीनियर

[श्री धीरपाल सिंह]

डिविजन की कोर्ट में केस दर्ज किया है। माननीय कोर्ट ने 20-8-1998 को विभाग को सिविल सूट के अन्तिम निर्णय आ जाने तक कोई कार्यवाही न करने के आदेश दिये हैं। उसके बावजूद भी हम यह आधार लेकर हाईकोर्ट में गए कि यह भूमि नगरपालिका में पड़ती है लेकिन विभाग का केस खारिज कर दिया गया। उसके बाद विभाग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। वहां पर एस0 एल0 पी0 दायर की है जो कि अभी तक लम्बित है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली के नजदीक जो हमारे प्रदेश के जिले पड़ते हैं, आवश्यकता अनुसार वहां पर टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट जमीनें एक्वायर करता है लेकिन जिन किसानों और जमींदारों की जमीनें एक्वायर की जाती हैं वे यह सोचते हैं कि हमारी जमीनें एक्वायर नहीं की जा रही हैं बल्कि छीनी जा रही हैं। टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट की नीति के अनुसार जो टर्म्ज एंड कंडिशंज़ हैं उनके अनुसार वहां पर 60-65 प्रतिशत मकानों की 3-3 मंजिलें बनी हुई हैं पक्के लैंटर पड़े हुए हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ मेरी कांस्टीचुएंसी है और यह इनकी नीति से सम्बन्धित है। मेरा यह बहुत ही वैलिड प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ में सैक्टर 2 और 46 हैं, वे बल्लभगढ़ से लगती हुई कॉलोनियां हैं, वहां से बहुत सी रिप्रिज़ैंटेशंज आई हैं। 21-1-98 को सैक्टर 2 का केस कोर्ट में लगा था और उसमें कोर्ट से स्टे है लेकिन फिर भी वहां पर लोगों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से केसिज़ हैं। मंत्री जी उन लोगों को बुलाकर उनको समय देकर न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे या इस बारे में कोई आश्वासन देंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय बिसला जी ने सैक्टर 2 की बात की है। माननीय विधायक जी इस बात से परिचित हैं कि वहां पर अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं। कितने वहां पर अवैध कब्जे हैं इसके बारे में इनको जानकारी है। इन्होंने जो बताया है कि वहां पर पक्के मकान हैं। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह विभाग की नीति "ए" और "बी" टाईप मकानों का अधिग्रहण से पहले धारा चार के तहत के निर्माण हैं। उनको पता करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है उसमें डी0 टी0 पी0 और एल0 ए0 ओ0 और दूसरे अधिकारी मैम्बर हैं उनकी रिकोमैंडेशन के आधार पर अगर वह सिफारिश करते हैं कि ये निर्माण दफा चार से पहले के हैं उनको छोड़ना वाजिब है तो उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपके समाने कोई ऐसा मुद्दा है जिनको बुलाना जरूरी है तो हमें बता दें। हमारी सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी भी नागरिक को हम परेशान करें। लेकिन अगर कानून के रास्ते में कोई अड़चन आती है तो ऐसे में हम हरेक नागरिक से माफी चाहते हैं। जहां तक माननीय साथी ने मुआवजे की या और कोई बात की है मैं उनको बताना चाहूंगा कि डिप्टी स्पीकर साहब यहां पर बैठे हुए हैं इसलिए इनको सारी बात का पता है। इन्होंने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था। अब यह मामला विचाराधीन है। डा0 साहब के कहने से पहले ही मैं हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अब तो इन्होंने इस बारे में कह दिया लेकिन डा0 साहब वह समय भूल गये जब चौधरी देवी लाल जी देश के उप प्रधानमंत्री थे तो उस समय दिल्ली के किसानों ने देवी लाल जी से मिलकर यह प्रार्थना की थी कि जो उनकी जमीन एक्वायर हो रही है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के देहात आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। इसके बाद चौधरी देवी लाल जी ने वहां पर 6 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की राशि निर्धारित की थी। हो सकता है अब यह राशि बढ़ा दी गयी हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस साल वहां की कांग्रेस सरकार ने मुआवजे की राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 23 लाख रुपये की है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर साहब ने इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी। हरियाणा बनने के बाद और हुडा की कार्यवाही होने के बाद से पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से इस बारे में सारी बातें सुनीं। उस समय माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने यह बात दर्शायी थी कि हमारे सामने केवल दो ही आप्शन हैं एक तो यह कि नोएडा में जिस ढंग से भूमि का अधिग्रहण हो रहा है उसको हरियाणा में आधार माना जाए और दूसरा यह कि पंजाब में पुडा जिस ढंग से भूमि का अधिग्रहण कर रहा है उसको आधार माना जाए। इन्होंने इन दोनों पहलुओं पर उस समय ध्यान दिलाया था। सब बातें सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठकर इस बात का अध्ययन करें कि इन दोनों में कौन सा तरीका बढ़िया है जिनसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस पर फैसला करने के लिए माननीय डिप्टी स्पीकर साहब को अधिकृत किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह सरकार किसानों की शुभ चिंतक सरकार है और हम किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं उनको उजाड़ने की हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है।

श्री नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, यह सारी करतूतें चौधरी भजन लाल जी की सरकार की थीं। यह तो रिकार्ड की बात है। सर, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी तो उस समय सुखराली, मौलाहेड़ा, झाड़सा, कन्हई और गुड़गांव की जमीनें जिसमें हरिजनों के प्लाट्स भी काटे हुए थे एवं जिन जमीनों पर इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बने हुए थे, उसको एक्वायर कर लिया गया। लेकिन ऑटो मार्किट बनाने के लिए खाली जमीन को एक्वायर नहीं किया गया। ये सारे काम उस समय के मंत्रियों की मिलीभगत की वजह से हुए जिसके कारण सरकार को भी और किसानों को भी करोड़ों रुपये का चूना लगा।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर माननीय डिप्टी स्पीकर साहब का अपना पैतृक गांव है इसलिए उनको पता है। 15-3-1991 को जब हमारी सरकार थी तो उस समय सरकार के सामने वहां के एक गांव के नागरिकों ने अपनी एक समस्या रखी कि उनके यहां पर विभाग की तरफ से दफा चार और दफा 6 के नोटिस आ गये हैं। इनको साथ लेकर गांव के लोगों को गांव में शामलात की जमीन पर इकट्ठा करके उस समय सरकार ने गांव वालों से कहा कि 15-3-1991 तक वहां जो निर्माण हो गया सो हो गया उससे बाहर आप फैसला कर लें। बाद में गांव वालों ने फैसला कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी सरकार के ऐसे भी उदाहरण हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी राठी साहब ने कहा कि हरिजनों के मकानों का अधिग्रहण किया और हरिजनों के नाम की राजनीति करते रहे। मैं माननीय विधायक को जानकारी देना चाहूंगा कि सैक्टर 9 और सैक्टर 9-ए बहादुरगढ़ में ऑटो मार्किट बनाने का प्रस्ताव है और इसमें 20.83 एकड़ भूमि हमने इसके लिए रखी है उस पर काम शुरु हो रहा है और जल्दी ही निर्माण कराकर अलॉट कर देंगे।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि जो लैंड का मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव उस समय की सरकार ने लिया था, वह अच्छी बात है। वहां के किसानों की जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की जाती है और उसका मुआवजा औने-पौने दामों में दिया जाता

[डा0 रघुबीर सिंह कादयान]

है और जब वह प्लॉट हुडा द्वारा अलॉट किए जाते हैं तो उनका रेट एक हजार या पन्द्रह सौ रुपये प्रति मीटर के हिसाब से रखा जाता है। इस तरह से हुडा ने जो जमीन किसानों से ली और वह जमीन जब प्लॉट होल्डर्ज़ को दी तो उसमें करोड़ों रुपये का मार्जिन होता है। इस तरह से जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर हो रही है उनका ऐक्सप्लाइटेशन हो रहा है। हुडा उस पैसे को ले लेता है। सरकार द्वारा वह पैसा डिवैल्पमैंट पर खर्चा जाता है। सरकार उसे लोन पर लेती है या वैसे लेती है किसानों का जो पैसा था वह कहां खर्च हुआ, कहां नहीं, यह किसी को पता नहीं होता लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि किसान की जो जमीन हुडा एक्वायर करेगा या सरकार करेगी, क्या उसमें फार्मर्ज़ को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाएगा या नहीं, यह जानना चाहता हूं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सवाल भी है और मेरी भावना भी है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी भावना तब प्रकट कर देते, जब बजट पर बोल रहे थे।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन यह कहेगा कि जमीन का मुआवजा 20 लाख रुपया प्रति एकड़ होना चाहिए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने विस्तार से बताया है। हमारे विचार में दो ही ऑप्शन थे। जो सुझाव उपाध्यक्ष महोदय ने दिए थे दोनों में से जो बढ़िया होगा उसे ऐडौप्ट करेंगे। डॉ0 साहब इसके अलावा आपके पास कोई जानकारी है तो दे दें। दिल्ली की तुलनात्मक दृष्टि से नोएडा और पंजाब के किसानों को कम मिलता है। हरियाणा और दिल्ली में अंतर है। दिल्ली देश की राजधानी भी है बाकी प्रदेशों में जहां भी किसान को मुआवजा ज्यादा मिलता है उसकी मुझे जानकारी दीजिए। कमेटी में उस पर विचार कर लिया जाएगा। लेकिन मैंने यह कहा कि वर्तमान सरकार की यह मंशा है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री धीरपाल सिंह : मैंने आपकी शान में तो कुछ नहीं कहा। क्या मेरे से कोई गुस्ताखी हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा लेकिन मेरा नाम क्योंकि दो तीन बार डिबेट में आया है इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। भाई नफे सिंह के प्रश्न में बात चली और बिसला जी ने भी कहा। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम गुड़गांव वाले सबसे ज्यादा इस दुख के भरे हुए हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो जैसा नफे सिंह जी ने कहा कि हरिजनों की बात चली थी। इस बात को मेरे पड़ौसी भी जानते हैं हमारी जो इंदिरा आवास कॉलोनी थी जो सरकार ने दी थी वह भी एक्वायर की हुई है जिनके लिए मैं मंत्री जी से बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं। जो बात रघुबीर कादयान जी ने कही है यह चिंता का विषय है और इस चिंता को मैं सबसे ज्यादा अपनी समझता हूं। पिछले एक साल से इस पर सबसे ज़्यादा चिंता मैंने प्रकट की थी। आज भी लगातार एक साल से मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम इसमें किसानों को कुछ ज़्यादा राहत दे सकें। दिल्ली की बात जहां तक चली, इस मामले में सबसे पहले चौधरी देवी लाल जी ने राह दिखाई। उस इलाके

का चौधरी देवी लाल जी ने हुडा के अधिकारियों से सर्वे करा कर किसान तथा मजदूरों के बने हुए मकानों को अधिग्रहण से मुक्त करा दिया था, परन्तु पिछली सरकारों के समय में तो झाड़सा, सुखराली तथा मौलाहेड़ा गांवों के हरिजनों के मकानों को जो सरकार ने हरिजनों को प्लाट देकर बनवाए थे, को भी अधिग्रहण कर लिया गया था। आज भी इनसे उम्मीद करते हैं कि चौधरी धीरपाल सिंह जी आप मंत्री हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज प्रदेश का किसान आपकी तरफ देखकर आपसे यह उम्मीद करता है कि आप उसके हितों का ध्यान रखें। जैसे मैंने सुझाव भी दिया था कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में पुड्डा है उसका उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन हमारे किसान के साथ सबसे बड़ा भेदभाव पीछे से ही होता चला आ रहा है। चौधरी धीरपाल सिंह जी आपको पता होगा कि गुड़गांव के सैक्टर 51-52 के लिये कुछ दिन पहले जमीन की एक्वायरमैंट हुई उसमें दो-दो गांवों को अलग-अलग रेट दिये गये। वजीराबाद और झाड़सा गांवों को तो उनकी जमीन के 12-12 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मिले और समसपुर और बिन्दापुर गांवों को उनकी जमीन के लिए 6-6 लाख रुपये मिले। इस प्रकार उन गांवों के किसानों के साथ कितना बड़ा भेदभाव किया गया। इसमें हुड्डा महकमे की कहीं पोलिसी में कमी है। जब उस जमीन की सेल्स प्राइस एक है तो किसानों को कम्पंसेशन देते समय भेदभाव क्यों करते हो। इसलिए चौधरी धीरपाल सिंह जी मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह पुड्डा जब किसानों की जमीन एक्वायर करता है और उसकी प्राइस तय करता है तो उसमें पब्लिक का नुमाइंदा, उस एरिया का एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 और जिला परिषद् आदि को उस कमेटी में शामिल करता है जो कमेटी किसानों की जमीन की कम्पंसेशन प्राइस तय करती है और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की कमेटी में इन सदस्यों के इलावा उन गांवों के सरपंचों को भी शामिल करना चाहिये। अगर पब्लिक के नुमाइंदे उस कमेटी में शामिल होंगे तो इनिशियल स्टेज पर यह मामला ठीक हो जायगा और आगे जाकर किसानों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चौधरी बंसी लाल जी सदन में मौजूद नहीं हैं। जब उनकी सरकार थी उस समय इस प्रकार की एक कमेटी बनाई गई थी लेकिन उस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई और उस कमेटी ने एक इंच जमीन भी रिलीज़ नहीं की। इसलिए उस प्रकार की कमेटी बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दिल्ली के सराउंडिंग एरियाज़ गुड़गांवा से मानेसर तक हैं उनके किसानों के हितों को सुरक्षित रखें। हमारे क्षेत्र के किसान आपसे यह उम्मीद रखते हैं। मैं सदन के दूसरे भाइयों से भी यह अनुरोध करूंगा कि जो भी सुझाव इस मामले के बारे में दे सकें दें ताकि हम अपने एरिया को दिल्ली नोएडा और पुड्डा से भी बेहतर बना सकें। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गुड़गांव की बात आई थी इसलिये मुझे यह सब कहना पड़ा।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और उसी आधार पर इन तीनों स्कीमों का अध्ययन करेंगे। स्पीकर सर, जो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने किसानों की जमीन के अधिग्रहण के लिए कम्पंसेशन देने के अन्तर की बात की है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की जाती है और उस जमीन का भाव तय किया जाता है तो उस जमीन की किस्म को ध्यान में रखा जाता है कि वह जमीन सिंचित है, असिंचित है, बालू है, बूड़ है या बंजर है इस प्रकार उस जमीन की गिरदावरी को देखकर उस जमीन की कीमत को कमेटी तय करती है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय को और पूरे सदन को आश्वासन देता हूं कि हम जब भी इस प्रकार की कमेटी बनायेंगे उस कमेटी के द्वारा अध्ययन करने के बाद ही कोई उचित फैसला

[श्री धीरपाल सिंह]
लिया जायेगा और यह महसूस नहीं होने देंगे कि किसानों के साथ ज्यादती हुई है। स्पीकर सर, पिछली सरकारें ऐसी भी थीं कि माननीय उपाध्यक्ष जी के गांव में जो शमशान भूमि थी जहां इंसान पैदा होने के बाद निश्चित रूप से जाता है उस शमशान भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया था। परन्तु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आते ही मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त उस भूमि को मुक्त करवाया। अध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस प्रकार की शिकायत सुनने का मौका आपको नहीं मिलेगा कि किसानों के साथ इस प्रकार का भेदभाव हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार उनके हितों को महफूज रखेगी। हम किसानों को खुशहाली देंगे ऐसी इस सरकार की मंशा है और धारणा है।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना 10.00 बजे चाहता हूं। ये पंजाब में पुड्डा और नोएडा का उदाहरण देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि गुड़गांव शहर एक ऐसा शहर है जहां दिल्ली से भी ज्यादा मंहगी जमीनें हैं और वहां देश की बहुत अच्छी-अच्छी कॉलोनीज बनी हुई हैं। दिल्ली के लोग गुड़गांव में बसना चाहते हैं। नोएडा में जमीन 1000 रुपये गज है, पुड्डा में 700 रुपये गज है जबकि हमारे यहां जमीनों के रेट 5000 से भी ज्यादा हैं। इसलिए कम से कम 5 गुना या 7 गुना नए रेट देकर ये कोई उदाहरण पेश करें, इनको पुड्डा और नोएडा से कम्पैरीज़न नहीं करना चाहिए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, धर्मबीर जी की बात बहुत बढ़िया है लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि कबीर जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोए, जो मन खोजो आपनो मो से बुरा न कोय। अध्यक्ष महोदय, ये साथी जो आज सामने बैठे हुए हैं इनको जब मौका मिला तो मौका मिलने के बाद इन्होंने कभी यह देखने की जरूरत नहीं समझी कि किसान की भूमि किस भाव पर अधिग्रहीत हो रही है और किस भाव पर बेची जा रही है। जब लोगों ने इनको नकार दिया और ये लोग खाली हो गए तो इनके दिमाग में अच्छी बातें आने लगीं। जो बात हमारी जानकारी में नहीं थी, वह डिप्टी स्पीकर जी ने बताई है कि गुड़गांव में किसानों को ज्यादा भाव मिलना चाहिए, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद भी कहीं कोई अच्छा सिस्टम होगा तो उसको स्वीकार करने का हमारा फर्ज बनता है और इसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छूट दी हुई है।

Setting up of Medical College

***399. @Shri Balwant Singh Maina,**
Rao Dan Singh } Will the Minister of State for Health be pleased to state; whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Medical College in the State, if so, the details thereof, alongwith time by which the said College is likely to be set up.

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 एम0 एल0 रंगा) : जी नहीं, राज्य में कोई नया राजकीय मैडीकल कालेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हरियाणा प्रदेश में कोई प्राइवेट मैडीकल कालेज खोल रहे हैं।

@Put by Shri Balwant Singh Maina.

डा0 एम0 एल0 रंगा : अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में एक मैडीकल कालेज रोहतक में है जिसमें 115 सीटें हैं। उसमें प्रवेश लेने वाले प्रार्थियों की संख्या 5000 से 6000 के बीच में होती है। क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं हैं इसलिए निजी क्षेत्रों में यदि कोई प्राइवेट ट्रस्ट कालेज खोलना चाहती है तो हम उनको बढ़ावा देते हैं जैसे 1998 में हमारे यहां बाबा मस्त नाथ ट्रस्ट ने मैडीकल कालेज खोलने के लिए एप्लाई किया तो उसको हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है लेकिन एम0 सी0 आई0 की इंस्पैक्शन अभी नहीं हो पाई है। इसी तरह से 1999 में आचार्य सुशील मुनि जो गुड़गांव का ट्रस्ट था, ने मैडीकल कॉलेज के लिए एप्लाई किया, हमने उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है लेकिन एम0 सी0 आई0 की अभी तक इंस्पैक्शन नहीं हो पाई है। इसके बाद हमारी सरकार आने के बाद 3 संस्थाओं ने हमारे पास मैडीकल कॉलेज के लिए एप्लाई किया जिसमें एक संस्था गुड़गांव की दशमेश शिक्षा ट्रस्ट है जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एप्लाई किया। हमने उनको 150 सीटों का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके अलावा हिन्दू एजुकेशन ट्रस्ट, सोनीपत ने मैडीकल कॉलेज के लिए एप्लाई किया। उनको हमने 150 सीटों का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो अग्रोहा मैडीकल कालेज की अप्रैल, 1999 में धन के अभाव में ग्रांटें बन्द कर दी गई थीं जिस कारण यह कालेज बन्द हो गया था, उसकी बहाली के लिए हमने केस को वापिस लेकर 1999-2000 के बजट में 7 करोड़ 2 लाख रुपये का सप्लीमैन्ट्री एस्टीमेट्स का प्रावधान किया है और हमने 2 सालों में लगातार 4 करोड़ 14 लाख 40 हजार रुपये ग्रांट देकर के उस कालेज का निर्माण कार्य शुरु करवाया। (मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 152 विद्यार्थी सड़कों पर आ गए थे जिनको माइग्रेट करके रोहतक मैडीकल कालेज में भेजा गया था, उनका कहीं और जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के निजी प्रयासों से प्रधानमंत्री तक को डी0 ओ0 लैटर लिखवाए गये जिसके परिणामस्वरूप भारत के अंदर पहला इतिहास हुआ है कि माईग्रेशन की सीटें न होते हुए भी भारत सरकार ने प्रवेश/माईग्रेशन को रैगूलराईज किया है और जिन दो कालेजों की बात कर रहे थे इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये हुए हैं, सिर्फ एम0 सी0 आई0 की इन्सपैक्शन होनी है उसके बाद ये कालेज शुरु हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त मुलाना के अंदर एक डैंटल कालेज को 100 सीटों का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था जिसकी डी0 सी0 आई0 से इन्सपैक्शन हो चुकी है और इसमें प्रवेश शुरु हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथियों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकारी कालेज खोलने के लिए एम0 आई0 सी0 की बहुत ज्यादा कंडीशंज होती हैं जैसे 300 बैडज का अस्पताल पहले होना चाहिए, 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, बैंक गारंटी होनी चाहिए, चाहे वह गारंटी अस्पताल पर हो चाहे सीटों पर हो। इस तरह सरकारी कालेज खोलने में बहुत सी कंडीशंज होती हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे ये प्रयास हैं कि अगर कोई निजी संस्थान हमारी सरकार के पास टैक्नीकल एजुकेशन या चिकित्सा शिक्षा के बारे में आता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाये। हम इन दोनों क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल के अंदर जो ट्रोमा सैंटर खोला गया है क्या इसी तरह का ट्रोमा सैंटर एन0 एच0-8 पर भी खोला जायेगा ?

डा0 एम0 एल0 रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि जिस समय करनाल में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डा0 सी0 पी0 ठाकुर आये थे उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनसे बात की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि हमारा प्रदेश दिल्ली को तीन तरफ से लगता है और यहां पर चार नैशनल हाईवेज़ हैं इसलिए यहां पर इन हाईवेज़ पर ट्रोमा सैंटर होने चाहिएं, इसको सैद्धांतिक तौर पर डा0 ठाकुर साहब ने मान लिया था और कहा कि आप इस बारे में प्रस्ताव भेज दें हम विचार कर लेंगे।

Sports Activities/Stadium

***491. Sh. Banta Ram Balmiki :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the steps taken by the Government to improve the sports activities in the State, alongwith the details thereof, and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in Radaur, if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां, श्रीमान जी।

(क) राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1. राज्य के खिलाड़ियों को बस किराये में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।
2. खिलाड़ियों को प्रतिदिन दी जाने वाली खुराक राशि 30/- रुपये से बढ़ाकर 50/- रुपये की गई।
3. गुड़गांव व अम्बाला में हाकी के लिए एस्ट्रो-टर्फ लगाने की कार्यवाही अग्रसर है।
4. राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड/कारपोरेशन द्वारा खेल नर्सरियां अंगीकृत की गई हैं तथा खेल नर्सरियां आरम्भ कर दी गई हैं।
5. ओलम्पिक खेलों के शुभारम्भ से पूर्व सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि हरियाणा राज्य का जो खिलाड़ी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, उसे क्रमशः 1.00 करोड़, 50.00 लाख तथा 25.00 लाख रुपये की राशि नकद ईनाम के रूप में दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 के सिडनी (आस्ट्रेलिया) में ओलम्पिक खेलों में श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा भारत्तोलन खेल में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 25.00 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जा चुका है।
6. सरकार द्वारा हरियाणा ओलम्पिक संघ के भवन निर्माण के लिए तीन एकड़ भूमि पंचकूला में उपलब्ध करवाई गई है।
7. चौ0 चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक प्रशिक्षण केन्द्र 200 खिलाड़ियों के लिए स्थापित किया गया है। जिसके लिए दिनांक 14-1-2001 को एम0 ओ0 यू0 पर हस्ताक्षर किये गये।

8. इस सरकार द्वारा राज्य के नारनौल, सोनीपत, झज्जर, करनाल, अम्बाला, जीन्द, सिरसा तथा भिवानी में आधुनिक सुविधाओं की बढ़ौतरी हेतु 40.00 लाख रुपये की राशि दी गई है।

9. राज्य सरकार द्वारा जिला फतेहाबाद में बनाये जाने वाले स्टेडियम हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

10. राज्य सरकार द्वारा जिला सिरसा में एक राज्य खेल परिसर बनाने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

11. भारत सरकार से अनुदान लेने के लिए ग्रामीण स्कूलों/खेल मैदानों के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। अब तक 10 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं, अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

12. राज्य में नई खेल नीति का गठन विचाराधीन है।

13. सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रस्ताव है।

श्री बंता राम बालिमकी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से जानना चाहूंगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं और क्या-क्या सुधार किए गए हैं ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने सत्ता में आते ही खेलों को बहुत महत्व दिया। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के सभी नामी खिलाड़ियों को एकत्रित करके कहा कि जो खिलाड़ी ओलम्पिक खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करेगा उसे क्रमशः 1.00 करोड़, 50.00 लाख तथा 25.00 लाख रुपये की राशि ईनाम के रूप में दी जायेगी। श्रीमती कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने पर हरियाणा सरकार ने उसे ईनाम के तौर पर 25.00 लाख रुपये अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को प्रतिदिन दी जाने वाली खुराक राशि 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई। राज्य के खिलाड़ियों को बस किराये में 75 प्रतिशत की छूट दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। इसी तरह सरकार द्वारा हरियाणा ओलम्पिक संघ के भवन निर्माण के लिए तीन एकड़ भूमि पंचकूला में उपलब्ध करवाई है। इसी तरह सरकार द्वारा राज्य के नारनौल, सोनीपत, झज्जर, करनाल, जींद, अम्बाला, भिवानी और सिरसा में आधुनिक सुविधाओं की बढ़ौतरी हेतु 40.00 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जिला फतेहाबाद में बनाये जाने वाले स्टेडियम हेतु 8 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसी तरह सिरसा जिले में भी स्टेडियम बनाने के लिए 27 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है। सरकार हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और अब खेलों के प्रति रूझान बढ़ने लगा है। गांव-गांव में खिलाड़ी बढ़ने शुरु हुए हैं। पहले लड़के शराब बेचने में लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस समाज को टूटने से बचाने का काम किया है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य संसदीय सचिव महोदय से जानना चाहूंगा कि अम्बाला और गुड़गांव में हाकी के लिये जो एस्ट्रो टर्फ बनाये जाने हैं उन पर कितना-कितना खर्चा आएगा ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, एक एस्ट्रो टर्फ के ऊपर दो करोड़ खर्च होंगे जिसमें से एक करोड़ हरियाणा प्रदेश की सरकार देगी और एक करोड़ भारत सरकार से आएगा। इन एस्ट्रो टर्फ के लिये टैण्डर भी बुलाए हुए हैं जो कि 20 तारीख को खुलने हैं।

श्री रमेश खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य संसदीय सचिव महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिये क्या नोर्म्ज़ बनाये हैं ? मेरे हल्के में भी दो-तीन गांव हैं जहां के लड़के एशियाई गेम्ज़ में खेलकर आए और गोल्ड मैडल लेकर आये थे। ये कथूरा, रिंढाना और बड़ौदा गांव हैं, क्या इन गांवों में भी कोई स्टेडियम बनाएंगे ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, इस तरह के स्टेडियम बनाने के लिये विशेष तौर पर प्रस्ताव पास होते हैं। छोटे से छोटे स्टेडियम के लिये भी छः एकड़ जमीन जरूरी है। अगर उन गांवों में से कोई पंचायत इस तरह का रैजुलेशन पास करेगी और कम से कम छः एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव लेकर आएगी तो वहां पर भी स्टेडियम बनाये जाने के लिये विचार किया जाएगा।

चौधरी रामफल कुण्डु : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या फतेहाबाद में भी हाकी के लिये कोई एस्ट्रो टर्फ बनाने का प्रावधान है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, फतेहाबाद में एस्ट्रो टर्फ बनाने का प्रावधान अभी नहीं है। फतेहाबाद में एक स्टेडियम बनाने का विचार है उसके लिये भौलिया गांव की आठ एकड़ जमीन एक्वायर भी कर ली गई है लेकिन यह महसूस किया जा रहा है कि इस स्टेडियम को बनाने के लिये आठ एकड़ जमीन भी थोड़ी पड़ेगी इसलिये चार एकड़ और एक्वायर करने के लिये बात चल रही है। ज्यों ही चार एकड़ और जमीन एक्वायर करने के लिये कार्यवाही पूरी हो जाएगी तो फतेहाबाद में स्टेडियम बनाया जाएगा।

डा0 सीता राम : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने बताया कि सिरसा में एक स्पोर्टस स्टेडियम बनाया जाएगा तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि इस स्टेडियम पर कितनी लागत आएगी और यह स्टेडियम कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, सिरसा के अन्दर स्टेडियम बनाने का विचार है जिसके लिये 27 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है। जहां तक स्टेडियम पर कितनी लागत आने का सवाल है तो स्टेडियम पांच लाख में भी बन सकता है, 10 लाख में भी बन सकता है। यह स्टेडियम तो बहुत बड़ा बनेगा इसलिये अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस स्टेडियम के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ?

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर सर, पिछले दिनों चरखी दादरी में एक स्टेडियम की आधारशिला रखी गई थी जो कि श्री अभय सिंह चौटाला जी ने रखी थी। इस बात को आठ-दस महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस स्टेडियम का काम शुरु नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि स्टेडियम का काम कब शुरु होगा और कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, ऐसा नहीं है कि पत्थर या आधारशिला रख के हम चले जाएं। ऐसा नहीं है। हम कहीं नहीं जाते। इनकी तरह नहीं है कि पत्थर रखकर चले जाएं। हमारी सरकार ने जो पत्थर रखे हैं उन पर काम भी करेंगे। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा सदन में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वैश्चंज का जवाब दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य संसदीय सचिव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे कदम हैं यदि वे कदम उठाए जाएं तो सरकार का खर्चा नहीं होगा। अगर उन कामों की व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो सरकार का खर्च कम हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के बहुत से स्कूलों में स्पोर्टस के पाठ्यक्रम हैं और गांव के स्कूलों में पी० टी० आई० होता है जो बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में खिलाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इन से निवेदन है कि पी० टी० आई०ज० को सख्त हिदायत दी जाए कि वे अपने कमरों में न बैठे रहें और पी० टी० का जो पीरियड होता है उसमें बच्चों को स्पोर्टस का ज्ञान दें और ग्राउंड में खेल खिलाएं। यह नहीं होना चाहिए कि पी० टी० आई० अपने कमरे में ही बैठा रहे। उसको अपनी काठ की कुर्सी ग्राउंड में डाल कर बैठना चाहिए और बच्चों को खेल खिलाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्पोर्टस को शिक्षा की नीति के साथ जोड़ेगी ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पोर्टस को बहुत गम्भीरता से लिया है और सरकार का खेल नीति बनाने का मामला अंडर कंसीड्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कुछ इस प्रकार के कदम हैं यदि वे कदम उठाए जाएं तो सरकार का खर्च कम हो सकता है। हमने केन्द्रीय सरकार को स्कूलों के खेलों के मैदानों को ठीक करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे और केन्द्रीय सरकार ने उनमें से 10 प्रस्ताव मंजूर भी कर दिए हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में अपनी सैटिस्फैक्शन जाहिर की है।

श्री बन्ता राम बाल्मीकि : स्पीकर साहब, हमारे कुरुक्षेत्र में सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और वे लम्बे तगड़े खिलाड़ी हैं। वहां पर हाकी के सबसे बड़े प्लेयर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कुरुक्षेत्र में हाकी का एस्ट्रो टर्फ बनाने का सरकार का विचार है ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रादौर हल्का हरियाणा का दिल है क्या वहां पर खेल स्टेडियम बनाने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बन्ता राम जी ने बड़ा अहम् सवाल पूछा है और इनका सवाल बिसला जी के सवाल के साथ मेल खाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हाकी के एस्ट्रो टर्फ बनाए जाएंगे उनमें आधा खर्चा प्रदेश की सरकार करेगी और आधा खर्चा भारत सरकार करेगी। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। कुरुक्षेत्र और सिरसा में जो हाकी के एस्ट्रो टर्फ बनाए जाएंगे उनका सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। स्पोर्टस अथोरिटी आफ इंडिया का यह पत्र आया है जिसके अन्दर भिवानी के स्टेडियम में एक एथलेटिक ग्राउंड और हाकी के लिए सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ देने का प्रावधान है जिस पर डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका प्रावधान केन्द्रीय सरकार ने अपने 2001-2002 के बजट में किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं राई स्पोर्टस स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा कि इस स्पोर्टस स्कूल के स्तर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए भारत सरकार इसका खर्च वहन करेगी इसकी चिट्ठी भी भारत सरकार से 31 अक्तूबर को हमारे पास आ चुकी है और इसकी इन्सपैक्शन भी कम्पलीट हो चुकी है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सिरसा में वालीबाल का और गुड़गांव में हाकी का केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, यहां पर सरकार की तरफ से बताया गया कि सरकार की तरफ से जो पत्थर रखा जायेगा उसको बड़ी अहमियत के साथ रखा जायेगा और जो पत्थर रखे जायेंगे उन पर कार्यवाही होगी। मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इनकी अपनी पार्टी के विधायक रामफल कुण्डू जी के गांव में मुख्य मन्त्री जी पत्थर रख कर आये थे। उस पत्थर को लोगों ने तोड़ दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस रखे हुए पत्थर पर कोई कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, आप बैठिये यह कोई सवाल नहीं है।

श्री रामपाल माजरा : यह इररैलेवेंट प्रश्न है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, जो क्वैश्चन चल रहा है यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि पुरानी सरकार ने एक ऐसा गलत निर्णय ले लिया था बावजूद हम सबके विरोध के बाद भी और जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उनके द्वारा भी विरोध जाहिर करने पर गलत निर्णय लिया गया और उस वक्त की सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही जिसका परिणाम यह निकला कि शराब बंदी की आड़ में हरियाणा प्रदेश में एक माफिया खड़ा हो गया था जिसकी वजह से पूरे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। मौजूदा सरकार ने नई पीढ़ी के रूझान को बदलते हुए उनका ध्यान स्पोर्टस साइड की तरफ किया यानि उनका रूझान खेलों की तरफ दुबारा किया। राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने ठीक कहा है कि अब हमारे बच्चों ने खेलों की तरफ दिलचस्पी दिखानी शुरु की है। आपको पता है कि सिडनी के खेलों में मल्लेश्वरी जी कांस्य पदक लेकर आई इसी प्रकार से सीमा अंतिल ने व कल्पना चावला ने भी हरियाणा का नाम खेलों में ऊंचा किया है। इससे जाहिर है कि नई पीढ़ी का रूझान खेलों की तरफ हुआ है वह इसलिए हुआ है कि मौजूदा सरकार ने अपने यहां के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है, अच्छे खिलाड़ियों को नौकरी में रिजर्वेशन दी गई है और अच्छे खेल के मैदान तैयार किये गए हैं। अब सरकार ने मुकम्मल फैसला लिया है कि जिस गांव में भी कोई पंचायत खेल स्टेडियम बनाना चाहती है तो उसके खर्च का 1/4 हिस्सा उस गांव के लोग देंगे और 3/4 हिस्सा सरकार देगी ताकि खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे जितने बोर्डज व कार्पोरेशन्ज हैं या जो प्राईवेट कम्पनीज़ हैं उनको भी कहा है कि आप पहले की तरह अपने यहां पर विभिन्न-विभिन्न खेलों की अच्छी-अच्छी टीमें तैयार करें। हमने भारत सरकार से मांग की है कि हरियाणा में एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाये ताकि खेलों को और अधिक बढ़ावा मिल सके और खेलों के मामले में हरियाणा देश का मान-सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, एशिया स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा सके। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार देश की रक्षा करते-करते हमारे हरियाणा के जवान देश का नाम रोशन कर रहे हैं उसी प्रकार से खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा कर सकें। हमारे यहां पर राई के अन्दर एक स्पोर्टस स्कूल था। वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का था, उसको बड़ी अच्छी सोच के साथ बनाया गया था लेकिन बाद में उसको एक ब्लाक तक ही सीमित करके रख दिया गया। अब हम दुबारा से भारत सरकार के सहयोग से इस स्कूल को नई पीढ़ी को अच्छे खेलों के खिलाड़ी तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रहे हैं। गुप्ता जी ने रामफल कुन्डू के नाम का जिक्र कर तो दिया लेकिन ये जो अच्छी बातें सरकार कर रही है उसको कहना भूल गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार में इतने पत्थर रखे गए थे कि उनको इकट्ठा करने

में बहुत समय लग जायेगा लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों के समय में भी जो अच्छे निर्णय लेते हुए पत्थर रखे गए थे और जिन पर अभी तक कार्य नहीं हुआ है चाहे वे पत्थर पिछले 20-30 साल पुराने ही क्यों न हों, उन अच्छे कामों को भी यह सरकार करने के लिए वचनबद्ध है। (विघ्न) एक पत्थर तोड़ने की बात तो है नहीं (विघ्न) उन पत्थरों से तो लोग आपका सर फोड़ेंगे (हंसी)

श्री रामफल कुण्डु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने "गुस्साए हुए लोगों ने" कहा है वहां पर कोई गुस्साए हुए लोग नहीं थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खरक गागर में पत्थर लगाने के लिए गए थे। गांगोली सब-माईनर कालांवाली सब माईनर Kharak Gagar माईनर का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और अप्रैल के महीने में दोनों नहरों में पानी चलेगा और विद इन टाईम लिमिट वाटर वर्क्स में पानी आएगा। अध्यक्ष महोदय, किसी शरारती तत्व ने जो कर थोड़ा बहुत तोड़ा है, यह मैं मानता हूं ? लेकिन गुस्साए हुए लोगों ने नहीं। लोग तो बड़ी खुशी से झूम उठे थे कि इस सरकार ने प्रगति के इतने काम किये हैं। पता नहीं गुप्ता जी कैसे यह कह रहे हैं कि गुस्साए हुए लोगों ने तोड़ा (विघ्न) गुप्ता जी इस बात का जवाब दें।

तारांकित प्रश्न संख्या 598

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भागी राम सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Construction of Bus Stand in Pataudi Town

***428. Shri Rambir Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand in Pataudi town ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Bus Stand is likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) :

(क) और (ख) जी हां ! उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर सरकार पटौदी में बस स्टैण्ड बनाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी।

श्री रामबीर सिंह : माननीय स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि वहां पर भूमि उपलब्ध है। 10 साल पहले सैक्शन 6 और 4 के नोटिस हुए थे लेकिन इसके बावजूद भी प्रोविन्शियल गवर्नमैंट की 14 एकड़ जमीन पड़ी हुई है तथा रोड के ऊपर एक एकड़ और जमीन भी उपलब्ध है। अगर परिवहन विभाग उस जमीन को लेना चाहता है तो उसके लिए खतो-खिताबत करके उसको जल्दी ले और वहां पर बस स्टैंड जल्दी बनवाने का

[श्री रामबीर सिंह]

कष्ट करें। वहां पर जमीन उपलब्ध है और प्रशासन की ओर से वहां पर एक सब-कमेटी बनाई गई थी जिसमें जी0 एम0 रोडवेज, एक्सीयन, पी0 डब्ल्यू0 डी0 और तहसीलदार को शामिल किया गया है और उनको इसे फाईनेलाईज करने के लिए एक महीने का टाईम दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस ओर ध्यान दे कर इस बस स्टैंड को जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, मैंने पहले ही बताया है जब जमीन उपलब्ध होगी तब उसके ऊपर ध्यान देंगे अगर माननीय सदस्य के ख्याल में कोई ऐसी जगह है तो वे बता दें उसका सर्वे करवा कर उस पर बस स्टैण्ड बनाने बारे विचार करेंगे।

श्री रमेश राणा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि घरौंडा जी0 टी0 रोड पर स्थित है वहां पर न तो कोई बस स्टैंड है और न ही कोई बस क्यू शैल्टर है। क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि वहां पर बस स्टैंड बस क्यू शैल्टर बनाया जाए, अगर हां तो यह कब तक बनायेंगे और अगर नहीं तो क्या वहां पर इस बारे में वे कोई विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अशोक कुमार : स्पीकर सर, वैसे तो यह सवाल पटौदी बस स्टैंड के बारे में है फिर भी सम्मानित सदस्य ने घरौण्डा बस स्टैंड के बारे में पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां का सर्वे करवा कर वहां पर बस स्टैंड बनाने बारे विचार किया जाएगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ बस स्टैंड को बने हुए तकरीबन 6 साल हो गये हैं लेकिन ऐगजिट और ऐन्टरी का रास्ता अभी भी कच्चा और कंजस्टिड हैं जिसकी वजह से लम्बी दूरी की बसें बस स्टैंड के अन्दर जाने की बजाए बाहर से ही मुड़ कर चली जाती हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके रास्ते की लिमिट को बढ़ाकर उसको पूरा करने बारे विचार करेंगे और यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ये इस बारे में अलग से नोटिस दें तो इस पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती वीना छिब्बर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहती हूं कि अम्बाला शहर में जो लम्बी दूरी की बसें आती हैं वे कालका मोड़ पर रुकती हैं लेकिन बरसात और तेज धूप के कारण वहां पर लोगों को बड़ी असुविधा होती है। जी0 टी0 रोड पर या गुरुद्वारा मंजी साहब या कालका मोड़ पर कोई बस क्यू शैल्टर या बस स्टैंड बनाने बारे विचार करेंगे ? दूसरे अध्यक्ष महोदय, बलदेव नगर कैम्प में एक छोटा सा बस स्टैंड बना हुआ है लेकिन वहां पर कोई भी बस रुकती नहीं है और न ही अम्बाला शहर की टिकट दी जाती है। क्या परिवहन मन्त्री जी इस बारे विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, बस क्यू शैल्टर के बारे में मंजी साहब गुरुद्वारा के पास बहन जी ने कहा है उसका सर्वे करवा कर वहां पर बस क्यू शैल्टर का निर्माण करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Stadium in B.A.R. Janta College, Kaul

***497. Sh. Tej Vir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of the Stadium in B.A.R. Janata College, Kaul in Pundri Constituency is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कौल स्टेडियम का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। स्टेडियम का शेष कार्य धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Repair of Roads

***508. Shri Chander Bhatia :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some portion of the road opposite to Rajeev Colony, ward No. 2 in Faridabad is damaged badly ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said road in near future ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न में सड़क की मरम्मत का प्रस्ताव है और वर्ष 2001-2002 के दौरान सड़क की मरम्मत का काम पूरा किये जाने की संभावना है।

Opening of Government Girls College, Gohana

***477. Dr. Ramkuwar Saini :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government Girls College at Gohana ; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : जी नहीं, श्रीमान्।

Change in Existing Policy of Private Bus Service

***321. Shri Padam Singh Dahiya :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make any change in the existing policy regarding privatisation of bus service/routes in the State ?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : हां, श्रीमान् जी।

T.B. Disease

***518. Shri Balbir Singh :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the T.B. disease has been revived in the State ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to check this disease ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 एम0 एल0 रंगा) :

(क) जी हां, यह रोग अब भी राज्य में प्रचलित है ;

(ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राज्य में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है।

Diet in Kaithal

***268. Shri Lila Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a DIET (JBT Training Centre) in village Teek or Geonge in District Kaithal ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be started ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) जी हां, श्रीमान् जी, ग्योंग जिला कैथल में डाईट खोलने के लिये प्रस्ताव भारत सरकार को विचार हेतु भेजा जा चुका है।

(ख) यह तभी आरम्भ की जा सकती है जब भारत सरकार द्वारा स्कीम की स्वीकृति प्राप्त हो जाये तथा यह राशि उपलब्ध करा दी जाये।

Digging of a Drain

***560. Smt. Veena Chibber :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to dig out a drain (Nala) from Hari Palace to Daruri Naka via Travani, Dokhamba Chowk ?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष चन्द) : जी नहीं।

Upgradation of Schools

***482. Shri Shashi Parmar :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Girls High Schools, Baund, Dhanana and Tigrana into 10+2 system school of district Bhiwani ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) (क) के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Crop Insurance Policy

***602. Shri Krishan Pal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the State Government has implemented Crops Insurance Policy as introduced by the Central Government ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु) : नहीं, श्रीमान् जी।

Building of Kalanaur Hospital

***588. Smt. Sarita Narain :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the building of Veterinary Hospital, Kalanaur is in dilapidated condition ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/reconstruct the said building ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी मोहम्मद इलियास) :

(क) जी हां।

(ख) पशु चिकित्सालय के भवन की छत की मुरम्मत की जा चुकी है तथा कुछ भाग में बिजली की फिटिंग भी बदली जा चुकी है।

ITI in Indri Constituency

***395. Shri Bhim Sain Mehta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an Industrial Training Institute in Indri Constituency ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) इंद्री निर्वाचन-क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Adequate Supply of Canal Water in the Distributaries

***286. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government is aware of the fact that water for use for irrigation from J.L.N. Canal is not reaching the tail end of the following distributaries :—

(i) Ladhuwas Distributary

(ii) Raliawas Distributary

(iii) Balawas Distributary

(iv) Jeetpura Distributary

(v) Nikhri Distributary

if so, the steps taken by the Government for adequate supply of water to the tail end ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं श्रीमान् जी, जीतपुरा व निखरी वितरिकाओं में पानी लगातार पहुंच रहा है। रालियावास वितरिका में पानी कि0 मी0 8 तक पहुंच रहा है लेकिन लाधुवास व बालावास वितरिका के अन्तिम छोर तक पानी पूरी तरह नहीं पहुंच रहा है। जबकि दोनों वितरिकाओं के अन्तिम छोर पर बने हुए तालाब मास दिसम्बर 2000 और जनवरी 2001 में भर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त कोई भी पानी सप्लाई का टैंक जो इन वितरिकाओं में पड़ता है, खाली नहीं रहने दिया गया।

पांचों वितरिकाएं जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना पर पड़ती है जोकि एक उठान नहर प्रणाली है। यमुना नहर और भाखड़ा जलाशय में कम पानी उपलब्ध होने के कारण प्रणाली की मूल नहरों में पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरा जवाहर लाल नेहरू पर लगे हुए पम्पिंग सैट जो कि 21 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और उनकी पानी उठाने की क्षमता कम हो चुकी है। इन पम्पों के नवीनीकरण का कार्य धन की व्यवस्था न होने के कारण नहीं हो सका। अब जे0 एल0 एन0 नहर के ऊपर लगे हुए पम्पों की क्षमता बढ़ाने के लिए 272 लाख रुपये की परियोजना नाबार्ड आर0 आई0 डी0 एफ0-1/भाग-II के अन्तर्गत स्वीकृत हुई है और इन पम्पों का नवीनीकरण राशि उपलब्ध होने पर कर लिया जाएगा। यह कार्य हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकूप निगम के द्वारा करवाया जाएगा।

यमुना नहर व भाखड़ा जलाशय में पानी की मात्रा बढ़ने पर और इन पम्पों के नवीनीकरण के बाद उपरोक्त वितरिकाओं के अन्तिम छोर पर पानी की मात्रा उपलब्ध होगी।

Leasing Out of Mines

***603. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Government has taken back or there is any proposal under consideration of the Government to take back mines operated by the Haryana Minerals Ltd., a State Government undertaking ; and

(b) whether such mines which were taken back or likely to be taken back by the Government from HML referred to in part (a) above have been leased out or proposed to be leased out to private parties ; if so, the criteria adopted for the purpose ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड ने 24-10-2000 को 20 खानों के खनन पट्टे छोड़े हैं।

(ख) नहीं। इनको अभी खनन पट्टे पर नहीं दिया गया है। इन को निजी पार्टियों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। खान एवम् खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(3) तथा पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के नियम 10(2) के निम्न-लिखित मानदंडों अनुसार इन खानों के खनन पट्टे प्रदान किये जायेंगे :-

(i) आवेदक की खनन कार्यों बारे विशेष जानकारी या अनुभव,

(ii) आवेदक के वित्तीय स्त्रोत,

(iii) आवेदक के पास कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों या उस द्वारा रखे जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों की गुणवत्ता,

(iv) आवेदक द्वारा खनिज तथा खानों पर आधारित उद्योग में प्रस्तावित पूंजी निवेष।

Supply of Water in Kairu System

***274. Shri Dharamvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the tail of burji number of Kairu System situated on the Gujrani Canal in district Bhiwani together with the number of years since when the water has not reached upto its tail ; and

(b) if so, the time by which the water will be made available by the Government upto the tail end of the said Kairu System ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) केरू माइनर की टेल बुर्जी 85000 फुट तक है।

(ख) इस समय यमुना नदी और भाखड़ा जलाशय से सप्लाई बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है तथा टेल तक पानी पहुंचाना संभव नहीं है। पिछले 20 सालों से लगातार चलने के कारण पम्पों की उठान शक्ति भी घट गई है। सप्लाई में वृद्धि होने तथा पम्प घरों का नवीनीकरण करने पर टेल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा।

Construction of a Minor from Pabra Head

***305. Shri Bhag Singh Chhatar :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction of a minor of 6 km. from Pabra Head is likely to be completed ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान् जी, ऐसी कोई योजना नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Opening of New Engineering College

25. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Engineering College and information technology college in the State during the year 2000-2001 and 2001-2002, together with the criteria adopted for giving admission therein ; and

(b) whether any seats for the admission of students belonging to rural area of the State shall be reserved in the colleges referred to in part (a) above ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी नहीं। वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में नये राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है। अपितु वर्ष 2001-2002 के दौरान गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार तथा 5 अन्य ट्रस्ट/समितियों को राज्य में 6 प्राईवेट इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार ने अनापत्ति पत्र जारी किये हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का दाखिला 'प्रवेश परीक्षा' की मैरिट के आधार पर होगा।

हरियाणा राज्य में एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की योजना है। इस संबंध में राज्य सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को ग्वालियर तथा इलाहाबाद में भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये दो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं के समान ही एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य में भी स्थापित करने हेतु प्रार्थना की है तथा इस सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्वीकृति होने के उपरान्त ही प्रवेश एवं आरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित किये जाएंगे।

(ख) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दाखिला लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

Sanctioned Strength of Staff

26. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) the details of the sanctioned strength of Doctors/Nurses/Clerks/Class IV/Chowkidars in Civil Hospital, Palwal ;

(b) whether some posts out of the posts referred to in part (a) above are lying vacant ;

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the posts referred to in part (b) above during the year 2000-2001 ; and

(d) the details of the medicines monthly supplied to the said Hospital during the year 2000 ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा0 एम0 एल0 रंगा) :

(क)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	:	1
	दंत चिकित्सा अधिकारी	:	1
	चिकित्सा अधिकारी	:	10
	नर्सिंग सिस्टर	:	3
	स्टाफ नर्स	:	19
	लिपिक	:	2
	चतुर्थ श्रेणी/चौकीदार	:	27

(ख) जी हां। उपरोक्त (क) में वर्णित पदों में से कुछ पद रिक्त पड़े हैं।

(ग) जी हां, चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) सप्लाई की गई दवाइयों की सूचि संलग्न है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान सामान्य हस्पताल, पलवल को सप्लाई की गई दवाइयों की सूची

सप्लाई की तिथि	दवाई का नाम	सप्लाई की मात्रा
4-5-2000	Inj. ARV 30 ml	100 Vials
5-7-2000	Inj. Hepatitis-B	100 Vials
	Tab. Antacid	10000
	Inj. Ampicillin 500 mg	400 Vials
	Tab. Albendazole	1000 tab.
	Inj. Avil	100 Am.
	Tab. Atenolol	4000
	Cap. Amoxycillin 500 mg.	1000
	Tab. Astemizol	1000

[डा0 एम0 एल0 रंगा]

सप्लाई की तिथि	दवाई का नाम	सप्लाई की मात्रा
	Tab. B. Complex	20000
	Tab. Cotrimoxazole SS	3000
	Tab. Cotrimoxazole DS	3000
	Tab. Ciprofloxacin 500 mg	500
	Tab. C.P.M.	20000
	Cap. Carbase	1000
	Tab. Cetriwal	2000
	Cap. Cloxacillin 500 mg	1000
	Tab. Colsprin	8000
	Tab. Ciprofloxacin+Tinidazole	1500
	Inj. Cloxacillin	280
	Inj. Diclofenac Sodium	500
	Inj. Dexamethasone	50
	Tab. Dependal M	5000
	Cap. Doxycycline	1000
	Tab. Dyspas Plus	1000
	Tab. Disprin	5000
	Tab. Etharnsylate	500
	I/V DNS	100 bottles
	Tab. Dytide	1000
	Tab. Diclopara	1000
	Inj. Dizaepam	100
	Tab. Eto-solbutol	3000
	Tab. Enteromax DF	1000
	Tab. Enalapril	1700
	Tab. Flucold	3000
	Inj. Haemoceal	15 bottles
	Cap. Mycosin	3000
	Tab. Metronidazole	2000
	Tab. Monosorbitrate	1400
	Tab. Multi Vitamin	3000
	Inj. Metclopromide	200
	Tab. Metronidazole Furazolodine	2000
	Tab. Norfloxacin 400 mg	1000
	Tab. Nemuslide	3000
	Tab. Numol	1000
	Tab. Paracetamol	10000

सप्लाई की तिथि	दवाई का नाम	सप्लाई की मात्रा
5.7.2000	Tab. Paramet	2000
	Inj. PP 4 lac	500 vials
	Tab. Ramcici	500
	Tab. Solbutamol	5000
	Cap Tetracycline 500 mg	2000
	Tab. Tus Q	1000
	Tab. Tinidazole	2000
	Tab. Vit. C	3000
	Inj. Xylocaine 2%	100
	Acriflavin	10
	Syp. Albendazole	100
	Sy. Amoxycillin & Podmoloxin	100
	Bandage 15 cm x 5 metre	30 dozen
	Syp. Paracetamol	100 bottles
	Cortula M. Eye drops	100
	Syp. Cotrimoxazole	100 bottles
	Syp. Cephalexin	100 bottles
	Cosyp Cough Syrup	100 bottles
	Diclofenac Gel.	50
	Syp. Furoxon	200 bottles
	Syp. Flucold	100 bottles
	Cleaning Powder	25
	Gloves	175 pairs
	Gention Violet	10 bottles
	Glass Syringe 2 ml	10
	Keralin Oint	100
	Ketoconazole Ointment	10
	Syp. Liv. 52	25 bottles
	Mercurochrome	10 bottles
	Syp. Nimuslide	100 bottles
	Occuflur Eye Drops	300
	ORS	300 packets
	Pyricort Eye Drops	275
	Phenyl liquid	30 bottles
	Povidine Iodine Oint	10

[डा0 एम0 एल0 रंगा]

सप्लाई की तिथि	दवाई का नाम	सप्लाई की मात्रा
	Syp. Paracetamol	30 bottles
	Proctosedyl Ointment	90 tubes
	Soframycin Eye drops	200
	Inj. Salvodyl	100 bottles
	SS Eye Drops	200
	Silver Sulphadizaine Ointment	10 Jar
	Soframycin Skin Oint	50 T
	Sodium Fussidate Oint	100 T
	Three Way Stopcock IV Canula	600
	Washing Powder	30 kg.
	Zoxan Eye Drops	100
	Zytee Gum Paint	50
	Towel	15
	X-ray film 8'x10'	1 Pkt. x 50 film
14-8-2000	I/V Dextrose with NS	17 bottles
	Tab. Paracetamol	5000
8-11-2000	Inj. B_1 B_6 B_{12}	200 ampules
	Inj. Cloxacillin	60
	Inj. Dexamethasone	100
	Inj. Diazepam	100
	Tab. Nemuslide	1000
	Tab. Vit. C	1000
	Cotton 500 mg	100
	Syp. Mycosin	50 bottles
	Povidine Iodine Ointment	50 tubes
	Sodium Fussidate	50 T
	Broom sticks	15 kg.
	Washing Powder	25 kg.
	Floor Cleaning Powder	60 kg.
	Phenyl Liquid	30 litres
	Opij Oxygen Disposable 8 litre	2 containers
	Tab. Paracetamol	10000
	Tab. cotrimoxazole DS	3000
	Inj. ARV 30 ml	25 vials

सप्लाई की तिथि	दवाई का नाम	सप्लाई की मात्रा
13-12-2000	Inj. ARV 30 ml	50 vials
	Tab. Paracetamol	10000
	Cap. Amoxycillin	1000
	Cap. Tetracycline	1000
	Tab. Cotrimoxazole DS	2000
	Inj. Diclofenac Sodium	300
	Gauge Surgical	30 Than
	Bandage 10cm x 4m	20 dozen
	Bandage 15cm x 5m	20 dozen
	Cosyp Cough Syrup	100 bottles
	Inj. Phenaramine Maleate	100 ampules
	Tab. Astemizole	1000
	Tab. Phenetoyn sodium	1000
	Tab. Dicyclomine	2000
	Cap. Fluextine	3000
	Cap. Vitazyme	2000
	Antacid Gel	200 bottles
	Cortula M.Eye Drops	100
	Dermoquinol	100 tubes
	Antifungal ear drops	100
	Hand Dusters	50
	Keralin Oint.	100 T
	Syp. Nemuslide	100 bottles
	Otec-AC ear drops	100
	Pyricort Eye drops	200
	Sodium Fussidate	100 T
	Tab. Maxeron MPS	1500
	Tab. Tinidazole	1000
	X-Ray Film 12" x 15"	5 pkts x 50 film
	X-Ray Films 8" x 10"	8 pkts x 50 film
10-1-2001	Inj. ARV 30 ml	100 vials
	Inj. Cefazoline	250 vials
	Gauge Surgical	10 Than
	Cap. Amoxycillin	1000
	Inj. Amikasyn	270 vials

[डा0 एम0 एल0 रंगा]

सप्लाई की तिथि	दवाई का नाम	सप्लाई की मात्रा
	Tab. Colsprin 100 mi	5600
	Cap. Cloxacillin 500 mg	1000
	Inj. Promethazine	100
	IV sets	248

उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धापन कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा दवाइयों की आपूर्ति की गई।

Construction of Railway Overbridge

27. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Railway Overbridge (ROB) in the State and particularly on Palwal Aligarh Road on built operate transfer (BOT) basis in near future; if so, the lists thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : निकट भविष्य में पलवल-अलीगढ़ सड़क पर रेलवे उपरि पुल निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण (बी0 ओ0 टी0) प्रणाली के आधार पर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। निकट भविष्य में निम्नलिखित उपरि पुल निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण प्रणाली के आधार पर निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं :--

(1) कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त दो मार्गीय रेलवे उपरि पुल।

(2) रिवाड़ी में रिवाड़ी-नारनौल सड़क पर रेलवे उपरि पुल।

Foreign Tour Undertaken by Minister/Officer

28. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether any Minister/Officer of the Animal Husbandry Department in the State undertook foreign tour during the year 2000-2001 ; if so, the name of such Minister/Officer togetherwith the details of the expenditure incurred thereon ?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी मोहम्मद इलियास) : जी हां, श्रीमान। वर्ष 2000-2001 के दौरान जिन मन्त्री/अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा की गई, की सूचि नीचे दी जाती है :--

ग्रुप-1 (20-6-2000 से 9-7-2000)

1. चौ0 मोहम्मद इलियास, राज्य मन्त्री, पशुपालन, हरियाणा।
2. श्रीमती वीना ईगलटन, आई0 ए0 एस0, वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन विभाग।
3. डा0 के0 एस0 दांगी, निदेशक पशुपालन विभाग, हरियाणा।

4. डा0 गुलाब राय चौधरी, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, हरियाणा।

5. डा0 विरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा।

यह ग्रुप कैनेडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के देशों में स्टडी टूर पर गया था।

ग्रुप-2 (3-9-2000 से 24-9-2000)

1. डा0 एस0 के0 खुराना, उप-निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा।

2. डा0 अनूप सिंह, पशु चिकित्सक।

3. डा0 एन0 के0 खुराना, पशु चिकित्सक।

4. डा0 हरबीर सिंह राठी, पशु चिकित्सक।

5. डा0 राम प्रताप, पशु चिकित्सक।

यह ग्रुप इजराईल, डैनमार्क तथा नीदरलैंड के देशों में स्टडी टूर पर गया था।

इन दोनों ग्रुपों द्वारा विदेश यात्रा विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित मानव संसाधन विकास परियोजना के अन्तर्गत की गई। इसका समस्त व्याय खादय एवं कृषि संगठन (एफ0 ए0 ओ0) द्वारा वहन किया गया था जिसका पूर्ण विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य, श्री जगजीत सिंह सांगवान और रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष : आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपकी कोई भी मोशन हमारे पास नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के मैम्बर का तो है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, जिनका मोशन आया है वे तो अपनी सीट छोड़ कर आगे आ गए हैं। आपका कोई मोशन नहीं है और आप बोल रहे हैं। इनको अगर ऐसे ही करना है तो ये मेरे चैम्बर में आ जाएं वहां पर बात कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान) जिनका मोशन आया है उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित है। उस पर आप अपनी रूलिंग दें। (शोर एवं व्यवधान) * * * * * * *

(इस समय डा0 रघुबीर सिंह कादयान अगली सीटों की ओर आ गए)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कादयान जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, देश की रक्षा का मामला है। (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मेरे पास रघुबीर सिंह जी का नोटिस आया है। आप उस बारे में मेरी रूलिंग सुनें। (शोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनका मोशन आया है आप पहले इनको बिठाएं और फिर अपनी रूलिंग दें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से लीडर आफ दि हाउस किसी भी मामले में बीच में ही इन्टरवीन कर सकता है उसी तरह से मैं भी लीडर आफ दि अपोजिशन हूं मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपका कोई मोशन नहीं है आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आप इन सबको बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आपकी बात भी सुन ली जाएगी। पहले आप स्पीकर साहब की रूलिंग आने दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice for adjournment of the Business of the Assembly under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly concerning the security of the country from Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A. today in the morning. I have gone through the notice and the relevant Rules etc. in this regard. After going through the notice, I have found that the matter proposed to be discussed is not in order as the same does not fall within the responsibility of the State Government as provided under Rule 68(iv) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly. Therefore, I refuse to give my consent to raise/ discuss this matter in this august House.

चौधरी भजन लाल : ऐसा आप ठीक नहीं कर रहे हैं।

डा0 रघुवीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, यह बहुत ही सीरियस मामला है क्योंकि यह देश की सुरक्षा से संबंधित है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप अपनी सीट पर बैठें (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप इनको कुछ पाठ पढ़ाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की तो प्रसन्नता है कि चौधरी भजन लाल जी और हुड्डा साहब एक माननीय साथी को काबू करने में तो इकट्ठा हैं लेकिन मुझे कादयान साहब को भी दाद देनी होगी कि इन दोनों के जोर मारने के बावजूद भी वे अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए आपसे भी और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से खासतौर से एक बात कहना चाहूंगा कि जब अध्यक्ष की रूलिंग एक

बार आ गयी तो फिर उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप उनकी रूलिंग को नहीं मानते हैं तो फिर उनका उस कुर्सी पर बैठने का क्या औचित्य रह जाता है ? भजन लाल जी, आप मुझे एक बात बताओ कि आया आप अध्यक्ष की बात को मानते हैं या नहीं ?

चौधरी भजन लाल : मानते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अगर उनकी बात को मानते हैं तो जब उन्होंने एक बार फैसला दे दिया तो फिर उसी बात पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : अब जो भजन लाल जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने कहा कि हमें आपकी मर्यादा रखनी चाहिए लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको हमारी बात भी सुननी तो चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके ही मैम्बर ने कहा था कि मैं उनके ऐडजर्नमैंट मोशन के बारे में अपनी रूलिंग दूं इसलिए मैंने तो उनके कहने पर ही अपनी रूलिंग दी है। अब आप किस बात पर बोल रहे हैं ? इसलिए अब आप बैठें।

वाक आउट

चौधरी भजन लाल : अगर आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो हम इसके विरोध में वाक आउट करेंगे फिर आप क्या करेंगे ? अगर आप बोलने ही नहीं देते हो तो।

श्री अध्यक्ष : वाक आउट करना आपका अधिकार है।

चौधरी भजन लाल : चूंकि आप हमें बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए हम एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्य एवं नैशनेलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी भी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल, आप बैठ जाएं। आप अपनी सीट पर बैठें। हिन्दुस्तान का जिक्र दिल्ली में होगा। यहां नहीं होगा। यह मामला केन्द्रीय सरकार से संबंधित है और यह स्टेट का सब्जैक्ट नहीं है इसलिए इसे रिफ्यूज कर दिया गया है आप बैठ जाइए। (विघ्न)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री नियम 121 के अधीन प्रस्ताव मूव करेंगे।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

> That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—
>
> (i) Committee on Public Accounts ;
>
> (ii) Committee on Estimates ;
>
> (iii) Committee on Public Undertakings ; and
>
> (iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes

for the year 2001-2002 be suspended.

Sir, I also beg to move—

> That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2001-2002, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion Moved—

> That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—
>
> (i) Committee on Public Accounts ;
>
> (ii) Committee on Estimates ;
>
> (iii) Committee on Public Undertakings ; and
>
> (iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes

for the year 2001-2002 be suspended.

And

> That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2001-2002, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes

for the year 2001-2002 be suspended.

And

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2001-2002, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल, आप बैठ जाएं। आप अपनी सीट पर बैठें। हिन्दुस्तान का जिक्र दिल्ली में होगा। यहां नहीं होगा। यह मामला केन्द्रीय सरकार से संबंधित है और स्टेट का सब्जैक्ट नहीं है इसलिए इसे रिफ्यूज कर दिया है आप बैठ जाइए। (विघ्न)

समितियों की रिपोर्ट्स पेश करना

(i) पब्लिक अकाऊंट्स कमेटी की 49वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Shri Bhagi Ram, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Forty Ninth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2000-2001, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the years 1995-96 and 1996-97.

श्री भागी राम (चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखों/वित्त लेखों पर वर्ष 2000-2001 के लिए लोक लेखा समिति की 49वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(ii) अधीनस्थ विधान समिति की 31वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Vaid Kapoor Chand, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirty First Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2000-2001.

वैद कपूर चन्द शर्मा (चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 31वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(श्री कर्ण सिंह दलाल बोलते हुए सदन से बाहर जाने लगे।)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल, आपको वहां से खड़े होकर बोलने का अधिकार नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जाते जाते कह दिया।

श्री अध्यक्ष : क्यों कह दिया, जाते जाते कैसे कह दिया। ये कोई तरीका नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपकी पेशंस की दाद देनी पड़ेगी। कुछ लोगों को अखबार में अपनी खबर छपवाने का चाव होता है लेकिन सदन आपके पेशंस की सराहना करेगा कि आपने सबको खुलकर अपनी बात कहने का अवसर दिया है उसके बावजूद भी ये सीमाएं यहां तक लांघ जाएं। चौधरी भजन लाल जी, इस सदन की एक गरिमा है क्या यह कोई तरीका है और आप ऐसे लोगों की सिफारिश करते हो। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा मैंबर जो इस सदन का पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रहा हो और जिसने सारी सीमाएं ताक पर रख दी हों। क्या वह आज अपनी सीट से उठकर वहां जाकर कुछ कह सकता है ? फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि आपने इस सदन की गरिमा को बहुत बरकरार रखा और मैं आपकी पेशंस की दाद देता हूं। कई इस किस्म के लोग हैं जिनको अपनी खबर छपवाने का चाव है और निष्कासित होने का चाव हो रहा है। एक अकेला बेचारा कहीं से आ गया रुलता खुलता।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल, आप अपना आचरण सुधारें और अपनी सीट पर बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सपलेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : इसमें पर्सनल ऐक्सपलेनेशन की कोई बात नहीं है, आप बैठ जाएं।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : सदस्यगण, अब बजट पर सामान्य चर्चा होगी। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के आदेश दिये उन आदेशों का निर्वहन करते हुए मैं अपनी भावना जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। खासतौर से सदन के नेता से मैं ऐसी आशा रखता हूं कि देश की सुरक्षा संबंधित मामले की ओर ध्यान देंगे क्योंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं जिनके पिता जी और ताऊ जी देश की आजादी के लिए जेलों में रहे। आज देश की सुरक्षा को खतरा है इसके लिये हमें चिंतित होना चाहिये। आपने मेरा एडजर्न मोशन तो अलाऊ नहीं किया लेकिन मैं इस चर्चा के द्वारा अपनी चिंता जरूर व्यक्त करना चाहूंगा और मुझे आशा है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप इसके बारे में रूलिंग का जिक्र न करें वैसे भी आप रूल्ज कमेटी के सदस्य हैं और आपको रूल्ज की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आज बजट पर डिसकशन हो रही है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले साल का बजट पेश किया था और इस साल का बजट भी पेश किया है। मैं उनके द्वारा बजट पेश करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिये बधाई देता हूं। पिछले साल भी उन्होंने टैक्स फ्री बजट इस सदन में पेश किया था लेकिन जब तक हम अपने घर तक पहुंचे तो एक के बाद एक टैक्स लगाना इस सरकार ने शुरु कर दिया था। इस साल फिर वित्त मंत्री महोदय ने टैक्स फ्री बजट इस सदन में पेश किया है। मैं इनकी इस बात को समझ नहीं पाया कि इन्होंने जो पिछले साल टैक्स लगाये थे वे सारे टैक्स माफ कर दिये या आगे कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। इस प्रकार का आश्वासन इन्होंने नहीं दिया। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बड़े सम्मानित सदस्य हैं। पार्लियामेंट में भी कई मर्तबा रहे हैं। यह बात अलग है कि वहां पर इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। लेकिन इनको इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि बजट अधिवेशन साल में एक मर्तबा आता है जिसमें पूरे साल का लेखा-जोखा होता है। बजट अधिवेशन में ठेकेदारी का सौदा नहीं हुआ करता जो पांच साल के लिये होता है। इस बात के लिए इतनी लम्बी चौड़ी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है (विघ्न) कि अब आगे के लिये आश्वासन दिया जाये। बजट अधिवेशन में आश्वासन नहीं हुआ करता है। बजट अधिवेशन में पूरे साल का लेखा-जोखा होता है कि हमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या अर्जित किया, कहां खर्च करेंगे इस बात का सारा विवरण बजट में पेश किया जाता है। माननीय सदस्य के पास सारा विवरण मौजूद है उन्होंने उसको पढ़ा तो है नहीं, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बातें पहले भी दो तीन दफा कही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उम्र में हम से बड़े हैं हम इनका सम्मान करते हैं। मैं पार्लियामेंट का जितने साल तक सदस्य रहा हूं ये उतने साल की लोक सभा की प्रोसिडिंग्ज मंगवा कर देखें और उसके बाद यह बात सदन में रखें तो अच्छा रहेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ओथ सेरेमनी तो है उस कार्यवाही में फालतू कुछ नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसमें दो फण्डज का प्रावधान रखा है। एक तो सिंकिंग फण्ड है जो सडन डैफिसिट होता है या सर्विस कंटींजेंसी होती है उसको मीट आउट करता है। दूसरा फण्ड है स्टेट इकोनोमिक रिन्यूअल फण्ड जो ऐस्केलेशन मैयर के बारे में है इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। लेकिन इस बजट में यह कहीं पर भी नहीं बताया गया कि इन दोनों फण्डज के बारे में पैसा कहां से आयेगा और इनमें कितना पैसा रखेंगे। ऐसी बात मैं पहली दफा देख रहा हूं कि किसी फण्ड की चर्चा की जाये और उस फण्ड को कहां से रेज करेंगे इस बारे में कोई बात नहीं की जाये। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कृपा करके इस बात को हमें समझाया जाये। क्योंकि पहले ही डैफिसिट 55 करोड़ रुपये का इस साल है और कुल मिलाकर 789 करोड़ रुपये डैफिसिट में हैं। अभी तक केन्द्र ने गेहूं के बारे में एम0 एस0 पी0 डिक्लेयर नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर केन्द्र गेहूं की एम0 एस0 पी0 नहीं बढ़ाता है तो हम किसानों को गेहूं की सिम्बोलिक प्राइस मिनिमम

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

20 रुपये प्रति क्विंटल कम से कम देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अखबार के आंकड़े बता रहा हूं आज के अखबार के एडीटोरियल में भी आया है कि 20 रुपये सिम्बोलिक देंगे क्योंकि उससे कम देने का कोई लाभ नहीं होगा। वह पैसा यह सरकार कहां से लाएगी, इस का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर व्हीट बोनस देना पड़ेगा तो ये उसके लिए फण्ड्ज कहां से रेज करेंगे। पिछले बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपये दिया था तो प्लान डाउन साइज हुआ था, अब की बार यह और डाउन साइज होगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल तनख्वाहों में 467 करोड़ रुपये बढ़े हैं और इन्ट्रस्ट के 260 करोड़ रुपये बढ़े हैं, इसके लिए फण्ड कहां से आएंगे। व्हीट बोनस अनाउंस कर दिया गया इसके लिए पैसा ये कहां से लाएंगे बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। जब बजट आंका जाता है तो देखना पड़ता है कि इससे आम आदमी को क्या राहत मिलेगी, किसान को क्या राहत मिलेगी, बेरोजगार नौजवानों के लिए इसमें क्या प्रावधान है, यही तरीका बजट आंकने का होता है लेकिन आज हर वर्ग पर मार पड़ रही है (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद अब तक 7 दफा बिजली के रेट बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक बिजली कनैक्शन का फ्लैट रेट 1100 रुपये कर दिया गया और मीटर की सिक्योरिटी 2000 रुपये कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रान्त में 4 एकड़ जमीन पर एक टयूबवैल की एवरेज है। आज एक टयूबवैल पर बिजली का मौजूदा रेट जहां साढ़े सात हॉर्स पावर की मोटर लगती है, साल का खर्च 12000 रुपये पड़ता है जिसमें 9000 रुपये बिजली के हैं और 3000 रुपये रख-रखाव के हैं।

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी हुड्डा जी ने यह कहा है कि हरियाणा प्रान्त में 4 एकड़ जमीन पर एक टयूबवैल की ऐवरेज है, यह सरासर गलत है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो बता देंगे, वह मैं मान लूंगा। 4 एकड़ जमीन पर एक टयूबवैल की ऐवरेज है और अगर मैं गलत हूं तो ये बता दें, मैं मान लूंगा।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : उपाध्यक्ष महोदय, हम इनको यह बाद में बता देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे ज्ञान है 4 एकड़ जमीन पर एक टयूबवैल की ऐवरेज होती है और एक टयूबवैल पर बिजली का खर्चा आज के रेट के हिसाब से 12000 रुपये सालाना पड़ता है अगर उस टयूबवैल पर साढ़े सात हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। (शोर)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हुड्डा जी ने विशेष तौर से कहा कि कांग्रेस रिजाइम के बाद सात बार बिजली के रेट बढ़े हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के वक्त में किस तरह से बिजली के रेट बढ़े हैं। कांग्रेस की सरकार में 1992 से 1994 तक दो सालों में बिजली के रेट तीन बार बढ़े हैं। 5-6-1992 को बिजली के रेट 10 प्रतिशत बढ़े हैं। 1-2-94 को 12 प्रतिशत, 28-12-94 को 30 प्रतिशत, 16-8-91 से लेकर 1-4-96 तक 14 प्रतिशत फ्यूल चार्जिज बढ़े हैं। इसलिए ये स्थिति को क्लीयर नहीं कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से मना नहीं करता कि कांग्रेस की सरकार के समय में बिजली के रेट नहीं बढ़े, कांग्रेस के समय में भी बिजली के रेट बढ़े हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जब इनकी पार्टी ने लोगों को कहा कि बिल मत भरो तो फिर ये किस मुंह से बिल मांग रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, किसान के ऊपर चोरी के जो केस बनते हैं उसके चार्जिज 4000 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से लिए जाते हैं और जो इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स हैं उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो उनसे 400 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से चार्जिज लिये जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स से 400 रुपये प्रति हॉर्स पावर और किसान से 4000 रुपये प्रति हॉर्स पावर चोरी के केसिज में पैनल्टी लगाई जाती है यानि किसान को 10 गुणा ज्यादा पैनल्टी लगाई जाती है, यह बहुत गलत बात है। इस तरह अपने आपको किसानों की हितैषी कहने वाली सरकार किसानों के साथ ही बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोगों ने बिल इसलिए नहीं भरे क्योंकि मेरे सत्तापक्ष के भाई ही कहते थे कि बिल मत भरो जब हमारी सरकार आयेगी तब बिजली, पानी हम मुफ्त कर देंगे।

श्री दलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे माननीय साथी हुड्डा साहब से पूछना चाहूंगा कि बिजली पानी मुफ्त देने की बात पहले हुड्डा साहब ने कही थी या हमने ? अखबारों में इनकी स्टेटमैंट आती थी और बिजली पानी मुफ्त का नारा इन्होंने दिया था और चौटाला साहब ने इनका नारा चोरी कर लिया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जो बात मैंने कही थी उसको मैं मानता हूं और अब भी कहता हूं कि जब पंजाब सरकार अपने किसानों को बिजली पानी मुफ्त दे सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं दे सकती। हरियाणा और पंजाब दोनों एक प्रदेश रहे हैं और यहां के किसान पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूं। पंजाब के अंदर किसानों को बिजली मुफ्त मिलती है वहां पर प्रधान मंत्री जी किसानों को सबसिडी दे रहे हैं जबकि हरियाणा के अंदर किसानों के बिजली के दाम भी बढ़ाये जा रहे हैं यह कहां का न्याय हरियाणा के किसानों के साथ हो रहा है। बिजली के रेट बढ़ने के कारण हरियाणा के किसानों को प्रति एकड़ धान की फसल में 2500 रुपये कम आमदनी हुई है। इस तरह हरियाणा के किसान का मनोबल कैसे ऊपर उठेगा ? हमारे वित्तमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने कहा कि किसानों को गन्ने का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया है और यह मूल्य पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने किसान को गन्ने का भाव 104 रुपये व 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया है। फिर हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा भाव कैसे दिया या तो बादल साहब झूठ बोल रहे हैं या हमारी सरकार। उपाध्यक्ष महोदय,घरेलू बिजली भी आज के दिन बहुत ज्यादा मंहगी पड़ रही है। जो आदमी एक बल्ब जलाता है उसके कनैक्शन को भी 2 किलोवाट से कम नहीं माना जायेगा यानि एक बल्ब जलाने वाले गरीब आदमी को भी हर दो महीने में 440 रुपये बिजली का बिल भरना पड़ेगा। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस सदन की जो ऊपर की लॉबी है, साईड की लॉबी है इनमें आफिसर्ज बैठे हैं और ये आफिसर्ज चण्डीगढ़, मोहाली और पंचकूला में रह रहे हैं। जो आफिसर पंचकूला में रह रहा है उसे चण्डीगढ़ और मोहाली में रहने वाले आफिसर की बजाय बिजली का बिल प्रति यूनिट 1.50 रुपये ज्यादा देना पड़ता है। यह मैं घरेलू बिजली की बात कर रहा हूं। जहां तक ट्रेडर्स और दुकानदारों की बात है इनके ऊपर भी कई कर

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

पीछे लगाये गये थे जैसे सर्फेस टैक्स के नाम से, एस0 टी0 38 के नाम से, लोकल एरिया डिवैल्पमैंट के नाम से, सैनीटेशन के नाम से, फायर टैक्स के नाम से और कहीं प्रोफैशनल के नाम से कई टैक्स वित्तमंत्री जी ने लगाये। मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था। हम तो पिछली दफा 11.00 बजे यहां पहुंचे थे नहीं लेकिन इन्होंने एक के बाद एक करके टैक्स लगाये जब कि लोगों को कोई फैसिलिटीज़ इन्होंने नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में इण्डस्ट्रीज की क्या हालत है। जिंदल साहब भी कल चर्चा कर रहे थे और खास तौर पर अच्छी इण्डस्ट्रीज की बात है जो ईमानदारी से टैक्स देती हैं, ऐक्साइज ड्यूटी पूरी देती हैं उनके ऊपर भी और टैक्स लगा दिये। अगर सारे टैक्स का हिसाब लगायें तो इण्डस्ट्री को 25 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ेगा। आज ये वाहवाही लूट रहे हैं तो जरा बतायें तो सही कि कौन सा इण्डस्ट्रीलिस्ट कमा रहा है। केवल वही इण्डस्ट्रीलिस्टस कमा रहे हैं जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं वे तो यहां से पलायन करने की बात सोच रहे हैं क्योंकि यहां पर वे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने 4 प्रतिशत लोकल एरिया डिवैलपमैन्ट चार्जिज लगाये हैं। यह आमदनी भी लोकल एरिया को नहीं जाएगी। यह स्टेट के पूल को जाएगी। अगर वे लोग चार परसैंट लोकल एरिया डिवैलपमैन्ट चार्जिज देंगे तो फिर अपने पड़ौसी राज्यों के उद्योगों के साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इनसे कैसे कम्पीट करेंगे। यहां से इण्डस्ट्रीज उठ कर जाएंगी तो हमारे यहां जो बेरोजगारी नौजवानों में बढ़ रही है उसका क्या होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री कृष्ण पाल गुज्जर को बधाई देता हूं कि उन्होंने विजीलैंस के सम्बन्ध में एक बढ़िया बात कही है। सारा का सारा सरकारी अमला अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्यवाही करने में लगा हुआ है चाहे वो आनंद सिंह डांगी के खिलाफ हो, चाहे तेजेन्द्र पाल मान के खिलाफ हो चाहे श्री जगबीर सिंह मलिक के खिलाफ हो। ऐसे कितने और साथियों के नाम लिखवाऊं। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने में लगे।

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी एक सबमिशन है कि जो इनकी पार्टी के साथी है जिसमें पूर्व राजस्व मंत्री भी है वे चूंकि हाउस में नहीं आ सकते इसलिये हुड्डा साहब उनके नाम न लें। यह हाउस की परम्परा रही है। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। (विघ्न) श्री जगबीर सिंह मलिक तो मेरी पार्टी के नहीं हैं। श्री कर्ण सिंह दलाल जो कि यहां पर विधायक हैं मैं उनका नाम लेकर कहता हूं कि इनके परिवार के खिलाफ भी राजनीतिक कारणों से इन्क्वायरी हो रही है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है क्योंकि हुड्डा साहब ने मेरा नाम लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अगर चाहे तो मेरे खिलाफ विजीलैंस इन्क्वायरी कर सकती है। लेकिन हुड्डा साहब की यह बात सही है कि यह सब राजनीतिक विरोध की वजह से किया जा रहा है। (विघ्न) यह भी सही है कि श्री धीरपाल सिंह और श्री सम्पत सिंह जी के खिलाफ भी ऐसा हो रहा है। इनके खिलाफ चोरी-छिपे हो रहा है और हमारे खिलाफ सरेआम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, वाइंड अप करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरी बातें शुरू हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप जल्दी खत्म करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे समय बता दें कि कितने समय में अपनी बात कह सकता हूं ताकि मैं उसी हिसाब से बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा जी, आपको सात मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैने इन्डस्ट्रीज के बारे में तो बता दिया है। अब हाउस टैक्स की बात आती है। हाउस टैक्स का मामला भी बड़ा गंभीर है। आज जिस हिसाब से हाउस टैक्स लगाने की योजना बनने जा रही है, इससे हर व्यक्ति को पांच से दस गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के भाव बढ़ा दिये, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, इसके अलावा एक और बात माईन्स की है, जिसके संबंध में पूरी डिटेल में तो इन्होंने भी नहीं बताया है। माईन्स के द्वार स्टेट को काफी आमदनी होती है और जोकि स्टेट की आमदनी का मुख्य जरिया था। इससे भी प्रदेश की आमदनी किस प्रकार से घट रही है, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग भरत के लिये खेतों से मिट्टी ले जाते थे उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद सांस लेने पर भी टैक्स लग जाएगा जबकि ये कहते हैं कि कर रहित बजट दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एस0 वाई0 एल0 की बात आती है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने अपने भाषण में चर्चा की है लेकिन वित्त मंत्री जी ने एस0 वाई0 एल0 पर कोई चर्चा नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, एस0 वाई0 एल0 सबसे गंभीर विषय है कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आये थे। हमारे को उनसे उम्मीदें थी कि वे पंजाब की तरह हरियाणा के लोगों को भी पैकेज डील देकर जाएंगे। किसानों को धान की फसल में मार पड़ी थी इसलिये किसान जो आगे गेहूं पैदा करके देगा उसके लिये पंजाब की तरह हरियाणा के किसानों को भी प्रधानमंत्री जी पैकेज डील देकर जाएं, वे तो एस0 वाई0 एल0 के बारे में भी यह कह गये कि बैठकर चर्चा कर लें और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कह दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस तरह से कह करके सरकार ने इस मामले को लटकाने की कोशिश की है। यह बात ठीक है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें यदि इस सरकार को हमारे समर्थन की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है तो मैं सदन के नेता से कहूंगा कि जहां पर भी हरियाणा के हितों का सवाल होगा वहां पर हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। अगर हरियाणा के हितों के लिए कहीं पर रास्ता रोकना है या कहीं और कुछ करना है, हरियाणा के हितों के लिए कोई लड़ाई लड़नी है तो हम आपका पूरा सहयोग देंगे। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगा कर इस मामले को लटकाने की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से बाहर बैठ कर हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल एस0 वाई0 एल0 नहर के बारे में कोई समझौता करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको न माने। हमारे माननीय साथी श्री बलबीर सिंह बाली ने कल चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान किसानों का क्या-क्या भला किया। मैं उनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के ही शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और वह श्रीमति इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान किया गया था। ऐसा करके उन्होंने देश के किसानों को बैंकों का रास्ता दिखाया था।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसके साथ साथ उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइवेटाईजेशन की शुरूआत भी की थी आप इस बात का भी ध्यान रखें क्योंकि आपकी गलत नीतियों के कारण ही किसानों को मार पड़ती रही। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियां सही तरीके से चलती तो आज देश का किसान सबसे ऊपर होता लेकिन आपकी पार्टी की गलत नीतियों ने देश के किसानों को मार दिया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने डब्ल्यू0 टी0 ओ0 की चर्चा की। (शोर) कहीं कोई प्राइवेटाईजेशन नहीं हुई सब बैंक नैशनेलाइज्ड हैं।

श्री बलबीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठें माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बलबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में मेरा नाम लेकर चर्चा की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1991 से लेकर 1996 तक केन्द्र में आपकी पार्टी की सरकार रही, पंजाब में भी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और हरियाणा में भी उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हमारे बड़े भाई माननीय सदस्य हुड्डा साहब उस समय पार्लियामैंट के मैम्बर थे तो उन पांच साल के दौरान आपने एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय क्या कार्यवाही की वह मैं लोगों को बताऊंगा और प्रदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ था और एस0वाई0एल0 कैनाल की खुदाई पर जो 700 करोड़ रुपए लगे थे वह कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही लगे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डब्ल्यू0 टी0 ओ0 के बारे में बताना चाहूंगा। डब्ल्यू0 टी0 ओ0 के कारण पूरे देश के किसानों के दिलों में दर्द पैदा हुआ है और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान 1950 में डब्ल्यू0 टी0 ओ0 का मैम्बर बना था। डब्ल्यू0 टी0 ओ0 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि खाद पर सबसिडी कम कर दी जाए। अमेरिका खुद दस हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से अपने किसानों को सबसिडी दे रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आप अनाज इम्पोर्ट करेंगे उस पर जो आपकी दो सौ तीन सौ परसैंट तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की वे ऑप्शंज हैं वे ऑप्शंज आप न करें। यहां तो आपने 50 से 70 परसैंट तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू0 टी0 ओ0 एक अप्रैल से लागू होगा लेकिन क्या क्या इम्पोर्ट हो चुका है, इन्होंने 14 लाख टन मक्का इम्पोर्ट किया जिसकी वजह से हिन्दुस्तान के किसानों को मक्का का अढ़ाई सौ रुपये से फालतू प्रति क्विंटल का भाव नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका की सरकार दिल्ली की सरकार को डिक्टेट कर रही है और दिल्ली की सरकार वह नीति अपना रही है। मलेशिया से अढ़ाई करोड़ टन सोयाबीन का तेल मंगवाया जिसकी वजह से हमारे किसानों को उनकी सरसों का भाव पूरा नहीं मिल सका जबकि वह आयल वैस्टर्न कंट्रीज रिजैक्ट कर चुकी थी, उसको हिन्दुस्तान की सरकार ने इम्पोर्ट किया। डिप्टी स्पीकर साहब, इस प्रकार से 33 लाख टन अनाज इम्पोर्ट किया गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि जिन किसान भाईयों ने अपना अनाज

बेचा नहीं था और अपने पास स्टोर करके रख लिया था यदि आज वे उसे बेचने के लिए मण्डी में जाते हैं तो उनको अपने गेहूं का मूल्य आज के दिन 400-450 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं मिल पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपने इम्पोर्ट के तो आंकड़े बता दिये। आप साथ ही एक्सपोर्ट के भी आंकड़े बता दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : यदि सरकार अनाज इम्पोर्ट न करती तो किसानों का नुकसान नहीं होता। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप अनाज, तिलहन आदि की बात करके आंकड़े दे रहे हैं कि इतना अनाज इम्पोर्ट किया गया है आप एक्सपोर्ट के आंकड़े भी बता दें। (विघ्न)

श्री कंवर पाल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, ये यहां पर कह रहे थे कि सरकार ने खाद पर सबसिडी कम कर दी। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि खाद पर सबसिडी सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने घटाने की शुरूआत की थी। बाहर से अनाज मंगाये जाने पर भी जो डंकल एग्रीमेंट हुआ था वह भी कांग्रेस सरकार के वक्त में ही हुआ था। अब जो डब्ल्यू0 टी0 ओ0 का समझौता हुआ है उसके तहत तो खपत का 6 परसेन्ट अनाज बाहर से मंगवाना पड़ेगा। ऐसे समझौते आपकी सरकार के समय में हुए थे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया कि ऐसे एग्रीमेंट कांग्रेस सरकार ने किये थे। मैं बताना चाहूंगा कि जो डब्ल्यू0 टी0 ओ0 का समझौता है उसमें किसानों को फायदा देने का भी प्रोविजन है। यदि हमें लगता है कि डब्ल्यू0 टी0 ओ0 से हमें नुकसान हो रहा है तो उसमें एक क्लाज सभी देशों के लिए रखी गई है कि वह छः महीने का नोटिस देकर इस डब्ल्यू0 टी0 ओ0 के समझौते से बाहर हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हमें उस का सदस्य बने रहना ही होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यदि ऐसा अनाज बाहर से किसी देश का आता है तो उस पर भारत सरकार 200-300 गुणा टैक्स लगा सकती है जिससे वे यहां पर न लेकर आये और वह अनाज भी हमारे जितना महंगा हो। जब उसके रेट्स भी हमारे जितने होंगे तो फिर हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। (विघ्न) उसका सदस्य बने रहना हमारा या किसी देश का जरूरी नहीं है। उसमें सभी को ऑप्शन दी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी खत्म करें।

श्री भजन लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। हुड्डा साहब, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये गवर्नर एड्रैस पर भी नहीं बोले थे। अब ये इस बजट पर पहली दफा बोल रहे हैं इसलिए इनको अपनी पूरा बात कह लेने दें और जितना समय ये लें उनको आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, जो जो आपने नाम दिये थे, उन सब को हमने बोलने का पूरा मौका दिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने जो गवर्नर ऐड्रैस पेश किया था उसके बाद इस बजट को पेश करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमें और गवर्नर एड्रैस में कोई खास फर्क नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जो गवर्नर एड्रैस था वह इस बजट से कहीं अधिक अच्छा था। जैसे गवर्नर एड्रैस में फौरैस्ट्री का जिक्र था लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। मैंने

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

यमुना नगर में देखा है कि फौरेस्ट्री के तहत वहां पर लोगों ने पापुलर और सफेदे की खेती की है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इनकी कीमत फिक्स करनी चाहिए क्योंकि जब किसान लोग अपने इन पेड़ों को बेचने के लिए मंडी में जाते हैं तो उसकी कीमत घटा दी जाती है और जब किसानों की तरफ से ये पेड़ मार्किट में आ जाते हैं तो बाद में इनकी कीमत बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि किसानों के हित को देखते हुए इस फसल की भी कीमत फिक्स की जाये ताकि किसानों को नुकसान न हो। सरकार ने एग्रीकल्चर की यील्ड के लिए तीन प्वायंट कुछ परसेंट पैसा बजट में रखा है, मेरी सरकार से मांग है कि इसके लिए भी पैसे को बढ़ाया जाये। सरकार का कर्जा पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। (विघ्न) पैसे का तो सिर्फ आवा-गावा ही हो गया है। लोगों के विकास की बात हो, लोगों के हितों की बात हो, या इन्फ्रास्ट्रचर की बात हो उसके लिए कोई पैसा बजट में नहीं रखा गया। जो पैसा रह गया है वह लोन की री पेमेंट का और अपने इम्प्लौयीज को पे देने का है। यहां पर कहा गया कि सरकारी नौकरी में नई भर्ती में कमी की जायेगी। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि सरकार छोटे स्तर पर यानी नीचे के लैवल पर तो इन पदों में कटौती कर रही है लेकिन बड़े स्तर पर यानी आई0 ए0 एस0 व आई0 पी0 एस0 स्तर पर कोई कमी नहीं कर रही। जबकि हमारे यहां पर पहले ही इन पदों की संख्या कहीं अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' जो कार्यक्रम चलाया था उसके काम करने के लिए पहले फेज में तो कुछ पैसा बंसी लाल जी छोड़ कर गए थे और कुछ पैसा एच0 आर0 डी0 एफ0 का था। जैसे इन्होंने ब्यान दिया है कि जब चाहे उस पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन वह इस्तेमाल हुआ नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सैकण्ड फेज में मुख्य मन्त्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया है उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है और सारा पैसा डिसैंट्रेलाईज करके खर्च किया जा रहा है तथा इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही कोई स्कीम इसके लिए बनाई गई है। ऐसा तो मैंने केवल आपके बजट में ही देखा है कि बिना बजट में प्रावधान किये कोई स्कीम चलाई जा रही है। जो बजट पेश किया गया है वह आंकड़ों के हिसाब से यह बिल्कुल बेमानी है और केवल सरकारी तनख्वाहों का बजट है इसमें विकास का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह बजट लोकहित में नहीं है केवल सैलरी बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस जनविरोधी बजट का डट कर विरोध करता हूं और आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान सभा में माननीय वित्तमंत्री महोदय ने वर्ष 2001-2002 का बजट अनुमान पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिसला साहब, आप अपनी स्पीच में समय का ध्यान रखें (विघ्न) आप अपनी समय सीमा में ही रहें। आपको बोलने के लिए 15 मिनट का समय अलॉट किया गया है इसलिए आप समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने समय से एक मिनट पहले ही बैठ जाऊंगा। इस हाऊस में निर्दलीय विधायकों की संख्या बहुत बड़ी है और हम लोग अपना अस्तित्व रखते हैं। इस विधान सभा में हम ही असली आदमी हैं जो चुन कर आए हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष

महोदय, समाज के सभी वर्गों की तरफ से इस बजट की सराहना की गई है। आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का आह्वान है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई मैम्बर चेयर की अनुमति से बोलता है तो कम से कम उस समय शांति का माहौल होना चाहिए, यह मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। जैसे कि मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्य मन्त्री जी ने सारे हरियाणा प्रदेश का आह्वान किया है कि आप सारे मिल कर इस हरियाणा प्रदेश को चहुमुखी विकास के पथ पर ले चलें और उसी आह्वान की रिफलैक्शन में इस प्रदेश के सभी वर्गों का चहुमुखी विकास होना है। उसी आह्वान की ओर देखते हुए ही यह बजट तैयार किया गया है जिसके लिए आदरणीय मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह समय समाज में नयी टैक्नोलोजी और नई विचारधारा का है यह बजट उस धारणा का आधार है। आम आदमी की धारणा है कि बजट में कर जरूर लगेंगे। यह कहां लिखा हुआ है कि बजट में कर जरूर लगेंगे, क्या कहीं संविधान में यह लिखा हुआ है या किसी किताब में मैंशन किया गया है कि बजट में कर जरूर लगने चाहिएं। यह बहुत ही अच्छी शुरूआत है और इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार ने यह बजट कर रहित पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी के दिन हम सब देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट का दिन था। भयानक भूकम्प से हज़ारों देशवासी गुजरात में मौत का शिकार हो गये और वहां लाखों घर उजड़ गये। इस प्राकृतिक आपदा को सारे देशवासियों ने एक हो कर उससे निपटने का प्रयास किया है और उसमें हरियाणा सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उपाध्यक्ष महोदय, भुज जिला में रापड़ तालुका में 19 क्षतिग्रस्त गांवों को ऐडॉप्ट किया है, वहां पर न केवल राहत सामग्री भेजी गई है बल्कि वहां पर उजड़े हुए लोगों को दोबारा से बसाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसके अलावा वहां पर हर प्रकार का रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय आप भी और सदन के हमारे कई सम्मानित साथियों ने अधिकारियों की टीम के साथ वहां पर पहुंच कर लोगों की सहायता करने का कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में जहां पर मैं रहता हूं उस सैक्टर में कई गुजराती परिवार बसते हैं। उन्होंने गुजारती पेपर और एलबम्ज दिखाए और उन्होंने एक बात रखी कि हरियाणा सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो सहायता वहां पर पहुंचाई है उससे उनका बहुत मार्गदर्शन हुआ है। गुजरात में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसकी वजह से वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ गया था तो हमारी पहल पर वहां पर जो कार्यक्रम शुरु हुआ है उसको देखकर और लोगों ने भी त्रासदी से निपटने के लिए कार्यक्रम बनाए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में आधे से ज्यादा राशि बिजली, परिवहन और सड़कों के लिए रखी है। यहां सदन में हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने बिजली के बारे में बड़ी भारी चिन्ता व्यक्त की है। बिजली के संकट से निपटने के लिए विपक्ष के साथ-साथ मुख्यमंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकारा है कि प्रदेश में बिजली का संकट है। उपाध्यक्ष महोदय, यह संकट एक दिन में ही नहीं आया है और इससे एक दिन में ही नहीं निपटा जा सकता है। बिजली का संकट पिछली सरकारों की भूल की वजह से, उस पर समय पर सही कार्यवाही न करने की वजह से हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिजली के संकट से निपटने के लिए वार फुटिंग पर 3 एम0 ओ0 यू0 सैन्टर गवर्नमैंट से मंजूर करवाए हैं। ऐसा काम पिछली सरकारें करतीं तो आज जो बिजली का संकट पैदा हुआ है वह पैदा ही नहीं होता।

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

सिंचाई के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सारी नहरों में पूरा पानी देने और उनसे खेतों में पानी देने के लिए बजट में काफी पैसा अलॉट किया है। फरीदाबाद में सारी माईनर्ज पक्की हो रही हैं इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं माननीय विधायक जी को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ये बल्लभगढ़ की बात करें जहां के ये विधायक हैं। इनको सारे फरीदाबाद की बात करने की जरूरत नहीं है। वहां पर न तो कोई माईनर पक्की हुई है और न ही वहां पर कोई पानी आया है। ये सिर्फ अपने हल्के की बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, कोई भी विधायक हरियाणा के बारे में बोल सकता है किसी भी पर्टिकुलर जिले के बारे में कह सकता है इसके लिए किसी पर भी कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। मैं तो हरियाणा की या अपने फरीदाबाद जिले की ही बात कर रहा हूं लेकिन ये तो सारे देश की और विदेश की बात करते हैं। क्या ये इतने बड़े नेता हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में हम सब साथियों का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि सरकार को सही सुझाव दें क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सरकार द्वारा सभी साथियों के अच्छे सुझावों को चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, स्वीकार किया जाता है। कल कृष्ण पाल जी गुर्जर ने बिजली के बारे में ऐसी तस्वीर खींच दी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में भाई कृष्णपाल जी मंत्री रहे हैं और उस समय ये 24 घंटे झंडे वाली गाड़ी लेकर घूमते रहते थे। अगर उस समय ये और दूसरे मंत्री बिजली के बारे में सीरियस होते तो कुछ काम करवाते। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत काम करने का संकल्प लिया है। मेवला महाराजपुर में ही 66 के0 वी0 के तीन सब स्टेशंज की आधारशिला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रखी है और इन पर 15 करोड़ रुपये का काम चालू हुआ है। इसी तरह से पल्ला पल्ली लाईन जो उन्हीं के हल्के में पड़ती है, पर भी 18 करोड़ रुपये का काम चालू हुआ है। इस तरह से सरकार 33 करोड़ रुपये के काम जिस माननीय साथी के विधान सभा हल्के में कर रही हो और वह साथी सदन में इस बारे में एक लाईन भी न बोले तो मैं समझता हूं कि हम चुने हुए साथी अपने फर्ज से कोताही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिसला साहब, आप अब वाइंड अप करें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : सर, मुझे तो अभी बोलते हुए तीन ही मिनट हुए हैं। सड़कों की भी बहुत खस्ता हालत सारे प्रदेश में रही है। सरकार ने प्रयास करके हुडको से 368.28 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध करवाया है इसलिए अब मैं समझता हूं कि 90 के 90 हल्कों में सड़कों पर काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और विशेष निवेदन सरकार से करना चाहूंगा। दिल्ली के नजदीक लगते हुए एरिया में सड़कों की वाइडनिंग एवं स्ट्रैंगथनिंग की बड़ी भारी आवश्यकता है। विशेषकर जिन सड़कों पर बड़े-बड़े ट्राले चलते हैं उन सड़कों की थिकनैस बढ़नी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1100 बसिज बदलने का जो फैसला लिया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने अभी फरीदाबाद में ट्रैफिक ऐड पोस्ट का शिलान्यास किया था जो कि बहुत अच्छी बात है। वहां पर जब भयंकर ऐक्सीडैंट हो जाते हैं तो लोग तड़फते रहते हैं उनको वहां कोई उठाने वाला नहीं होता। इसलिए सरकार का यह कदम बहुत

अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। कृषि की डायवर्सीफिकेशन के बारे में हुड्डा साहब ने तथा दूसरे अन्य साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने डब्ल्यू0 टी0 ओ0 और गैट के बारे में बातें कही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने खुद इस बारे में आदेश दिये हैं और वे इस तरह की नीति भी बना रहे हैं। आज कृषि की डायवर्सीफिकेशन अत्यंत आवश्यक है। आज किसान आंख मींचकर गेहूं और धान बोता चला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिसला जी, लेकिन आप तो गन्ना बोते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : मैं सब कुछ बोता हूं। हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि आज जो किसान गेहूं और धान उगाते हैं उसमें अगर सरकार की तरफ से एक हजार या दो हजार रुपये प्रति एकड़ देकर यह कहा जाए कि आप गेहूं और धान की फसल उगाना छोड़कर दूसरी फसलें उगाएं तो इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के बारे में भी आज आदरणीय मंत्री जी ने क्वैश्चन ऑवर में विस्तार से जवाब दिया है लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में और डिप्टी स्पीकर साहब आपके जिले में जो जमीन ऐक्वायर हो रही है उसके बारे में कई लोगों की बड़ी जायज मांग है उनकी सुनी जाए और जहां जमीन रिलीज हो सकती है वह अवश्य कर दी जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का इसके लिए ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कांस्टीच्यूशन की अमैंडमैंट 73-74 के तहत हमारे फरीदाबाद में फरीदाबाद नगर निगम का निर्माण हुआ। मैं वहां के किसी चुने हुए प्रतिनिधि या अधिकारी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जो फ्रेम वर्क है उसके तहत वहां रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है कृप्या मुख्यमंत्री जी उसकी तरफ ध्यान दें। वहां जो लोगों की समस्याएं हैं जैसे ट्रैफिक, रोड्स या पानी पूरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें देखा जाए और वहां की स्थिति सुधारी जाए। कानून-व्यवस्था की जहां तक बात है कानून व्यवस्था सारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से अच्छी है। खेलकूद नीति के लिए सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने सैनिकों और शहीदों के मान सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है और यह हम सभी के लिए फख्र की बात है। कारगिल में हर चौथा शहीद हमारे हरियाणा प्रदेश का था और इसके लिए समस्त हरियाणावासी बधाई के पात्र हैं और हरियाणा को वीरों का प्रदेश कहा है यह जुझारू और कर्मठ लोगों का प्रदेश है। मैं बताना चाहता हूं कि देश की पार्लियामैंट में चर्चा हुई है कि 15 हजार सैनिक अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा डाक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए क्योंकि वहां ज्यादा पैसा कमायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिसला जी, अब वाइंड अप करें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें कोई इस प्रकार की अकैडमी बनानी चाहिए जहां हमारे यहां के बच्चे ग्रेजुएट या जमा दो के पश्चात् कोई ट्रेनिंग ले सकें। हमारे यहां गांव के बच्चे लड़ाकू तथा शूरवीर हैं लेकिन वे जब लैफ्टिनैंट के इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पाते हैं इसलिए रिजैक्ट हो जाते हैं।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने लड़ाकू शब्द का प्रयोग किया है लड़ाकू नहीं कह सकते हैं अच्छी प्लानिंग करने वाला कह सकते हैं हम अच्छा फाइटर कह सकते हैं। शूरवीर हैं देश के लिए बलिदान दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लड़ाकू तथा शूरवीर कर लें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लड़ाकू शब्द का सही इस्तेमाल किया था। अब तक तीन लड़ाई हुई हैं युद्ध में वही लोग जम पाते हैं जो लड़ाकू होते हैं मैदान में वही टिकते हैं जो लड़ सकते हैं न लड़ने वाले तो मैदान छोड़कर भाग आये। मेजर सुल्तान सिंह व होशियार सिंह शहीद हुए। तो मैं कह रहा था कि कोई अकैडमी बननी चाहिए जहां हमारे यहां के बच्चे छह महीने की ट्रेनिंग लें। ग्रामीण विकास में सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसे सरकार को दूर करना चाहिए और उस कुरीति में हम राजनीतिक लोग भी शामिल हैं जब कोई शादी होती है तो 20-20 एकड़ भूमि में टैंट लगा दिया जाता है और 20-20 हजार आदमी उसमें आ जाते हैं इससे समाज के गरीब आदमी को बहुत दिक्कत होती है। 100 से ज्यादा आदमी शादी में नहीं आने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सारी बीमारियों को अगर आप और हम ढूंढना चाहेंगे तो मैं कहता हूं कि सबसे पुरानी पद्धति वैदिक पद्धति मौजूद है। हमें उसे अपनाना चाहिये तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। आर्य समाज की स्थापना हर गांव में होनी चाहिये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों की चौपालों में यज्ञ होना चाहिये। अंत में मैं उपनिषद का पहला मंत्र सुना देता हूं जो इस प्रकार है :-

ईशा वास्यम् इदं सर्व यत् किंचित् जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यस्वित् धनम्।

इसमें कहा गया है कि "अ" संसार के लोगों त्याग भावना से सीखो।

यह वेदों का मैसेज है इसको हमें एडोप्ट करना चाहिये। अंत में मैं इस बजट की सराहना करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बजट को पास कर दिया जाये। धन्यवाद।

श्री नफे सिंह राठी (बहादुरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज बजट 2001-2002 पर चर्चा चल रही है। डिप्टी स्पीकर सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2150 करोड़ रुपये का जो योजना परिव्यय रखा है और जिस हिसाब से हर डिपार्टमैंट में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए भलाई के लिये जो इन्होंने प्रोविजन रखा है और बेहतर ढंग से बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नफे सिंह जी आप पांच मिनट में कंक्लूड करें।

श्री नफे सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, हम नये मैम्बर हैं, बोलने के लिए थोड़ा टाईम तो आपको देना चाहिये। डिप्टी स्पीकर सर, जहां बिजली, सिंचाई और सड़क परिवहन आदि क्षेत्रों में 54.6 प्रतिशत खर्चा दर्शाया गया है यह बहुत ही अच्छी बात है। ये सभी जिंदगी की अहमियत की चीजें हैं। बिजली के बारे में विशेष तौर पर 485 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जहां सिंचाई के लिए 368.16 करोड़ रुपये का प्रोविजन है। डिप्टी स्पीकर सर, 1995 में प्रदेश में फ्लड आई थी और फ्लड आने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार रही परन्तु उन सरकारों ने सड़कों पर एक तोला मिट्टी भी डालने का काम नहीं किया और सड़कों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। आदरणीय

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश की सरकार की सत्ता संभालते ही जिस तरह से एक युद्धस्तर पर इस काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए सड़कों को ठीक करने का काम किया है उसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं। सड़कों के अच्छे काम के लिए माननीय विपक्ष के साथियों ने भी इस काम के लिये सरकार की सराहना की है जब सरकार के काम अच्छे होंगे तो सराहना तो करनी ही पड़ेगी। जबरदस्ती उन कामों की सराहना तो अवश्य की जायेगी। इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है। कल बी0 जे0 पी0 के साथी ने इसके बारे में काफी लम्बी चौड़ी बातें कहीं कि इस सरकार के आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से उनको आंकड़ों सहित बताना चाहूंगा कि 1998 में 828 कत्ल हुये, 1999 में 836 हुये और 2000 में 794 हुये इसी तरह से अपहरण की घटनायें 1998 में 507, 1999 में 546 और 2000 में 496 हुईं। इसी तरह से चोरी की घटनायें 1998 में 5934, 1999 में 6619 और 2000 में 6400 हुई ये सब आंकड़े मौजूद हैं। 1999 में डकैती के 113 केस हुए हैं और 2000 में 104 डकैती के केस हुए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कल ही पूरण सिंह जी का और करण सिंह दलाल जी का प्रश्न आया था। इसी तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछली सरकारों के समय के मुकाबले से कहीं बेहतर और अच्छी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि कानून और व्यवस्था के बारे में कांग्रेस की सरकार के समय में 1995 में बहादुरगढ़ में बेबी किलर कांड शुरु हो गये थे, लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा 8 साल से कम उम्र की छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किये गये और उनका कत्ल किया गया। 1995 से 1998 तक बेबी किलर कांड हुए लेकिन उस समय की सरकार बेबी किलर को पकड़ने में नाकामयाब हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय चौ0 ओम प्रकाश चौटाला जी की तारीफ करना उचित समझूंगा कि इन्होंने दिल्ली में 50 हजार छोटी-छोटी बच्चियों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव डाला तब जाकर यह बेबी किलर पकड़ा गया। बहादुरगढ़ उस समय बेबी किलर कांड के नाम से जाना जाने लगा था। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौ0 ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आई तब से बहादुरगढ़ से गुंडे और बदमाश लोग भाग गए हैं। इस प्रकार दिल्ली के साथ लगते क्षेत्रों जैसे बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव में अब शांति है और इन क्षेत्रों में विकास के कार्य चल रहे हैं लेकिन विपक्ष के साथी पता नहीं किस दृष्टि से इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेलों के बारे में कहना चाहूंगा कि जब से चौ0 अभय सिंह चौटाला हरियाणा ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष बने हैं तब से खेलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, खेलों के मामले में जो प्रगति एक साल से हुई है वह इससे पहले कभी नहीं हुई। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबाल टूर्नामैंट और बहादुरगढ़ में जो भारत केसरी दंगल हुए हैं वह शांति प्रिय तरीके से आयोजित किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं और एक खिलाड़ी की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं इसलिए जो खेलों के आयोजन की नीति चौ0 अभय सिंह चौटाला जी ने सरकार को दी है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस नीति को लागू किया जाए जिससे हरियाणा के खिलाड़ियों का भला हो सके और नौजवानों को गलत रास्ते पर जाने से रोका जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आने के बाद से हमारे यहां लगभग 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया है उसकी न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में सराहना हो रही है। सारे प्रदेश की सरकारें इस 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' को अपने राज्यों में लागू करने पर विचार कर रही है।

[श्री नफे सिंह राठी]

उपाध्यक्ष महोदय, जिस किस्म के विकास कार्य हरियाणा में चल रहे हैं वह काबिले तारीफ है। अभी कल यहां यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट को हरियाणा में लागू करने के बारे में चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बहादुरगढ़ शहर दिल्ली के साथ लगता शहर है और दिल्ली के सबसे नजदीक पड़ता है। बहादुरगढ़ की आबादी मेरे ख्याल से डेढ़ लाख के लगभग है, वैसे अभी सैन्सस की रिपोर्ट नहीं आई है। वहां पर सीवरेज की डिस्पोजल सिस्टम नहीं है और यहां के खेतों में सीवरेज का गन्दा पानी छोड़ दिया जाता है जिससे गन्दगी और मच्छर फैल रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्लान के तहत बहादुरगढ़ में भी एक ट्रीटमैंट प्लांट लगाने का प्रयास किया जाए। बहादुरगढ़ से सोनीपत जाने के दो रास्ते हैं एक तो वाया असौधा से खरखौदा और दूसरा रास्ता है नारा से नारी। इन दोनों रास्तों की चौड़ाई 12 फुट है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन रास्तों को कम से कम 24 फुट चौड़ा किया जाए। बहादुरगढ़ से खरखौदा तक तो दिक्कत है लेकिन खरखौदा से सोनीपत तक का रास्ता 24 फुट चौड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, 1162 साल पहले बहादुरगढ़ बसा था तब से एक शमशानघाट वहां पर था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस शमशानघाट की जमीन को एक्वायर कर लिया था। अब वहां पर मुर्दों को जलाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि शमशानघाट की उस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये ताकि लोगों को दिक्कत न हो। उस जमीन पर शैड और घाट बने हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल के दौरान माननीय मंत्री जी श्री धीरपाल जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि बहादुरगढ़ में आटो मार्किट बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह मार्किट जल्दी से जल्दी बनवाई जाये क्योंकि बहादुरगढ़ में आटो मार्किट के 200 मैंबर हैं जिसके कारण से नैशनल हाई वे पर जाम लग जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। यह आटो मार्किट बनने से हाई वे पर जाम नहीं लगेगा और लोगों को दिक्कत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति, खेल नीति, सूचना एवं प्रोद्योगिकी नीति और टैक्नीकल एजूकेशन के बारे में जो नीतियां बनाई हैं ये बहुत अच्छी हैं इससे हमारे प्रदेश की प्रगति होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जिस हिसाब से जन कल्याणकारी कार्य कर रही है उनको देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि वे सरकार की आलोचना करें लेकिन फिर भी मेरे विपक्ष के भाई छींटाकशी करे बिना नहीं रहते। इनको चाहिए कि ये सरकार को ऐसे सुझाव दें जिनसे जनता की भलाई हो और जो अच्छे कार्य हमारी सरकार कर रही है उसमें सरकार का साथ दें।

श्री उपाध्यक्ष : नफे सिंह जी प्लीज आप कंक्लूड करें।

श्री नफे सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ के इन्डस्ट्रीयल एरिया में 900 एकड़ भूमि दफा-4 के तहत एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने एक्वायर की है और वहां पर नये इन्डस्ट्रीयल सैक्टर विकसित किये जायेंगे। जिसके कारण वहां पर ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। हरियाणा के 19 में से 18 जिलों में 220 के0 वी0 ए0 के पावर हाउस हैं लेकिन झज्जर जिले में 220 के0 वी0 ए0 का एक भी पावर हाउस नहीं है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वे झज्जर जिले में भी एक 220 के0 वी0 ए0 का पावर हाउस बनायें और यह पावर हाउस बहादुरगढ़ में बनाया जाये ताकि वहां

के लोगों को बिजली की समस्या न हो। ऐसा होने से हरियाणा के सभी जिलों में 220 के0 वी0 ए0 के पावर हाउस हो जायेंगे। इसके अलावा बहादुरगढ़ में ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम है, अभी थोड़े दिन पहले इस स्टेडियम में भारत केसरी का दंगल हुआ था और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस समारोह में मुख्य अतिथि थे इन्होंने भी देखा था कि इस स्टेडियम में 40-50 हजार दर्शक आये थे लेकिन इस स्टेडियम का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस स्टेडियम का काम पूरा करवाया जाये। इसके अलावा एक छोटी सी बात सदन में और रखना चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के साथी कभी भिवानी रैली करते हैं, कभी किसान रैली करते हैं। जैसा कि मेरे माननीय साथी बाली जी ने कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष को तो यह भी नहीं पता कि गेहूं, बाजरे या जवार का पेड़ कैसा होता है फिर ये किसानों का हितैषी अपने को कैसे कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कांग्रेस के भाई सुनने की हिम्मत तो रखते नहीं हैं सिर्फ कहना जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब और जय प्रकाश जी प्लीज आप बैठें। राठी साहब आप भी बात न दोहरायें प्लीज आप भी बैठें। हुड्डा साहब आप बिना इजाजत के न बोलें। आपको बोलने का पूरा समय दिया गया था। (शोर) अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस बेचारे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की भी क्या गत है। इन्हें भिवानी स्टेज के ऊपर भी बुला लिया गया उसके बावजूद भी बोलने नहीं दिया गया। (शोर) यहां पर भी इनके साथी कहते हैं कि ये नहीं बोल सकते। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय विपक्ष के कई सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिए। हुड्डा साहब, आप भी बैठिए। दलाल साहब, आप भी बैठें। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश की बात भी श्री करण सिंह को कहनी पड़ रही है। (शोर) यह तो बड़ी अजीब बात है। (शोर) जय प्रकाश तो अपनी बात खुद भी कह लेता है। (शोर) आप सब बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हुड्डा साहब को बेचारा कैसे कह दिया (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लिया और मुझे बेचारा कहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जानकारी के लिये थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। असहाय और बेबस आदमी को बेचारा कहा जाता है। इससे भी ज्यादा स्पष्ट कर दूं। इससे ज्यादा फ़जीयत इनकी क्या होगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भी ये लोग इनको बोलने नहीं दें। इनको तो आपको दाद देनी चाहिए कि आपने फिर भी इनको बोलने का समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई भी सदस्य चेयर की परमिशन लिये बगैर खड़ा होकर बोले तो उसकी बात रिकार्ड न की जाए। (शोर) नफे सिंह जी, आप अपनी बात एक मिन्ट में पूरी करके कन्क्लूड करें।

श्री नफे सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथियों को ज्यादा तकलीफ होगी लेकिन मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * *। (ऐसा उन्होंने भागी राम की ओर इशारा करते हुए बोला)। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सदन की व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए, (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण, श्री कर्ण सिंह दलाल और श्री जगजीत सिंह सांगवान स्पीकर की वैल में आकर जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : क्या स्पीकर सदन के किसी सदस्य को सदन से उठा कर बाहर फैंकने की बात कह सकता है ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संयम में रहें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन के सदस्यों को सीमा में रखने का प्रयास किया जाए। यह बेहतर रहेगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी अपोजीशन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और संयम में रहें। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्पीकर सदन के किसी सदस्य को सदन से उठा कर बाहर फैंकने की बात कह सकता है ? (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनने की कृपा करें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठ जाएं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज वे लोग पार्लियामैंट्री लैंग्वेज का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने ट्रेजरी बैंचिज पर बैठ कर जनतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया था। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं अपोजीशन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि आप सभी बैठ जाएं और संयम में रहें। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर कौन से रूल के तहत सदन के किसी सदस्य को सदन से उठा कर बाहर फैंकने की बात कह सकता है। (शोर)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अजीब तमाशा है अपोजीशन के सदस्य आपकी बात को अनसुनी करके अपनी गज गज की लम्बी जुबानें ले करके अपनी मनमर्जी की बात कहते जा रहे हैं। सदन की गरिमा है उसको कायम रखना हम सब का फर्ज है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या सदन का कोई सदस्य तेरी ऐसी तैसी लफ्ज किसी सम्मानित सदस्य के प्रति सदन में कह सकता है और अगर किसी सदस्य ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठें। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरी बात सुनें उसके बाद आप अपनी रूलिंग दे दें। आप मेरी बात सुन लें उसके बाद सारी रूलिंग इकट्ठी दे दें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : किसी सदस्य को किसी दूसरे पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जो कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया वह गलत किया। (शोर) आक्षेप लगाने की शुरुआत कैप्टन अजय सिंह यादव ने की। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस में डैकोरम रखना बहुत जरूरी है। हर सदस्य का यह कर्त्तव्य होना चाहिए। वह सदन में चुन कर आया है। सारे प्रदेश के लोग आप लोगों को देख रहे हैं कि जिनको उन्होंने चुन कर यहां पर भेजा है उनका क्या किरदार है और वे कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस ढंग से बात कर रहे हैं, किस ढंग से उनकी नुमायंदगी कर रहे हैं। देखने में आया कि माननीय सदस्य श्री भागीराम जी ने कैप्टन अजय सिंह यादव को * * * * दिखाया। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह बात आपको किसने कही ? (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, श्री भागी राम मेरे सामने बैठते हैं इसलिए मैंने उनको * * देखा था। (शोर)

श्री अध्यक्ष : पहले कैप्टन अजय सिंह ने उनको * * था। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चाहे उन्होंने बाद में दिखाया हो। (शोर) आप मेरी बात तो सुनें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप * * मत बोलो। हाउस के अन्दर इस पिलर पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें। उसके बाद बोलें। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : पहले आप यह बताएं कि इस बात की शुरूआत कहां से हुई थी। (शोर)

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, * * * * ही कहा जाएगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य को सभ्यता से बोलना चाहिए। (शोर)

---

*Expunged as ordered by the Chair.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, यह ठीक है कि यहां पर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। (शोर एवं विघ्न)

12.00 बजे

श्री धीरपाल सिंह: धर्मवीर जी अगर भूल हो गई हो तो उसको सुधारना चाहिए। मैं समझता हूं कि भूल को सुधारने में कोई बुराई नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों अपना आचरण सुधारें। आप लोगों से बार-बार रिक्वैस्ट की गई है कि आप अपना आचरण सुधारें। (शोर एवं विघ्न) सदन में आपका आचरण ठीक नहीं है। बाहर आपका आचरण कैसा है वह आपको पता होगा। (शोर एवं विघ्न) सदन में आपका आचरण ठीक नहीं है। इस बारे में सभी मैम्बर जानते हैं। आप दोनों बिना वजह सबसे ज्यादा इन्टरवीन करते हैं। पहले आप अपना आचरण सुधारें। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, किसका आचरण ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी का और कर्ण सिंह दलाल का आचरण ठीक नहीं है।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, कई बार मामला गर्म हो जाता है तो उस समय आपको भी संयम से काम लेना चाहिए। आपने कर्ण सिंह जी को कह दिया कि फैंक दो उठा कर। आपने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिये थे। (शोर एवं विघ्न) आपका किसी मैम्बर को यह कहना कि गेट आऊट, यह आपको शोभा नहीं देता (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अगर कोई सदन की कार्यवाही में विघ्न डालेगा तो उसको ऐसा कहना पड़ेगा। (शोर एवं विघ्न) भजन लाल जी वे मैम्बर की हैसियत से यहां पर नहीं बोल रहे थे। ये अपनी सीट से न बोल कर दूसरे सदस्य की सीट से बोल रहे थे। किसी दूसरे की सीट से किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से यह कहना कि गेटआऊट-गेटआऊट ठीक नहीं है। ये सदस्य भी यहां पर चुनकर आये हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किसी सदस्य को अपनी सीट से अलग हटकर बोलने का अधिकार नहीं है।

चौधरी भजन लाल : ये आपसे सीनियर हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : वे मेरे से सीनियर नहीं हैं।

चौधरी भजन लाल : आपको पता नहीं है, वे आपसे सीनियर हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी ये दोनों मेरे से जूनियर हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्पीकर का जो दायित्व होता है वह आपको निभाना चाहिए। (शोर एवं विघ्न) पहले मैं अपनी बात तो कर लूं। स्पीकर को चाहिए कि वे दोनों पक्षों को एक आंख से देखें। (शोर एवं विघ्न) यदि आपका हमारे प्रति ऐसा ही बर्ताव रहा तो हम बजट पर बहस के समय यहां पर बैठेंगे नहीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राव इन्द्रजीत जी आप बैठिये। (शोर एवं विघ्न) इसमें गलत क्या किया। (शोर एवं विघ्न) आप सभी बैठिये। अब सी० एम० साहब कुछ कहना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने के लिए अनुमति प्रदान की इसके लिए आपका धन्यवाद। (शोर एवं विघ्न) मुझे तो स्पीकर साहब ने अनुमति दी है, अब तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। (शोर एवं विघ्न) जय प्रकाश जी आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता की यह आपत्ति मुनासिब नहीं है। इन्होंने जो कहा है वह अध्यक्ष को चुनौती देना है। (शोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कुछ कायदे कानून बने हैं और उसके मुताबिक सदन का कोई भी सम्मानित सदस्य अगर कोई बात अपनी कहना चाहेगा तो वह अपनी सीट पर से ही कह सकता है। आप सब को पता है कि कर्ण सिंह ने वहां पर गेट के पास जाकर एक अनर्गल और गैर जिम्मेवाराना बात करने का प्रयास किया। (शोर एवं विघ्न) हैरानी मुझे यह है कि कैप्टन अजय सिंह जैसा आदमी जो मिल्ट्री मैन भी है, पढ़ा लिखा आदमी भी है और बुद्धिमान भी है, वह गांव के गंवार आदमियों की भाषा का इस्तेमाल यहां पर करे वह शोभा नहीं देता। (शोर एवं विघ्न) आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और आप जिम्मेवार पदों पर रहे हैं। आप तीसरी-चौथी मरतबा जीत कर इस सदन में आते हैं। हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के इसलिए पक्षधर नहीं हैं क्योंकि आपके घर में रिसेन्टली एक दुर्घटना घटी है, उसको देखते हुए हम आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। हम सामाजिक लोग हैं। हम यहां पर केवल राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए नहीं आते और न ही हमारा ऐसा कोई ध्येय है। (शोर एवं विघ्न) दलाल साहब आप तो मेरे से बहुत बड़े आदमी हैं। आपसे मेरी बात नहीं हो सकती। आपसे तो मैं हाथ जोड़ता हूं यहां भी जोड़ता हूं और बाहर भी जोड़ सकता हूं। इसके अलावा और कहीं पर भी जहां पर आपसे मिलूंगा वहां भी हाथ जोड़ दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि इस सदन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। अब तक सदन का माहौल बड़ा पीसफुली चल रहा था। अब सैशन समाप्ति के करीब है। अब या तो ये वाक-आऊट करके ये अपनी कोई खबर बनाना चाहते हैं या इनका कोई और ध्येय हो सकता है। अगर इन्होंने जाना है तो आराम से भी जा सकते हैं, इसमें तलखी और कटुता पैदा करके जाने की कोशिश क्यों करें ? अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आप अपनी रूलिंग दें और फिर सदन की कार्यवाही को आगे चलाएं। (शोर एवं विघ्न)

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, यह जो यहां पर अव्यवस्था बनी और सारा माहौल यहां पर गड़बड़ा गया, यह गलत हुआ। स्पीकर साहब, आपके इस कुर्सी पर बैठे जाने के बाद यहां के लोग आपसे बहुत सी आशा लगाए बैठे थे। पिछले 5-6 दिनों से यह सैशन चल रहा है। आपके द्वारा आशानुसार कुछ न करने की वजह से इन साथियों की आशाओं पर पानी फिर गया। जब किसी एक व्यक्ति ने एक माननीय सदस्य को गांव की भाषा में गंजा कहा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा था कि * * * * * * । उन द्वारा यह बात कहनी अच्छी नहीं थी। आपको पता है कि हरियाणवी भाषा में तेरी * * * कहना गाली है।

राव इन्द्रजीत सिंह : जब * * के ऊपर इतना एतराज हुआ है तो यहां पर हमारे विपक्ष के नेता ने जब यह कहा कि स्पीकर को सभी को एक आंख से देखना चाहिए तो उसके ऊपर भी इन लोगों की तरफ से क्या कहा गया, आपने सुना होगा। जब हमारे नेता ने आपत्ति नहीं जताई तो फिर * * * * कहने पर क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यहां पर गंजा कहने पर ऐतराज हुआ है जबकि हमारी तरफ के लोगों को भी कई बार कुछ बातें बोलते रहते हैं। क्या गंजा कहना कोई गलत बात है ?

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : आप इस बात पर गौर करें कि किसी सदस्य को यह कहना * * * * * * यह ठीक नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इन्हें * * कहने पर इतना ऐतराज क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, किसी सदस्य को यह कहना कि * * * * * * बहुत गलत बात है और अनपार्लियामैंटरी है। कैप्टन साहब, आपको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। (विघ्न) यह ठीक नहीं है। आपका यह आचरण उचित नहीं है (विघ्न) आप बैठिए (विघ्न) आप किस लिए खड़े हुए हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी तक कैप्टन अजय सिंह को इस बात का ज्ञान नहीं हुआ है कि ये आप की इजाजत से बोलते वक्त डायरैक्ट किसी दूसरे मैम्बर से बात नहीं कर सकते। यह अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं लेकिन किसी दूसरे सम्मानित सदस्य से सीधे मुखातिब नहीं हो सकते हैं। हमें इनसे हमदर्दी है। वह हमदर्दी इसलिए है कि अभी हाल ही में इनके घर मे एक दुर्घटना घटी है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनके साथ यह दुर्घटना न घटी होती तो यह सदन इनसे यहां पर क्षमायाचना करवाता। इनका किरदार इस किस्म का था कि इसके लिए इन्हें क्षमायाचना करनी पड़ती। इस हाउस में ऐसी ट्रैडीशन नहीं है कि जिस किसी ने भी कुछ गलत आचरण किया है या कोई गलत बात कही है उसके लिए उसे क्षमायाचना करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहूंगा कि इनके हालात पर तरस खा कर इस चैप्टर को क्लोज करें। (विघ्न एवं शोर) मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं मैं यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो कि काबिले ऐतराज हो। कैप्टन साहब को याद होगा कि आंखों देखी में भी ये कह रहे थे "पढ़ा-लिखा" मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस देश में "वाईजैस्ट स्टुपिड" भी हैं। ये फिर से उसी प्रकार की चर्चा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस सदन से तथा विशेषरूप से अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस मामले को यहीं पर निपटाया जाए और सदन की कार्यवाही को पीसफुली चलाया जाए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब सैशन की समाप्ति नजदीक है इसलिए अच्छे वातावरण में इसे समाप्त होने दीजिए और इसकी कार्यवाही को ठीक चलने दीजिए।

श्री देवराज दीवान (सोनीपत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2001-2002 के बजट पर बोलने के लिए समय प्रदान किया जिसके लिए मैं आपका अति आभारी हूं। हरियाणा प्रदेश के मान्यवर वित्त मन्त्री महोदय ने 12 मार्च को सरकार का जो बजट यहां हाउस में प्रस्तुत किया है मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्तावित बजट से शत-प्रतिशत सहमति प्रकट करते हुए अपने वित्तमन्त्री को एक शानदार और विकासशील बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। उन्होंने प्रदेश के आम नागरिक की भावनाओं के अनुरूप इस बजट को तराशा है और उसमें प्रदेश के विकास के रंग भरने का सराहनीय कार्य भी किया है।

अध्यक्ष महोदय, मानवीय संवेदनाओं के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। गुजरात में 26 जनवरी को आए विनाशकारी भूकम्प ने न केवल पूरे देश को अपितु पूरी दुनिया को हिला कर

*Expunged as ordered by the Chair.

रख दिया। गुजरात में हुई इस भीषण तबाही के मौके पर हरियाणा सरकार ने गुजरातवासियों की इस दुख की घड़ी में जो तत्काल सहायता वहां पहुंचाई और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार का पूरा प्रशासन एवं जनता एकजुट हो कर गुजरात की इस भयानक त्रासदी के मौके सहायता के लिए पहुंची उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। भूकम्प प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने के साथ ही सरकार ने रापड़ ताल्लुका के 19 गांवों को एडॉप्ट कर सारे भारतवर्ष के साथ ही साथ दुनिया में एक मिसाल कायम की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी की सोच कितनी ऊंची है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हम गुजरात वासियों की इस दुख की घड़ी में साथ दें और राज्य की कई संस्थाओं ने राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री जी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर वहां पर उन लोगों की सेवा की है। आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी सरकार का नाम चमका है और मुख्यमंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। अभी हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी भी आए थे उन्होंने भी इनके इस काम के लिए इनकी प्रशंसा की है।

श्री अध्यक्ष : देव राज दीवान जी आप जल्दी से खत्म करें।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, अगर समय की कमी है तो कोई बात नहीं मेरे पास लिखी हुई स्पीच है मैं इसको सदन की टेबल पर रख देता हूं और इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं इनको और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने इसमें राज्य के चहुंमुखी विकास करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री जी ने तो चुनाव से पहले जो वायदे किए थे तकरीबन-तकरीबन वे सभी वायदे पूरे कर दिए हैं और एक मिसाल कायम की है। उन कामों की वजह से जनता ने फिर से इनको चुनाव में जिताकर भेजा है। आज मुख्यमंत्री जी लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और वायदे भी कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि आज जनता इस सरकार से नाराज है। वे यह नहीं कह पाते कि जनता मुख्यमंत्री जी की नीति से, सरकार की नीति से, उनके काम से नाराज नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि आज जनता की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा होती है जिसको चाहे हम हों, यह सरकार हो और चाहे विपक्ष हो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जनता में कुछ नाराजगी तो रहती ही है। मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने वायदे पांच साल के लिए किए हैं अभी तो एक साल ही इस सरकार को हुआ है। विपक्ष के साथी चार साल और इन्तजार करें फिर देखें कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए वायदे और हमारी सरकार द्वारा किए गए वायदे पूरे किए जाते हैं कि नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी "सरकार आपके द्वार" प्रोग्राम में जहां पर भी गये और जो वायदे किए गए हैं उसके बारे में अफसरों से तसल्ली करते हैं कि मैंने ये ये वायदे फलानी-फलानी जगहों पर किए थे वे पूरे हुए हैं कि नहीं मैंने दोबारा से भी वहां पर जाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी की इस प्रकार की सोच है। वह कोई भी काम हो चाहे वह बिजली से या सिंचाई से रिलेटिड हो उस काम को पूरा करवाने की कोशिश की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को बताना चाहूंगा कि मैं पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज कमेटी का मैम्बर हूं और उस कमेटी ने पिछले 6 महीने पहले बिजली के सभी सैक्टर्ज का दौरा किया था और फिर दोबारा से उनका 6 महीनों के बाद दौरा किया था हमें वहां पर एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली थी और आने वाले सालों में जनता को भी दिखाई देगा कि मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने कैसे अच्छे काम किए हैं। वे हमेशा यह देखते हैं कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो कोई परेशानी न हो।

[श्री देवराज दीवान]
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं काम करके दिखाऊंगा और हरियाणा को देश में नम्बर एक पर लाऊंगा इसके लिए मैं यह बात एकतरफा होकर नहीं कह रहा हूं बल्कि विश्वास के साथ कहता हूं कि विपक्ष के साथी चार साल और देखें। ये बात सच होकर रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात कहना चाहूंगा। (विघ्न) गुप्ता जी आज भी आप देख रहे हैं और आपने पहले भी देखा है। आज आप कह रहे हैं कि अपराध हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अपराधी ने तो अपराध करने हैं। कत्ल भी होते रहते हैं इनको कोई नहीं रोक सकता। न इनको कोई पहले सरकार रोक सकी और न ही कोई सरकार आगे रोक पाएगी। लेकिन सरकार की मंशा देखी जाती है, मुख्यमंत्री की मंशा देखी जाती है या पुलिस अधिकारियों की मंशा देखी जाती है। मैं आज पूरे तौर पर यह कह सकता हूं कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं उनकी वजह से आज पुलिस के अधिकारी पूरी तरह से अपराधियों को ट्रेस करने में लगे हुए हैं। जब भी कोई वारदात होती है पुलिस के अधिकारी चैन से तब तक नहीं बैठते जब तक अपराधी पकड़ न लिए जाएं। इसलिए कानून और व्यवस्था ठीक रखने के बारे में सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है। केस तो होते ही रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की समस्याओं के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप अपनी ये समस्याएं लिखकर भेज देना।

श्री देवराज दीवान : ठीक है जी, मैं इनको लिखकर भिजवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं और अपने विपक्ष के साथियों से भी कहूंगा कि वे इस बजट का पूरा समर्थन करें। (धन्यवाद)

श्री बलबीर पाल शाह (पानीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। पिछले साल भी चौधरी सम्पत सिंह जी ने सदन में बजट पेश किया था उसमें उन्होंने जनता से यह वायदे किए थे कि वे कोई नया कर नहीं लगाएंगे इसके लिए हमने उनको मुबारकवाद भी दी थी। इस बार भी उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें नये करों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इनका पिछले साल का जो बजट था उसमें सिर्फ बेर खिलाए गए थे और इनके वे बेर गला घोंट साबित हुए। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा की जनता घुटन महसूस कर रही है। जनता पर बहुत ज्यादा कर लाद दिए गए और जिस ढंग से ये कर लगाए गए उसको जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं इस साल के बजट के बारे में यही कहना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छे शब्दों में पेश किया गया है लेकिन होना यह मेले के हलवे जैसा ही है इसको खाने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी तासीर क्या है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं ट्रांसपोर्ट महकमे के बारे में कहना चाहूंगा। बजट में कहा गया है कि 1100 बसिज बदलने का प्रावधान है। लेकिन अगर इसको ठीक ढंग से पढ़ा जाए तो यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि 450 बसिज 2000-2001 में बदली गयी हैं और 2001-2002 में 650 बसिज बदलने का प्रावधान किया जाएगा। अगर मंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता तो ठीक था लेकिन यह कह देना कि इस वर्ष में 1100 बसिज का बदलने का प्रावधान किया है, ठीक नहीं है। यह थोड़ा हाउस को गुमराह करने वाली बात है। इनको इस बात की बारीकी को समझना चाहिए। इसके साथ-साथ एक और बात मुझे बजट में नजर आ रही है कि जो पुराने ट्रांसफार्मर्ज हैं या जो सड़े हुए या फुके हुए ट्रांसफार्मर्ज हैं जिनकी जगह नये ट्रांसफार्मर्ज लगाए जाने हैं उनमें अब कॉपर क्वायल्ज की बजाए ऐल्यूमिनियम की क्वाल्यज होंगी। मैं इस बारे में सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कॉपर क्वायल्ज की रजिसटैंस बहुत कम होती है और उनकी लाइफ

ज्यादा होती है अगर ऐल्यूमिनियम की वचायल्ज वाले ट्रांसफार्मर लगाए गए तो वे इतना लोड सह नहीं पाएंगे और फुंक जाया करेंगे जिससे बाद में जनता को और सरकार को बड़ी परेशानी होगी।

मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से एक ऐसी बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी ने शराबबंदी की लेकिन उसके बाद शराबबंदी को हटा दिया गया और जो साथी डिस्टिलरी में काम कर रहे थे उन साथियों को दोबारा वापस नहीं लिया गया जिसकी वजह से बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। स्पीकर सर, आप ही की कांस्टीचूएंसी का एन0 एफ0 एल0 के पास एक साथी था एक बच्चा था उसने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए कि उसके पास डिस्टिलरी में काम करने के सिवाय और कोई रोजगार नहीं था और बेरोजगारी से तंग आकर उसने आत्महत्या की। इस बार भी सरकार ने कॉन्फेड, अपैक्स और बहुत सी संस्थाओं को बंद करने का फैसला लिया है मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग वहां से हटाए गए हैं या हटाए जाएं उनको किसी न किसी दूसरे विभाग में ऐडजस्ट करना चाहिए क्योंकि यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। इसी तरह से बिजली की समस्या की बात है चाहे हम कहें या न कहें सच्चाई यह है कि 1987 में जो बिजली थी उसकी आधारशिला चौधरी बंसी लाल जी ने रखी थी जिनको प्यार से हम बाबू जी कहते हैं। उसके बाद सरकार लोकदल की बन गई और लोगों ने यह देखा कि हरियाणा बिजली से चमचमा रहा है तो उसका क्रेडिट लोकदल की सरकार को मिला। वास्तविक तथ्य यह था। (विघ्न) पंवार साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। मेरी मंशा व्यक्तिगत आक्षेप करने की नहीं है मैं तो जनभावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैं यहां से नंबर बनाकर नहीं जाना चाहता हूं। बिजली की चोरी सरकार के सामने एक गंभीर समस्या है और बिजली चोरी जो होती है उसको लाइन लौसिज में दिखाया जाता है। आज जो बिजली के मीटर देने का निर्णय लिया गया है वह गरीब जनता के पक्ष में नहीं है पहले कोई गरीब आदमी मीटर या बिजली का कनैक्शन लेना चाहता था तो 900 या एक हजार रुपये में मिल जाता था लेकिन आज अगर उसको अपनी झोंपड़ी में एक बल्ब और एक पंखा चलाना हो तो उसको कई हजार रुपया देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह उसके लिए एक बड़ा भारी बोझ है। अध्यक्ष महोदय, अगर वह अमीर होता तो झोंपड़ी में न पड़ा होता बल्कि हुड्डा की आलीशान कालोनी में आपके पड़ौस में बसता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस नीति को बदला जाए और लोगों को व खास तौर से जो नयी कालोनियां बनी हैं जो न तो गांव के लाल डोरे में आती हैं और न ही शहर की म्यूनिसिपल लिमिट में आती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप शॉर्ट करें।

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात कह दूंगा। अब मैं पानीपत की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पानीपत शहर में वाटर सप्लाई इस समय बहुत कम है। उसकी वजह कुछ तो बिजली है, कुछ पानी के ट्यूबवैल्ज बैठ गये हैं और कुछ ट्यूबवैल्ज में पानी कम आना शुरु हो गया है। आगे गर्मियां आने वाली हैं इसलिए पानी के लिये सरकार को कुछ इंतजाम करने चाहिये। चौटाला साहब पानीपत अक्सर आते रहते हैं मैं उनसे एक प्रार्थना करूंगा कि वे एम0 एल0 ए0 को एच0 आर0 डी0 एफ0 का एक करोड़ रुपया अवश्य दें। लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पानीपत में भी "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत उन कालोनियों में जाकर उन लोगों की हालत देखें और उन लोगों को पीने का पानी देने और नालियों का प्रबन्ध करें। पानीपत शहर गंदगी से सड़ रहा है और वहां पर सुअर पालन हो रहा है मुझे यह डर है कि आने वाले समय में कहीं कोई महामारी

[श्री बलबीर पाल शाह]

शहर में न फूट पड़े। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर तव्वज्जह दें और एम0 एल0 ए0 ग्रांट को दो करोड़ रुपये तक करें क्योंकि जब यह सरकार बुढ़ापा पैंशन को डबल कर सकती है तो इस ग्रांट को भी कर सकती है। अगर दो करोड़ न करे तो एक करोड़ रुपये एम0 एल0 ए0 को दे दें और एक करोड़ से अपना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाये हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शाह जी शार्ट करें।

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा पानीपत में ट्रैफिक कनजैस्न इतना है कि पानीपत में फलाइ ओवर या बाइ पास का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिये। इसी तरह से एजुकेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इन कालोनियों में सर्वे करवाकर प्राइमरी या मिडिल स्कूल खोलने चाहियें ताकि बच्चों को पढ़ने के लिये दूर न जाना पड़े। इसके अलावा मैं पब्लिक स्कूलों के बारे में कहना चाहूंगा कि मैं उनके हक में नहीं हूं फिर भी इसलिये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये स्कूल शिक्षा दे रहे हैं सरकार साक्षरता की जब बात करती है तो उन स्कूलों के बच्चों को भी उसमें शामिल करती है जो रिकोग्नाईजड नहीं हैं। इसी तरह से हैल्थ मिनिस्टर ने एक प्रश्न के जवाब में एक दिन कहा था कि प्रदेश में जनसंख्या पर काफी नियंत्रण हुआ है। मैं आपके माध्यमं से हैल्थ मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस जनसंख्या कंट्रोल में वे भ्रूण हत्याएं भी शामिल हैं जिनके कारण जनसंख्या में गिरावट हो रही है। ऐसे मानव अपराध पनप रहे हैं जिन पर सरकार को बैन लगाना चाहिये और सख्ती से उस पर अमल करने के साधन अपनाने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : शाह जी आप बैठिये। (विघ्न) जब आपका नाम पहले पुकारा गया उस समय आप सदन में मौजूद नहीं थे और अब ज्यादा समय देने की बात करते हैं।

श्री बलबीर पाल शाह : सर मैं 5 मिनट में समाप्त करता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप कल डिमाण्डज पर बोल लेना।

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पानीपत टाऊन को इको टाऊन डिक्लेयर किया गया था उसके बारे में पिछली सरकार ने क्या कोशिशें की हैं ताकि पानीपत टाऊन को एक साफ सुथरा और इकोलोजी टाऊन बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे यहां बहुत सी समस्याएं है लेकिन मैं एक अन्तिम समस्या के बारे में कहना चाहूंगा कि पानीपत में मुसलमानों के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां वे मुर्दों को दफना सकें। पानीपत में बहुत से प्रदेशों से जैसे बंगाल से, मद्रास से और यू0 पी0 से मुसलमान लोग आकर बस गए हैं इसलिए मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई है।

श्री अध्यक्ष : बलबीर पाल जी, अब आप बैठिए, कल बोल लेना।

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे कल बोलने का मौका देंगे।

चौधरी लीला कृष्ण (फतेहाबाद) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रो0 सम्पत सिंह जी ने 12-3-2001 को सदन में कर मुक्त बजट प्रस्तुत किया। इसके लिए हरियाणा की जनता कृतज्ञ है कि कितना सुन्दर और कर रहित बजट पेश किया गया है। यह देश के लिए एक मिसाल है। मैं बजट पर बोलने से पहले गुजरात में आई त्रासदी के बारे में दो मिनट

कहना चाहूंगा। 26 जनवरी को जब भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा था, एक शक्तिशाली, भयानक और विनाशकारी भूकम्प गुजरात में आया जिसके कारण हजारों लोग मर गए लाखों लोग जख्मी हुए और लाखों लोग बेघर हुए। इस त्रासदी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां गए और डिप्टी स्पीकर साहब, चौ0 अजय सिंह चौटाला जो एम0 पी0 हैं, अभय सिंह चौटाला, प्रो0 सम्पत सिंह जी, रामबीर सिंह जी और मुख्यमंत्री महोदय अपने दल बल के साथ सभी वहां गए। मैं स्वयं भी वहां गया, जब हमने वहां जाकर हालात देखे तो कलेजा मुंह को आता था। अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार इतनी स्तब्ध रह गई थी कि उन्हें खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है। हरियाणा सरकार ने मदद करके पहल की और दूसरे लोगों को राह दिखाई। हमारी सरकार ने वहां पर एक-एक आदमी का, एक-एक फैमिली का सर्वे किया और उनके राशन कार्ड बनाए। हरियाणा की धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने और सारे देश के लोगों ने इकट्ठे होकर मदद की विदेशों से भी जो इमदाद गुजरात में पहुंची उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यूरोक्रैटस का नाम भी लेना चाहूंगा, पुराने चीफ सैक्रेटरी विष्णु भगवान, राम सहाय वर्मा, पी0 एन0 पराशर और आर0 एन0 जैन तथा और भी कई बड़े लोग वहां पहुंचे, सब बड़े-बड़े अधिकारी निक्कर और बनियान पहनकर राहत कार्यों में लगे हुए थे। यह सारा क्रैडिट हरियाणा सरकार को जाता है। गुजरात के अखबार जो हम यहां लेकर आए थे, उनमें लिखा है कि हम कृतज्ञ हैं और हम यह अहसान कैसे उतार सकेंगे। गुजरात के लोग बड़े ही नेक लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने गुजरात में सूई से लेकर बड़ी-बड़ी मलवा उठाने वाली मशीनें, लाखों कम्बल और 500 ट्रक अनाज के दिए। नमक, मिर्च और हल्दी आदि चीजें भी वहां पहुंचाई गई थीं। मेरे ख्याल से यह एक ऐसी मिसाल है जिसको हिस्ट्री में लिखा जाएगा। स्पीकर साहब, विपक्ष के भाईयों ने बिजली और पानी की समस्या के बारे में काफी कुछ कहा। यह बात तो इस महान सदन के सभी मैंबरान जानते हैं कि वर्षा न होने के कारण ही यह समस्या आई लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इसका सामना किया। कोई मैंबर कहता है कि दिल्ली से पानी लाओ, कोई कहता है कि हिमाचल से पानी लाओ। जब बरसात ही नहीं हुई तो पानी की समस्या हरेक जगह ही हुई होगी। इंसान पर परमात्मा की अपार कृपा होती है और वर्षा हो तो सारी समस्या दूर हो जायेगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वर्षा हो जाये। (शोर एवं व्यवधान) जिस समय चौधरी भजन लाल जी सदन के नेता थे तब उन्होंने संपत सिंह जी को पानी के मामले पर कहा था कि उन्होंने भगवान के पास टैलीफोन किया है और अभी वर्षा हो जायेगी और पानी की समस्या नहीं होगी तथा ऐसा कहते ही थोड़ी देर में वर्षा शुरु हो गई थी। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चारों तरफ विकास का सूत्रपात है। मौजूदा सरकार एक-एक हल्के में जाती है और लोगों की समस्या सुनती है तथा उसी समय उसका समाधान करती है। साथ की साथ जो समस्या होती है उसे दूर करने के लिए उस पर काम शुरु करने के आर्डर जारी कर दिए जाते हैं। यह जब से हरियाणा बना है तब से आज तक एक मिसाल है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस विधान सभा का डेढ़ साल समाप्त हो चुका है और इस डेढ़ साल में सरकार ने जिस तरह से प्रगति के कार्य किये हैं उनसे ऐसा लगता है कि आने वाले एक साल के बाद हरियाणा की जनता की कोई समस्या नहीं रहेगी क्योंकि आने वाले एक साल में लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार ने फतेहाबाद में एक 220 के0 वी0 ऐ0 के पावर हाउस की नींव रखी है और मेरे अहरवां गांव में भी एक 132 के0 वी0 ऐ0 का पावर हाउस लगवाया है।

श्री अध्यक्ष : लीला कृष्ण जी आप जल्दी कंकल्यूड करें।

चौधरी लीला कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी मुझे समय नहीं दिया गया इसलिए बजट पर 3-4 मिनट बोलने के लिए ज्यादा दिए जायें। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत फतेहाबाद में 1.50 करोड़ रुपये का एक स्टेडियम बनाना मंजूर किया गया है जिसका उद्घाटन माननीय अजय चौटाला जी और अभय चौटाला जी ने किया। इस कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार पशु अस्पताल, स्कूलों में कमरे और हरिजनों की चौपालें आदि जैसे जन-कल्याणकारी कार्य कर रही है इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब है। इस बारे में मैं मेरे विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि सरकार बदलने से चोर-उचक्कों की मानसिकता नहीं बदलती कि वे कानून न तोड़ें। चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में भी डकैतियां और लूटपाट की घटनाएं होती थीं, चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय में भी डकैतियां और लूटपाट की घटनाएं होती थीं और अब भी हो रही हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है कि चोर और डकैत सरेआम जनता में घूमें। अब हमारी पुलिस बड़ी ही सूझबूझ के साथ कार्य कर रही है और उसका मेन ध्येय यही है कि वह चोर लूटेरों को पकड़े और पकड़े भी जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी डाले जा रहे हैं। यह भी सरकार की एक उपलब्धि है।

स्पीकर सर, सबसे बड़ी बात एस0 वाई0 एल0 की है जिस पर विपक्ष ने भी बड़ा जोर दिया है। पाकिस्तान की तरफ एस0 वाई0 एल0 का पानी बेकार जा रहा है इस मसले में भी हमारे मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने केन्द्र सरकार से बात की और इस मसले को सुलझा कर हरियाणा को पानी दिलाने की मांग की। इसी तरह बिजली की बात है। पंजाब में तीन परियोजनाएं चल रही थीं और गोबिन्द सागर वाली चौथी परियोजना भी पूरी हो चुकी है। इसमें से भी 50 फीसदी बिजली की मांग हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय चौटाला साहब ने जोरदार शब्दों में केन्द्र सरकार से की है। यह भी बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। विपक्ष के कई भाईयों ने एन0 ओ0 सी0 का जिक्र किया था कि किसानों को बिजली विभाग से बिल अदायगी का एन0 ओ0 सी0 लेना पड़ता है उसके बाद ही वे किसी बैंक से लोन या फिर अन्य सरकारी सुविधाएं पा सकता है। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने इस एन0 ओ0 सी0 की पाबंदी हटा दी। अब किसानों को कोई एन0 ओ0 सी0 नहीं लेना पड़ता है। विपक्ष के नेता यहां पर बहानेबाजी करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, बिजली के बिल मिनिमम कंजम्पशन में दो किलो वाट के आते थे और मुख्यमंत्री जी ने उसको संशोधित करके कम से कम 1 किलोवाट कर दिया जोकि दुरुस्त है। इसके लिये भी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले टयूबवैलों की हार्स पावर बढ़ाने के लिये 2000 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से चार्ज किये जाते थे। जब लोगों ने इस सम्बन्ध में शिकायतें कीं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी शिकायतों को सुन कर 2000 रुपये प्रति हार्स पावर के रेट को घटाकर 500 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया। इसके लिये मैं मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौटाला साहब की प्रशंसा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिजली की चोरी की बात आई। यह ठीक है कि बिजली की चोरी हो रही है लेकिन बिजली की चोरी गरीब आदमी नहीं करता है। बिजली की चोरी या तो टयूबवैलों पर होती है या फिर इण्डस्ट्रीज में होती है इसलिये अफसरों द्वारा जो रेड की जाती है वह गरीब आदमियों पर न करके इंडस्ट्रीज या फिर टयूबवैलों पर जाकर रेड करें। गरीब आदमियों पर इस तरह के जुर्माने न लगाये जाएं।

श्री अध्यक्ष : लीला कृष्ण जी, अब आप वाइंड अप करें।

चौधरी लीला कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सारे विपक्ष के सदस्यों से भी कहूंगा कि वे इस बजट को सर्वसम्मति से पास करें।

श्री चन्द्र भाटिया (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया है। इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बजट हरियाणा के वित्त मंत्री भाई सम्पत सिंह जी ने पेश किया है और पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें कोई भी कर नहीं लगाया गया। विपक्ष में बैठे कुछ साथी भी कह रहे थे कि इससे पिछला बजट जो आया था उसमें भी कोई कर नहीं लगाये गये थे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, हम सब लोग विधान सभा के अन्दर अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने और उनका समाधान कराने के लिये बैठे हैं। जनता भी इसी उम्मीद से चुनकर हमें भेजती है कि हम अपने क्षेत्रों की कमियों को विधान सभा में रखें। क्षेत्र के विकास में जो कमियां रह जाती हैं उन्हें हम यहां पर कह भी सकते हैं। इन कमियों का समाधान करवाने के लिये सरकार के सामने या मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस कर रहित बजट के लिये मैं सरकार को बधाई भी देता हूं। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी इस बजट की सराहना की है। इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी कई बातें भी सरकार के सामने रखीं और कुछ सुझाव भी सदन में रखे हैं। यह बात ठीक भी है क्योंकि यह सैशन इसीलिये होता है। चाहे विपक्ष के साथी हों या फिर हम हों, हम भी बैठे हैं और सरकार भी यहां बैठी है। हरेक को अपनी बात विधान सभा के अन्दर रखनी भी चाहिए और जो-जो सुझाव हों वे भी सदन में रखने चाहिएं कि फलां हलके में यह कमी है और इस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में चाहे जिस किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, इस सदन में जो भी सदस्य चुन कर आता है वह एक ही बात कहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो। जो भी सदस्य यहां पर चुन कर आता है वह अपने क्षेत्र की बात सदन के सामने और सदन के नेता के सामने रखता है। वह सदस्य अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान वहां के लोगों को कहता है कि वह उनके गांवों के विकास की बातें मुख्य मंत्री के सामने रख कर मनवाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले हमारे अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा लेकिन मैं अपने अपोजीशन के माननीय सदस्यों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हरियाणा में विकास के कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। चाहे कहीं पर सड़कें बनाने की बात हो, चाहे कहीं पर स्कूलों के कमरे बनाने की बात हो, चाहे कहीं पर किसी गांव की गलियां पक्की करने की बात हो और चाहे कहीं पर पीने के पानी की समस्या के समाधान की बात हो, सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के माननीय साथी यह भी कह रहे हैं कि प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं लेकिन उसके साथ ही अपना विरोध दर्ज करवा देते हैं। मैं अपोजीशन के माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहूंगा कि जो विकास के कार्य प्रदेश में हो रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए और उनके बारे में आपको अपने सुझाव देने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य अपने सुझाव देने की बजाय सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको बुरा बताना शुरु कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों गुजरात में भूकम्प आया था। उसमें वहां के लाखों परिवार उजड़ गए और हजारों लोगों की जानें गईं। वहां पर लाखों लोग घर से बेघर हो गए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने वहां पर लोगों की जो सहायता की है उसकी सारे देश में

[श्री चन्द्र भाटिया]

सराहना हो रही है। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला था उस समय भी मैंने कहा था कि हरियाणा सरकार ने गुजरात के भूकम्प पीड़ित लोगों की जो सहायता की है उसके लिए आप लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए और यदि उसके बारे में आपके पास कोई सुझाव हैं तो वह देने चाहिएं लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनकी तरफ से कोई सुझाव देने की बजाय ये कहने लग गए कि वहां पर बढ़िया काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह तो हर व्यक्ति का इन्सानी फर्ज बनता है कि ऐसे मौके पर लोगों की मदद की जाए।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। वह किसी की ब्याह शादी का मामला नहीं था जिसके लिए इनको न्यौता देते। वहां पर हजारों लोग मारे गए और भूकम्प के कारण जो लोग घर से बेघर हो गए थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी उनकी सहायता करने की बात थी। वहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा की तरफ से लोगों की जो सहायता की है उसकी सारे देश में सराहना हो रही है। सारे देश के लोग कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया। अध्यक्ष महोदय, यह बात सुन कर हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बौखला गए कि हरियाणा सरकार की पूरे देश में सराहना हो रही है। ये इस बात को सुन नहीं सकते। इसके बारे में भी इन्होंने टीकाटिप्पणी करनी शुरू कर दी। हम यह कहते हैं कि अगर कोई गलत बात है तो वह मुख्य मंत्री जी को बतानी चाहिए कि यह गलत काम है। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले हरियाणा प्रदेश में जो सरकारें रहीं चाहे वह कांग्रेस पार्टी की रही और चाहे वह हविपा की रही आज की सरकार द्वारा जो मदद गुजरात में की गई ऐसी मदद किसी भी पार्टी की सरकार ने कभी भी कहीं पर नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के समय में हाऊस टैक्स लगाया जाता था तो उसको भी ये याद कर लें। हरियाणा विकास पार्टी के समय में भी हाऊस टैक्स बढ़ाये। हम बंसी लाल जी से कहते थे कि इसको आप न बढ़ाओ, इसको ठीक कर लो लेकिन हमारी उस वक्त सुनी नहीं जाती थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि विपक्ष के भाईयों को जो आज की सरकार अच्छे काम कर रही है उनकी सराहना करनी चाहिए। जो काम इन लोगों ने कर रखे हैं उनके बारे में हरियाणा की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। जब हविपा की सरकार थी तो उस वक्त हमने कहा था कि चौधरी बंसी लाल जी, अब दुबारा इस तरफ बैठने का मौका आपका आने वाला नहीं है। मैं सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में हाऊस टैक्स लगाये जाने का जो एक्ट बना था वह कांग्रेस की सरकार के वक्त में बना था। मैं यह भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि फरीदाबाद से कांग्रेस का जो साथी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ता था वह उस कमेटी का चेयरमैन था। उसने अपनी कलम से वहां पर टैक्स लगाने के लिए कार्यवाही पूरी की थी। आज उन्हीं की बदौलत वहां पर हाऊस टैक्स की मारा-मारी है। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने के लिए पहले काफी समय दिया गया है। अब आप बैठ जायें। भाटिया साहब को अपनी बात कह लेने दें।

श्री मांगे राम गुप्ता : आप ने मुझे पहले जो समय दिया, उसके लिए हम आपका अहसान समझते हैं। आप हमें समय देंगे तो हम अपनी बात कह लेंगे वरना हम अपनी बात नहीं कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप फिर किसी मौके पर अपनी बात कह लेना।

श्री मांगे राम गुप्ता : यह तो आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा और न कोई गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप समय नहीं देंगे तो आपकी मर्ज़ी है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये प्वायंट आफ आर्डर पर अपनी बात कहना चाहते हैं। प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने का मैम्बर का अधिकार है। ये काफी सीनियर मैम्बर हैं। आप इनको अपनी बात प्वायंट आफ आर्डर पर कहने दें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अभी हमारे साथी भाटिया साहब, यहां पर हाऊस टैक्स बढाने की बात कर रहे थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी बैठिये, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी बात सुन तो लें। आप हमारे से इतने नाराज क्यों हो गये। (विघ्न) भाटिया साहब हाउस टैक्स की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार इनके खिलाफ चुनाव लड़ता था उसने वह हाउस टैक्स लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से गलती हुई है तो इसीलिए वह चुनाव हार गया। अब आप इस टैक्स को खत्म करवा सकते हो।

श्री चन्द्र भाटिया : हाऊस टैक्स जिस भाई ने फरीदाबाद की जनता पर लगाया था उसको जनता ने हरा दिया। कृष्ण पाल जी ने भी इस बारे में अपने विचार रखे थे। हम अपनी बात कह सकते हैं और सरकार को सुझाव दे सकते हैं। हाऊस टैक्स की मारा-मारी इन लोगों ने की थी। इस बारे में हम सुधार कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं और अच्छे कामों की हम सभी को सराहना करनी चाहिए। गुप्ता जी, हाऊस टैक्स की जो देन है यह आप लोगों की है। आपकी सरकार के समय में यह हाऊस टैक्स लगाया गया था। इस बारे में हमारा मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि इस हाउस टैक्स के फार्मूले को सुधारा जाये और इसको ठीक किया जाये। इन भाइयों का काम तो सिर्फ हरियाणा की जनता को गुमराह करने का रह गया है ताकि हरियाणा की जनता को गुमराह करके दुबारा से सत्ता में आ सकें। जैसा मैं कह रहा था कि बंसी लाल जी के समय में जब हम अपनी बात कहना चाहते थे तो हमें अपनी बात कहने नहीं दी जाती थी और न ही हमारी कोई बात मानी जाती थी। आज के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको हम अपनी बात कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और इनके सामने हम अपने सुझाव रख सकते हैं। एक बार इस पर विचार किया जाए और इस फार्मूले को ठीक किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं। मुख्य मंत्री जी इस बात को अनदेखा नहीं करेंगे। आप सब लोगों के जो सुझाव होंगे वे उस पर विचार कर लेंगे। जो लोग जनता से जुड़े हुए हैं वे इस बात को जानते हैं कि मुख्य मन्त्री जी कितने लोकप्रिय हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हरियाणा की जनता उनके नेतृत्व को मानती भी है। यही कारण है कि हरियाणा की जनता ने उनको एक बार फिर चुन कर भेजा है और इस सीट पर बिठाया है।

अध्यक्ष महोदय, वे लोग जो आज जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जब उनके अपने हाथ में कलम की ताकत थी उस समय तो उन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं

[श्री चन्द्र भाटिया]

आज जब जनता की मार लगी है तो समझ में आया है। आज वे बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं मैं कहना चाहूंगा कि जब इनकी अपनी सरकार थी उस समय अगर ये लोग चाहते तो पानी की समस्या का समाधान कर सकते थे, सड़कों की समस्या का समाधान कर सकते थे, बिजली की समस्या का समाधान कर सकते थे। अध्यक्ष महोदय, इस बात को मानना पड़ेगा कि हरियाणा के अन्दर जितना काम आज हुआ है और सड़कों की मुरम्मत का काम चल रहा है आज से पहले कभी इतना काम नहीं हुआ है। मुझे भी हरियाणा की जनता ने दूसरी बार चुन कर विधान सभा में भेजा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जितना विकास इस सरकार के समय में हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ है। आज तो मैं खुद विधायक हूं। मेरे से पहले फरीदाबाद से जो विधायक थे वे मन्त्री होते थे उनके पास पावर होती थी लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के अन्दर काम करने की मन्शा होनी चाहिए कि हम सुधार करना चाहते हैं और हमें काम करना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। कानून व्यवस्था के बारे में उस समय क्या स्थिति थी और आज की सरकार के समय में क्या स्थिति है इन दोनों के बीच में फर्क जरूर दिखाई देता है। मैं यह नहीं कहता कि कहीं कोई कमी नहीं हो सकती है कमी जरूर हो सकती है लेकिन अच्छे कामों की तो सराहना होनी चाहिए। आज कानून-व्यवस्था की बात की जाती है कभी वह समय भी था जब लोग अपने घरों से निकलते हुए भी डरते थे। कानून-व्यवस्था के नाम पर उस समय जो लूट मचाई जाती थी आज वह हालत कहीं नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो विपक्ष के साथियों के पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है उन्हें तो बोलने के लिए कोई न कोई मसाला चाहिए क्योंकि उन्होंने तो बिना मतलब के भी विरोध करना है। जब बजट में कोई नया कर लगाया जाता था तो उस समय बजट देखा जाता था और बड़ा शोर मचता था। अब जब बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है तब भी यह कहा गया कि बहुत कर लगाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अगर कोई कमी पेशी है तो उसके बारे हम भी कह रहे हैं। सरकार से भी हम कहते हैं और अगर कोई गलत बात हुई है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो सैशन बुलाया जाता है वह इसलिए बुलाया जाता है कि सभी लोग अपनी बात रखें। हो सकता है हमारा कोई सुझाव सरकार के काम आ जाए। अच्छी चीजें हमें बतानी चाहिएं। बिजली के रेट्स बढ़े हैं इनमें कुछ कमी की जाए। हाउस टैक्स का जो फार्मूला है उसको थोड़ा चैंज किया जाए इसी प्रकार से अगर कोई और अच्छा सुझाव हो तो बताना चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं उनकी सराहना ये लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पहली बार हुआ है कि हरियाणा के अन्दर 1100 नई बसें चलाई गई हैं।

श्री अध्यक्ष : भाटिया साहब, अब आप वाईंड अप करें क्योंकि फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने रिप्लाई भी देना है।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, हम जिस बात को कहते हैं उस बात को सुनने पर कई बार हमारे विपक्ष के साथियों को लगता है कि हम गलत कह रहे हैं लेकिन इस बात को विपक्ष के साथी भी मानते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाऊस टैक्स की बात

भी आई। आज इस सरकार ने पैंशन का बहुत बढ़िया काम किया है कि इसको 100 रुपये से बढ़ा कर 200 रुपये कर दिया है। आज तक किसी भी सरकार ने बुजुर्गों के बारे में इस प्रकार की कोई बात नहीं सोची। हरियाणा सरकार ने इस बात को सोचा और आज हरियाणा के अन्दर हर बुजुर्ग को सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। गरीब हरिजन कन्या के लिए 5100 रुपये सरकार की तरफ से दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाटिया साहब, मांगे राम जी गुप्ता तो कहते थे की पैंशन को तोड़ दो तो उस वक्त मैंने कहा था कि जो पैंशन तोड़ेगा उसकी सरकार टूट जाएगी। (विघ्न)

श्री चन्द्र भाटिया : मैंने एक बार पहले भी कहा था कि एक समय वह भी था कि मुख्य मन्त्री जी से मिलने का समय नहीं मिलता था और एक मुख्य मन्त्री आदरणीय औम प्रकाश चौटाला जी हैं उनसे किसी भी समय मिला जा सकता है और टेलीफोन पर या मिलकर विधायक अपनी बात कह सकते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला कर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि मुख्य मन्त्री हर विधान सभा के क्षेत्र के अन्दर जा कर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सामने बैठकर सुनते हैं। उसके बारे में भी कई साथियों ने कह दिया कि यह पैसा बी0 डी0 ओज0, ए0 डी0 सीज0 और डी0 सीज0 लगाते थे। हम यह कहते हैं कि यह पैसा ए0 डी0 सी0 या बी0 डी0 ओज0 लगाते थे लेकिन उसके अलावा भी मुख्य मन्त्री का हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जाना और रूबरू लोगों की समस्याओं का समाधान

13.00 बजे

करना बहुत ही अच्छी बात है। पहले जो मुख्यमंत्री होते थे उनसे तो मिलने में बहुत मुश्किल होती थी आज मुख्यमंत्री जी खुद लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के लोग जो अपनी बातें कहते हैं तो उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि वे भी कभी सरकार में थे उन्होंने भी पूरा राजपाट चलाया था तो उस वक्त उन्होंने लोगों के साथ क्या किया था। चौधरी बंसी लाल जी ने लोगों से वोट लेने के लिए शराब बंदी की बात करी थी। उसके बाद उसको खोल दिया अब शराबबंदी करने में और उसको दोबारा से खोलने में क्या राज था उसके बारे में तो सारी जनता जानती है। अध्यक्ष महोदय, उनकी सरकार के वक्त मैं और आनन्द शर्मा जी जो यहां पर विधायक बल्लभगढ़ से थे जब भी अपनी बात कहना चाहते थे तो हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता था।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। * * * * * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, हमने हमेशा ईमानदारी से अपनी बात को, अपनी समस्याओं को यहां पर रखा। लेकिन चौधरी बंसी लाल जी हमें बोलने का मौका ही नहीं देते थे और हमें बाहर निकालने की बात करते थे। हम उस वक्त कहते थे कि ये जो पुलिस में भर्ती हुई है वह ठीक नहीं हुई है लेकिन हमें सुना ही नहीं जाता था और हमें सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, यहां पर विपक्ष वालों ने कहा है कि प्रदेश का नाश हो जाएगा। मैं इस सदन में यह जरूर कहना चाहूंगा कि अभी हमारी सरकार आए हुए एक साल ही हुआ है और इस सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं अभी आप आने वाले चार सालों में देखें कि कितने अच्छे-अच्छे काम

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री चन्द्र भाटिया]

होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए थे वे पूरे कर दिये हैं बल्कि उससे ज्यादा काम कर दिए हैं। आज जहां पर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी बैठे हुए हैं तो मैं बंसी लाल जी से कहना चाहूंगा कि भगवान इनकी उम्र को लम्बी करे लेकिन यहां सदन में उस कुर्सी पर बैठने का समय अब इनका नहीं आएगा। यहां पर इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। आज इनको लगता है कि लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। लोगों के दु:ख दर्द की बात याद आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी तो उस वक्त हमारे फरीदाबाद में गरीबों के झौंपड़ों पर बुलडोजर चला दिया गया था। लोगों को वहां पर कुचल दिया गया था। वहां पर लोगों के अन्दर भय का वातावरण पैदा हो गया था। हमने बंसी लाल जी की सरकार में तीन साल तक जमकर संघर्ष किया है चाहे हमने उनको समर्थन दिया हुआ था लेकिन हम अपनी बात पूरे जोर शोर से करते थे। आज यहां पर ये बैठे हुए हैं तो इनको तकलीफ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया है और लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हरियाणा के सभी क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मेरे एक साथी ने पानीपत नगर निगम के चुनाव के बारे में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करूं। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को देखें। इसके अलावा मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि पहले भी सभी साथियों ने मिलकर उनसे एक रिक्वैस्ट की थी कि विधायकों के मकान का और कार का लोन बढ़ाया जाए। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम इस बात को कहेंगे तो हमारी यह बात प्रैस में आ जाएगी इसलिए आप ही उनसे इस बारे में कह देना। (विघ्न) मैंने उनसे कहा कि अगर सभी विधायक साथी चाहते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना कर लूंगा। इसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि एम0 एल0 ए0 की ग्रांट को भी चालू कर दें तो यह बहुत अच्छा होगा। जहां करोड़ों रुपया खर्च होता है अगर वहां थोड़ा और खर्च हो जाएगा तो इसमें कोई बात नहीं है। विधायक इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। इसी तरह से अगर मुख्यमंत्री जी हाउस टैक्स और बिजली की बढ़ी हुई दरों के बारे में भी विचार करके कोई फार्मूला निकालें तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों से साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री कृष्ण लाल (असन्ध-अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री प्रो0 सम्पत सिंह जी ने जो 2001-2002 का बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और बजट पर भी विपक्ष के साथियों ने सदन में चर्चा की विशेषकर बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया जिसकी वजह से सारे हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आन दी फलोर ऑफ दी हाउस आश्वासन दिया कि जब भी प्रदेश में किसानों को बिजली पानी की जरूरत होगी हम उनको बिजली देंगे। पहले भी हमारी सरकार ने किसानों को बिजली देने के लिए केन्द्र सरकार के पावर मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके अधिक बिजली ली है जिसके कारण अब की बार हरियाणा ने सैंट्रल पूल में 54 लाख टन खाद्यान्न दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में कुछ आंकड़े सदन को बताना चाहता हूं।

हरियाणा सरकार ने किसानों को अधिक बिजली देने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। हरियाणा राज्य कृषि प्रधान क्षेत्र है इसलिए हमारी सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह किसानों को अधिक से अधिक बिजली दे। अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में हमारी सरकार ने किसानों को 412 करोड़ रुपये की सबसिडी दी है। 2000-2001 में 613.8 करोड़ रुपये सबसिडी देने का प्रावधान है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की कि ऐसे किसान जो 15 एच0 पी0 से लेकर 20 एच0 पी0 तक की मोटरें चलाते हैं वे दस हजार रुपये जमा करवाकर अपना इंडीपैंडैंट ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। इसी तरह से हमारी सरकार का 13-8-2000 को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने का कीर्तिमान है। इसी प्रकार से अगस्त, 2000 में राज्य में प्रतिदिन औसतन 524 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति किसी एक महीने में की गयी है जो अब तक का रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय, पानीपत और फरीदाबाद के बिजली प्लांटस ने 1999-2000 के दौरान 3110 लाख यूनिट अधिक बिजली का उत्पादन किया है। हमारी सरकार ने फयूल कंजम्पशन के रूप में चालीस करोड़ रुपये का फायदा किया है। बंसी लाल जी की सरकार के समय 1997-98 में 960 और 1998-99 में 835 बिजली के कनैक्शन दिए गए जबकि हमारी सरकार ने 9111 कनैक्शंज दिए हैं। इसी तरह से सैल्फ फाइनांस स्कीम के तहत 7989 कनैक्शंज दिए हैं। जबकि भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी की सरकारों के वक्त यानी साढ़े आठ सालों में 75 हजार टयूबवैल्ज कनैक्शंज की टैस्ट रिपोर्ट पूरी थी और ये कनैक्शंज दिए जाने थे लेकिन इन्होंने एक भी कनैक्शन नहीं दिया। अधिक बिजली के उत्पादन में 1998-99 में 351 करोड़ 50 लाख यूनिट का उत्पादन हुआ और 1999 में 381 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। हमने 30 करोड़ यूनिट अधिक बिजली का उत्पादन किया है और ट्रांसफार्मर जलने की दर में 3 प्रतिशत की कमी आई है क्योंकि हमारी सरकार के समय में पूरी मात्रा में वोल्टेज दी जाती है। वर्ष 2000-2001 में प्रसारण प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। श्री बलबीर पाल शाह ने चर्चा करते हुए कहा कि बिजली के लिए आधारशिला चौधरी बंसी लाल ने रखी थी मैं बताना चाहता हूं कि बंसी लाल जी ने बिजली के सुधार की बजाय बिजली को कंडम बनाने का काम किया है-इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 110 मैगावाट का प्लांट जो 25 लाख यूनिट बिजली डेली बनाता था उसके लिए ए0 बी0 बी0 कंपनी के साथ सांठ-गांठ करके उसके हवाले कर दिया और केवल 8 मेगावाट यूनिट बिजली बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया और अब वह 2 साल से बंद है एक साल में 9 हजार लाख यूनिट बिजली बनती है। पी0 यू0 सी0 मौके पर गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए विजिलैंस इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या यह ठेका हरियाणा की जनता का 300 करोड़ रुपया बर्बाद करने के लिए दिया गया था। इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक मेगावाट बिजली तैयार करने के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बिजली के उत्पादन में एक परसैंट भी इन्ट्रैस्ट नहीं लिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 500 मैगावाट का गैस बेस्ड प्लांट हिसार, फरीदाबाद और यमुनानगर के लिए दिया है और मेरे हल्के में भी 60 मेगावाट का प्लांट बनाया जाएगा। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में बिजली का बहुत अधिक उत्पादन होगा।

अब मैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आंकड़े बताना चाहूंगा और एक मिनट का समय और लूंगा। आपने अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का समय दिया है और उसी समय में मैं अपनी

[श्री कृष्ण लाल]

बात कह दूंगा। "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में अब तक चौटाला साहब ने ग्राम विकास के 15905 काम घोषित किए जिनमें से 7918 काम पूरे किए जा चुके हैं 5013 पर काम चल रहा है 80 प्रतिशत से अधिक काम पूरे किए जा चुके हैं, 2399 पर काम जल्दी ही शुरु किया जाएगा और इन कार्यों पर अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जी ने जो कर रहित बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं व बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will give his reply. (विघ्न) धर्मवीर जी, आपका प्लान मैंने सुन लिया है अभी-अभी आप और चौधरी भजन लाल जी बैठकर जो रणनीति रच रहे थे वह मैंने सुन ली है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस सदन में इस प्रकार की कोई साजिशें भी होती हैं अभी अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा है कि ये अपनी सीट को छोड़कर दूसरे की सीट पर जाकर रणनीति बना रहे थे।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि * * * * * * * * (शोर)।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। चौधरी भजन लाल जी आप बैठिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के कुछ साथी बजट पर बोलने से रह गये हैं आप उनको बोलने का समय दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बोलने किस को नहीं दिया। ठीक है आप रिप्लाई शुरु करवाएं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आपने अपनी लिस्ट में श्री धर्मवीर सिंह जी का नाम नहीं दिया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने धर्मबीर सिंह जी का नाम 9 नम्बर पर दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप खुलकर बोलें।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठिये। अब वित्त मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, यह बात ठीक नहीं है कि आप हमें बोलने का समय नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर सिंह जी आप बैठिये। जो धर्मबीर सिंह जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी तो पोस्ट लंच सैशन बकाया है आप हमें बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि अब तक 24 सदस्य बजट पर बोले हैं जिनमें से विपक्ष के 14 और ट्रैजरी बैंचिज के 10 हैं और विपक्ष को 347 मिनट का टोटल समय दिया गया तथा ट्रैजरी बैंचिज को 226 मिनट का टोटल समय दिया गया।

राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने हमें बजट पर बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह अजीब तमाशा है हाउस को चला पाना मुश्किल हो रहा है। (विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है और ये बीच में बोलने वाले कौन होते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सदन को कंट्रोल कीजिये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी आप बैठ जायें। जो धर्मबीर सिंह जी ने कहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं विघ्न) जब समय बढ़ाएं तो आप लोग प्रोटैस्ट करते हैं, इसलिए अब आप लोग बैठ जाएं। आप ग्रांटस पर बोल लेना। अब सम्पत सिंह जी का जवाब आना है इसलिए अब किसी और मैम्बर की बात को नोट न किया जाए।

श्री धर्मबीर सिंह : * * * * *

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * * *

चौधरी भजन लाल : * * * * *

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के एक सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए।)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस ढंग से सदन चलाया जा रहा है, इसकी सारी बातें बढ़िया हैं। आज का बिजनैस सरकुलेट हो चुका है, भजन लाल जी और अन्य मैम्बर्ज के पास यह बिजनैस है। उसके हिसाब से जो-जो नाम आए हैं उनको बोलने दिया गया है। आज की फस्ट सिटिंग में रिप्लाई लिखा हुआ है और सैकिण्ड सिटिंग में डिमाण्डज़ आएंगी, उन पर जितना चाहे बोल लेना और जितना समय मर्जी बढ़वा लेना। डिमाण्डज पर आप लोग खुलकर बोल लेना। इसलिए अब मेरी बात सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और वित्तमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि विधायकों को पहले जो 50 लाख रुपये की ग्रांट अपने हल्कों में काम करने के लिए दी जाती थी वह दोबारा से शुरु की जाये और वह राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की जाये ताकि विधायक भी अपने हल्के में विकास कार्य करवा सकें। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 12-3-2001 को बजट एस्टिमेट्स सदन में रखे और उसके ऊपर बड़ी लम्बी चौड़ी बहस हुई तथा जितने सदस्य इस बार बजट एस्टिमेट्स पर बोले इतने सदस्य पहले कभी नहीं बोले, यह रिकार्ड की बात है। इतने ज्यादा मैंबर बजट पर बोले यह हमारा, सौभाग्य है और अच्छी बात है। बजट पर बोलते हुए बहुत से मैंबर्ज ने अच्छे सुझाव दिए और वे सुझाव हमने नोट भी किए हैं। कई सदस्यों ने बजट की सकारात्मक आलोचना की और कई मैंबरों ने केवल मात्र आलोचना के लिए ही आलोचना की लेकिन फिर भी मैं सभी मैंबरों का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जिस दौर से आज सारी दुनियां गुजर रही है और आज जिस तरह से सारी दुनियां के अंदर आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है उससे कोई भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती क्योंकि आज सारे काम गलोबल लैवल पर हो रहे हैं और लीबरलाईजेशन की पोलीसी अपनाई जा रही है। इसी तरह डब्ल्यू0 टी0 ओ0 के बारे में काफी बातें यहां आई। इन सब बातों को देखते हुए जब बजट एस्टिमेट्स पेश करने पड़ते हैं और वित्त मंत्री जब अपना बजट तैयार करता है तो उसको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्पीकर सर, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह बजट बनाया गया है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई माननीय सदस्यों ने इस बजट की यहां पर सराहना भी की है। स्पीकर सर बजट में पूरी कोशिश की गई है कि खर्च पर कंट्रोल किया जाये। जिस रेशो से खर्चे बढ़ते हैं उस हिसाब से रिसीट रेशो बढ़ना भी जरूरी है ताकि खर्चे पूरे किए जा सकें। इसी तरह से गैर-उत्पादक खर्चों को भी घटाने की कोशिश की गई है ताकि बजट का बैंलस बना रहे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक फाईनैंशियल मैनेजमैंट का सवाल है आप सभी जानते हैं कि जैसा फाईनैंशियल मैनेजमैंट हमारा अच्छा रहा है और खर्चों पर जो कंट्रोल रहा है उसे 11वें फाईनैंस कमीशन ने भी माना है। कल कई माननीय सदस्य फाईनैंस कमीशन की जगह प्लानिंग कमीशन का नाम लेकर और प्लानिंग कमीशन की जगह फाईनैंस कमीशन कहकर कन्फयूज़ कर रहे थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितना अच्छा फाईनैंशियल मैनेजमैंट हमने किया है, खर्चों पर कंट्रोल किया है उसकी हमें सजा भी मिली है क्योंकि 11वें फाईनैंस कमीशन ने अपने पहले वाले फाईनैंस कमीशन के मापदण्डों के मुकाबले अब अपने मापदण्डों में परिवर्तन कर दिया है कि जो बीमार स्टेट्स हैं उनके लिए अलग से ज्यादा पैसा का प्रावधान कर दिया। स्पीकर सर, जिन स्टेट्स का मैनेजमैंट अच्छा नहीं है, जिनका खर्चे पर कंट्रोल नहीं है और जो स्टेट्स आमदनी के साधन जुटा नहीं पा रहे हैं, जिनके यहां पर रिफोर्मज नहीं हो रहे हैं तथा जो आज की दुनियां के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं उन स्टेट्स को 11वें फाईनैंस कमीशन ने बढ़ावा दिया है और जैसे मैंने बताया कि हमारी जैसी स्टेट जो प्रगतिशील स्टेट हैं उनको 11वें फाईनैंस कमीशन ने नजरअंदाज किया है लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है कि बजटरी कंसट्रैंट्स होते हुए भी हमारी स्टेट के विकास में कोई कमी न आये और विकास की गति में कोई कमी नहीं आई। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। स्पीकर सर, हमें यह भी नुक्सान हुआ है कि पहले हमें जो सैन्ट्रल असिस्टैंस का फाइनैंस कमीशन के मार्फत शेयर मिलता था वह शेयर 1.238 प्रतिशत था जो कि अब 0.944 प्रतिशत रह गया है। स्पीकर सर, प्लान कट का भी जिक्र आया था। जहां तक प्लान कट का सवाल है। (विघ्न)

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठ जाइए। अब वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। समय नष्ट न करें। (विघ्न) सारी बातें आपके सामने आएंगी। आप ध्यान से सुनें। जो भी कादयान साहब बोले, वह रिकार्ड न किया जाए।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 150 करोड़ की राशि हमें कम मिली है। स्पीकर सर, विपक्ष के एक सदस्य कादयान जी कोई क्वांटिटी की बात कर रहे थे। स्पीकर सर, जैसा कि मैंने कहा कि हम नहीं चाहते कि जनता पर कोई बोझ पड़े इसलिये हम कर प्रणाली में सुधार करके सरलीकरण से साधनों को अडोप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा साधनों को जुटाया जा सके। आगे आने वाले साल में हमने ऐसे कदम उठाने की कोशिश की है ताकि बजट एक्सपैंडिचर पर कंट्रोल रह सके और बजट का प्रबन्धन भी ठीक रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चिन्ता महसूस की गई। स्पीकर सर, कहीं कहा गया कि नोन-प्लान

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

एक्सपैंडिचर बढ़ रहा है तो कहीं कहा गया कि बजट का घाटा बढ़ रहा है और बारोइंग बढ़ रही है। स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तीनों चीजों पर हमने कंट्रोल किया है जैसा कि मैंने पहले बताया है। बजट स्टेटमैन्ट के अन्दर भी घाटे को कम किया। पहले घाटा 97.99 करोड़ था जो कि पिछली बार यानि कि चालू वित्त वर्ष में घटा कर 68.35 करोड़ किया गया। इस हिसाब से हमने 29.44 करोड़ का घाटा अपने प्रयासों से कम किया। अब जो घाटा शुरु से चला आ रहा है वह कोई हमारा अकेले का तो नहीं था। हमें तो विरासत में यह घाटा मिला था वह अलग है। हमारे जो अपने प्रयास रहे हैं उन प्रयासों से तो हमने 29.44 करोड़ रुपये का घाटा कम किया।

स्पीकर सर, जहां तक ये कर लगाने की बात करते हैं जैसे कि एल0 ए0 डी0 टी0 की बात थी। यह एल0 ए0 डी0 टी0 किस पर लगता है वह आप भी जानते हैं और हाउस भी जानता है। जो सरकार की या प्रदेश की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और प्रदूषण भी फैलाते हैं। यह सब करने के बावजूद भी आउट ओफ सेल दिखाते हैं, केवल मात्र उनके ऊपर यह एल0 ए0 डी0 टी0 लगाया है और वह भी केवल एक से दो परसैंट है। यह भी मोटे-मोटे उद्योगों पर लगाया है, आम आदमी या साधारण ट्रेडर पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया है। स्पीकर सर, इससे इनको क्या तकलीफ है। इसके अलावा ये जो नगरपालिकाओं की या कोई दूसरी बात कर रहे थे तो स्पीकर सर, कमेटियां अपने साधन जुटाती हैं, पंचायतें भी अपने साधन जुटाती हैं और संविधान ने उनको पावर्ज दी हुई हैं। रिसोर्सिज़ जुटाने का काम भी उनके ऊपर छोड़ा गया है। हालांकि हमने अपनी तरफ से स्टेट का फाइनैंस कमीशन बनाया है और पहले कमीशन ने डायलूशन ओफ फण्ड्ज़ में उनको 32 करोड़ से भी ऊपर पैसा दिया है। अब फिर सैकेण्ड फाइनैंस कमीशन बनाया गया है वह भी स्टेट रिसोर्सिज़ से उनको ग्रान्ट देगा लेकिन कमेटियों का अपना काम भी रिसोर्सिज़ जुटाना है। इसलिये स्पीकर सर, हमारी तरफ से कोई टैक्स नहीं है। स्पीकर सर, स्थानीय निकायों को जहां एक तरफ पावर्ज दी गई हैं दूसरी तरफ उनके हाथों में यह अधिकार भी दिये गये हैं कि वे अपने रिसोर्सिज़ भी जुटायें जो कि वे जुटा रहे हैं। जहां तक स्टेट का सवाल है तो केवल मात्र एल0 ए0 डी0 टी0 को छोड़कर बाकी कोई भी टैक्स वगैरह आम आदमी पर नहीं लगा है और एल0 ए0 डी0 टी0 भी बड़े लोगों पर लगा है।

स्पीकर सर, जहां तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात की बात है तो पिछले साल 7.46 प्रतिशत था जो कि अब बढ़कर 8.38 प्रतिशत हो गया है जिससे आपको और इस सदन को खुशी होनी चाहिए। अब की बार के लिये भी यह सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 8.67 दर्शाया गया है। स्पीकर सर, जो कर प्राप्ति की बात है तो हमारे कर एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बतायेंगे कि हमारी स्टेट कितनी प्राग्रेस कर रही है और किस तरह से स्टेट का रवैन्यू बढ़ रहा है। इसके अलावा बजट घाटे को पूरा करने की जो बात है तो अभी केन्द्र सरकार से भी सहायता आनी है क्योंकि अभी तक प्लानिंग कमीशन के साथ मीटिंग नहीं हुई है जो कि आने वाली 22 मार्च के लिये फिक्स है। 22 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे मिलेंगे। उस वक्त अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्लानिंग कमीशन के मार्फत लेने की कोशिश करेंगे। स्पीकर सर, इसी तरह से सामान्य योजना सहायता, बाजारी ऋणों और केन्द्रीय करों में हिस्सा बढ़ोतरी यानि इन तीनों चीजों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर तो और भी बढ़ौतरी होगी। इसके बाद तो बजट घाटे को पूरा करने के

सम्बन्ध में कोई शंका नहीं रह जाती। स्पीकर सर, गैर योजना के जो खर्चे हैं उन पर भी हम और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक ऋणों का सवाल है। स्पीकर साहब, पिछली बार बोरोइंग के बारे में जो एस्टिमेट दिया था इस बार उस एस्टिमेट में कमी आई है। यह भी हमारी सरकार की उपलब्धि है और मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि आपका सहयोग ले करके हम बोरोइंग को कम करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर साहब, वैसे बोरोइंग्ज प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। यह बात हम सभी मानते हैं। लेकिन कर्जा चुकाना और उसका ब्याज चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर प्रदेश के विकास के लिए कर्जा लेकर उसके मूल ढांचे को विकसित करेंगे तो उसके साथ-साथ प्रदेश की प्रगति होगी, उसके साथ-साथ रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, उससे मैनुफैक्चरिंग यूनिट भी ज्यादा आएंगे, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा लगेंगी इस तरीके से आमदनी बढ़ेगी और उस आमदनी से हम कर्जे और ब्याज से छुटकारा पा सकते हैं। स्पीकर साहब, वह स्टेज भी आएगी और हम चाहते भी हैं कि वह स्टेज आए जिस टाईम बोरोइंग खत्म हो जाएगा और हम अपने पावों पर खड़े हो जाएंगे।

स्पीकर साहब, जिस समय बजट पर बहस चल रही थी उस दौरान में कम से कम 10 मैम्बर्ज को बीच में बार-बार टोका था, बार-बार कहा था कि आप प्रदेश के विकास के बारे में अपने सुझाव दें और ये भी सुझाव दें कि किस तरीके से रेवेन्यू रिसोर्सिज बढ़ाए जा सकते हैं। अगर इस बारे में किसी मैम्बर की तरफ से कोई सुझाव आता तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता और उन पर गौर करता। मेरे अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने बजट की आलोचना तो कर दी लेकिन किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया कि रैवेन्यू रिसोर्सिज कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। स्पीकर साहब, जहां तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है। उस बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने और खास करके मांगे राम गुप्ता जी ने आंकड़े दे कर अपनी बात कहने की कोशिश की और कहा कि इस बार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 54.6 परसैंट रखा है जबकि पिछली बार 64.5 परसैंट रखा था। स्पीकर साहब, जहां तक कम्पैरीजन की बात है तो 1997-98 में 48.8 परसैंट रखा था, 1998-99 में 52.10 परसैंट था। स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी ने तीन चार महकमों का जिक्र किया था। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो हाई-वे को अपग्रेड करने का वर्ल्ड बैंक का 429 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट था जोकि आर्थिक प्रतिबंध लगने की वजह से वह हमें नहीं मिल पाया यह आपको पता ही है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का डब्ल्यू० आर० सी० पी० का प्रोजैक्ट है जिसके लिए 370 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था और वह 31 दिसम्बर 2000 में समाप्त होना था लेकिन चौधरी भजन लाल जी वह प्रोजैक्ट आपकी सरकार के समय में 1994 में मंजूर हुआ था। इस प्रोजैक्ट के शुरु होने में ही दो साल लग गए थे।

स्पीकर साहब, यह तो हमारी उपलब्धि है वरना यह पैसा जाया जाता हमने इस पैसे को खर्च करने के लिए अवधि बढ़वाई है और वह अवधि 31 दिसम्बर 2001 तक बढ़ाई गई है और इस साल इस प्रोजैक्ट के लिए 210 करोड़ रुपये रखे गये हैं। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक बिजली के क्षेत्र में ए० पी० एल० टू की बात थी तो जो ए० पी० एल० वन था उसके बाद ही ए० पी० एल० टू का वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना था वह अभी नहीं मिला है क्योंकि जितने रिफार्म्ज वह चाहते हैं उस किस्म के रिफार्म्ज नहीं हुए हैं। हम मानते हैं कि हमने रिफार्म्ज करने के प्रयास किए हैं चाहे वह कम्पनियां बनाने की बात थी और चाहे वह कारपोरेशन बनाने की बात थी उनको बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से प्रयास किए लेकिन उनकी तरफ से यह बात कहना कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्राइवेट कम्पनी हो और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के

[प्रो0 सम्पत सिंह]

लिए प्राइवेट कम्पनी होने के बाद ए0 पी0 एल0 टू का लोन मिलेगा। इस पर जनमत की राय लेकर के, विपक्ष के साथियों को विश्वास में लेकर और दूसरे एक्सपर्टस की राय लेकर ही कोई कदम उठायेंगे। हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते। अगर यह सब चाहते हैं कि इन कम्पनियों का निजीकरण हो तो फिर यह ए0 पी0 एल0-दो इस्तेमाल हो जायेगा। अगर इनका निजीकरण नहीं चाहते तो फिर यह इस्तेमाल नहीं होगा। इस ए0 पी0 एल0 दो के इस्तेमाल न होने की वजह से यह जो इन्फ्रास्ट्रैक्चर का काम है यह अधूरा रहेगा।

यहां पर कर राशि लक्ष्य की प्राप्ति की बात की है। इस बारे में शंका जाहिर की कि यह कर प्राप्ति का जो टारगेट है इसको सरकार पूरा नहीं कर पायेगी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चालू वर्ष के अन्दर बजट राशि का लक्ष्य 4162.95 करोड़ रुपये रखा गया है और संशोधित अनुमान 4427.64 करोड़ रुपये रखा गया है यानि 264.79 करोड़ रुपये का लक्ष्य अधिक रखा गया है जो वर्ष 1999-2000 के मुकाबले में 25.5 प्रतिशत अधिक है। चालू वर्ष में 31 जनवरी तक 3545.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है यानि जो संशोधित लक्ष्य रखा गया था उसका 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है और अभी दो महीने फ़रवरी व मार्च बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि हमने 4427.64 करोड़ रुपये का जो लक्ष्य रखा हुआ है उसको बाकायदा पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से कर राशि का जो लक्ष्य 2001-2002 का है वह 5105.92 करोड़ रुपये का है जो चालू साल के मुकाबले में 15.3 प्रतिशत अधिक है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगला जो वित्त वर्ष आयेगा उसमें इसको पूरा करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने आबकारी डयूटी के लक्ष्य के बारे में भी शंकाएं जाहिर कीं। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि चालू वित्त वर्ष के अन्दर जो अब चल रहा है वह 840 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था। स्पीकर साहब, जनवरी तक 761.82 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है जो कि 90.7 प्रतिशत है। अभी दो महीने बकाया हैं यह टारगेट भी हमारा बढ़ेगा, घटेगा, नहीं। इसी तरह से मुख्य क्षेत्रों, जैसे कृषि, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई व समाज कल्याण विभागों के बारे में कहा गया कि इन के लिए कम पैसा रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी विभाग का संशोधित अनुमान देखेंगे तो पायेंगे कि पहले की अपेक्षा अधिक पैसे इन विभागों के लिए रखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप कृषि विभाग को देखें। इस विभाग में हमने 379.89 के बजाय 403 करोड़ रुपये रखे हैं। बिजली के लिए 1019.68 करोड़ की बजाये 1287 करोड़ रुपये रखे हैं। सिंचाई के लिए हमने 659.37 की बजाये 773 लाख रुपये रखे हैं। पी0 डब्ल्यू0 डी0 के लिए 316.59 की जगह पर 511.63 लाख रुपये रखे गए हैं। जल आपूर्ति के लिए 375.66 लाख की जगह पर 486.24 लाख रखे गए हैं इसी प्रकार से शिक्षा के लिए 1378.09 लाख की जगह पर 1485.89 लाख रुपये रखे हैं। स्वास्थ्य के लिए 342.07 लाख की जगह पर 371.88 लाख रुपये रखे हैं। समाज कल्याण विभाग के लिए 461.16 लाख की जगह पर 473.44 लाख रुपये रखे गये हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन विभागों के लिए यानि इन मदों में पहले से अधिक राशि रखी गई है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी लगातार 5 साल तक वित्त मंत्री रहे। इनकी मैं स्पीचें पढ़ता रहता हूं। मैं बजट का कोई मास्टर तो हूं नहीं। मैं तो एक लर्नर हूं। मैं तो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1992-93 से लेकर जब तक ये पांच साल तक वित्त मंत्री रहे और इन्होंने जो बजट स्पीच यहां पर पढ़ी वह मैंने सारी की सारी पढ़ी। मैंने इनकी स्पीच में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि ला एण्ड आर्डर के लिए पैसा रखने का कोई जिकर किया हो।

गुप्ता जी आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था के अन्दर जो पैसा खर्च होता है वह नॉन प्लान के अन्दर होता है। इसके लिए अलग से खर्च होता है इसलिए बजट में पुलिस का जिक्र नहीं आता। गुप्ता जी आप खुद समझदार हैं, स्याने हैं। इस बारे में यदि कोई दूसरा मैम्बर बात करता तो मैं मान लेता कि वह ठीक कह रहा है लेकिन आप जैसा व्यक्ति इस बारे में कहे कि कानून व्यवस्था के लिए कुछ पैसा नहीं रखा या उसका कोई जिकर नहीं किया थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी आप 5 मिनट में अपनी बात खत्म करें।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, यहां पर कई माननीय साथियों ने एस0 वाई0 एल0 के बारे में कई सवाल उठाये। इस बारे में मैं यहां पर केवल एक नोटिफिकेशन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें हरियाणा की तकदीर को किस तरह से खराब किया गया। यह नोटिफिकेशन 1981 की है। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा था . . . आज जो है 3.5 एम0 ए0 एफ0 पंजाब का पानी नहीं बढ़ेगा हरियाणा का पानी बढ़ेगा। अगर आप वह नोटिफिकेशन देखना चाहें तो वह 1976 की नोटिफिकेशन है जिसमें यह साफ लिखा है-- The State of Haryana will get 3.5 MAF and the State of Punjab will get the remaining quantity not exceeding 3.5 MAF. इसके बाद 3.5 से ऊपर पंजाब को नहीं मिलेगा और जो दिया गया है उससे चौधरी भजन लाल जी बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा राज्य का हुआ है वह आपके वक्त में ही हुआ है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने तो 3.83 करवा के दिया था और इसमें दिल्ली का अलग से है (विघ्न) पंजाब का पानी कैसे बढ़ेगा। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : पंजाब का कुछ बढ़ेगा। (विघ्न)

श्री भजन लाल : नहीं बढ़ेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठिये। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंह : 1976 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार पंजाब का पानी 3.5 एम0 ए0 एफ0 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय पांच मिनट और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन उस दिन चौधरी भजन लाल जी ने मेरी अदम मौजूदगी में कह दिया था कि मैंने भी इस स्टेट का भट्ठा

[चौधरी बंसी लाल]

बिठाया है। मैं इनको भट्ठा बिठाने की बात का जवाब देना चाहता हूं। (विघ्न) जो स्टेटमैंट चौधरी सम्पत सिंह जी ने पढ़ी वह तो पढ़ी ही पढ़ी इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, यह 1981 में चौधरी भजन लाल जी के समय में तीन चीफ मिनिस्टर के साथ प्रधान मन्त्री जी की मौजूदगी में एग्रीमैंट हुआ था। चौधरी भजन लाल, श्री शिव चरण माथुर और सरदार दरबारा सिंह ने उस पर हस्ताक्षर किये थे। 1976 के फैसले में था। The State of Haryana will get 3.5 MAF and from the remaining quantity, Punjab will get not more than 3.5 MAF. पंजाब के ऊपर एक सीलिंग लगाई गई थी उसके बाद जो समझौता हुआ उसमें पंजाब का शेयर 4.22 एम0 ए0 एफ0 इन्होंने एग्री कर लिया, हरियाणा का 3.5 एम0 ए0 एफ0 से 3.83 एम0 ए0 एफ0 तो हमने इराडी कमीशन से करवाया था। पानी बढ़ गया था और उसके बाद राजस्थान का पहले 8 एम0 ए0 एफ0 था वह 8.30 एम0 ए0 एफ0 हो गया, दिल्ली और जम्मू तथा कश्मीर का वही रहा जो पहले था। अध्यक्ष महोदय, 1981 में जो समझौता था उस बारे में इराडी कमीशन ने बड़े क्लीयर शब्दों में लिखा है कि 1981 का जो एग्रीमेंट हुआ इसमें जो 1976 का भारत सरकार का फैसला था वह भी इसमें मरज हो गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं वह भी पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, ठीक है, अब आप बैठें। आपको सैकण्ड सिटिंग में टाईम दे देंगे आप उस समय अपनी क्लैरिफिकेशन दे लेना।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो चीज इन्होंने कर दी है वह तो अब भुगतनी पड़ेगी। बार-बार ये लोग कहते हैं कि पंजाब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन्ज हैं, फलां के साथ बहुत अच्छे रिलेशन्ज हैं इसलिए आउट ऑफ कोर्ट आप फैसला कर लें। अध्यक्ष महोदय, आउट ऑफ कोर्ट फैसला करने का भी कई बार प्रयास किया गया है लेकिन चाहे किसी भी पार्टी का राज हो आज अगर इसमें हम राजनैतिक बात करें तो दूसरी बात है लेकिन यह स्पष्ट है कि पंजाब और हरियाणा का फैसला आउट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि सभी के अलग-अलग अपने-अपने इन्ट्रस्ट क्लैश करते हैं। ऐसा वक्त भी था जिनके राज में पत्ता तक नहीं हिलता था और कांग्रेस पार्टी के प्रधान मन्त्री थे और पंजाब के अन्दर भी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे और हरियाणा के अन्दर भी कांग्रेस के ही चीफ मिनिस्टर थे। तीनों जगह पर एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं। आज तो चाहे केन्द्र में मिली जुली सरकार है और दूसरी जगह चाहे समर्थन प्राप्त सरकार है और दूसरी तरफ चाहे अकेली पार्टी की सरकार है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे पंजाब में कांग्रेस बोले, चाहे पंजाब में अकाली दल बोले, चाहे कोई और बोले सारा पंजाब एक ही भाषा बोलेगा और हरेक आदमी यह बात कहेगा कि एक बून्द पानी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी की भी सरकार रही हो इस पर हर बार चर्चाएं चलती रही हैं। इसी बात को ध्यान में रख कर ही कि इस ईशू का राजनीतिकरण कर दिया गया है इस वजह से हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यही सोच कर आदरणीय चौधरी देवी लाल जी अप्रैल, 1979 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। स्पीकर सर, अगर यह केस चलता रहता और वापिस न लिया जाता तो आज उसका फैसला कभी का हो गया होता। आज हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल रहा होता। आज जो हालात हैं वे नहीं होते। स्पीकर सर, 1979 में चौधरी देवी लाल जी के वक्त यह केस किया गया था और 1982 में उसको विदड्रा किया गया था। अगर उसको विदड्रा नहीं

किया गया होता तो आज हमें पानी मिल रहा होता उसके बारे में फैसला हो गया होता। अब दोबारा से 1996 में केस डाला गया है। इसके बारे में हमारे द्वारा फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामला राजनीतिक होने की वजह से अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अभी 22 तारीख को कानूनी राय लेकर पूरे जोर शोर से इसके बारे में बात करी गई है। यहां पर बताया जा रहा था कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी भी वकील हैं तो ठीक है इस बारे में इनकी भी राय ले ली जाएगी। मैं सबसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने सही मायने में अपने हिस्से का पानी लेना है तो कोर्ट में इसका फैसला होने दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। * * * * * * * * * * ।

श्री अध्यक्ष : यह जो भजन लाल जी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मेरे साथियों ने यहां पर साऊथ हरियाणा में यमुना वाटर का भी जिकर किया है। स्पीकर सर, एन0 बी0 लिंक से यमुना में पानी डाला जाता है। आज बरसात नहीं हुई है उसकी वजह से भाखड़ा में पानी का लैवल कम हो गया है और यमुना में भी पानी खत्म होने को है। आज हरियाणा में यमुना का शेयर है उसका केवल हमें 350 क्यूसिक पानी मिल रहा है। आज भाखड़ा का पानी लिंक करके वह भाखड़ा से एन0 बी0 में डाला जा रहा है। वह आज 1.45 एकड़ फीट डाला जा रहा है। यह इसलिए डाला जा रहा है ताकि उस क्षेत्र को पीने के लिए पानी और किसानों को पानी मिले। यही कारण है कि आज सारे हरियाणा में रिकार्ड तोड़ फसल हो रही है। पिछली बार भी रिकार्ड तोड़ फसल हुई है। अब इन लोगों को चिन्ता हो रही है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम बिजली और पानी मुहैया करवाकर किसानों को देंगे और आने वाले समय में भी रिकार्ड तोड़ फसल होगी। (विघ्न) अब ये बिजली की बात करते हैं तो इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस बारे में रामपाल माजरा जी ने इनको बता दिया था कि कितने परसैन्ट इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए थे। इन्होंने कभी 45 प्रतिशत, कभी 25 प्रतिशत, फिर 25 प्रतिशत और फिर 25 प्रतिशत। चौधरी बंसी लाल जी ने 1-7-96 को 20 प्रतिशत बढ़ाए थे और 15-6-98 को 15 प्रतिशत रेट बढ़ाए थे। स्पीकर सर, अगर टोटल एवरेज इस बार की निकालें तो 11 प्रतिशत ही इन्क्रीज है। जहां तक ये टयूबवैल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में किस की सरकार है वहां पर कांग्रेस की सरकार है। जहां हमारे टयूबवैल्ज पर 100 फीट के पानी के 62 पैसे उसके बाद 50 पैसे, 43 पैसे और 35 पैसे हैं और इन लोगों की सरकार में महाराष्ट्र में 110 पैसे हैं जो कि आपके ऊपर वाले स्लैब भी नहीं है। मध्य प्रदेश में 100 पैसे हैं, कर्नाटक में 80 पैसे हैं और दिल्ली में 75 पैसे हैं। यहां पर मेरे साथी कृष्ण पाल जी भी कह रहे थे कि यू0 पी0 के अन्दर 70 पैसे हैं और वहां पर बी0 जे0 पी0 की सरकार है। ये रेट हरियाणा में किसी भी स्लैब पर नहीं हैं। हमने ऊपर से ऊपर 62 पैसे रखे हैं। अब ये यहां पर ऐसी बातें करते हैं। इसी तरीके से मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि ये विश्वास रखें कि प्रदेश इस बजट के आधार पर चहुमुखी विकास करेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। जो उन्होंने अपने, ग्रीवैंसिज रखे हैं या मांगे दी हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा। कृष्ण पाल जी भी यहां पर कह रहे थे कि यह सुझाव और वह सुझाव माने जाने चाहिएं। तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि सैन्टर के

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

15-15 वजीर यहां पर आए थे उनमें अडवाणी जी और प्रधानमंत्री जी भी थे। सुझाव माने जाते हैं और उन्होंने विशेषकर सरकार की और लीडरशिप की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। ये यहां पर कैसी बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, टाईम की कमी की वजह से मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने इनकी सारी बातें जो-जो इन्होंने यहां पर कही हैं उनको नोट किया हुआ है और उनको पूरा करेंगे और मैं स्टेट को आश्वासन देता हूं कि विकास की गति और तेज होगी। स्पीकर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 2.00 P.M., today the 14th, March, 2001.

13.55 hrs. (The Sabha then* Adjourned till 2.00 P.M. today 14th March, 2001).

33270—H.V.S.—H.G.P., Chd.